

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 मार्च, 2012

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 1 मार्च, 2012

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(3)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)3
अतारंकित प्र न एवं उत्तर	(3)26
विभिन्न मामले उठाना	(3)26

गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, सैक्टर-23, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनन्दन	(3)28
चेयर पर आक्षेप करना/निलम्बन प्रस्ताव को वापस लेना	(3)28
नियम 30 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(3)32
हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में पारदर्शिता संबंधी	(3)34
वक्तव्य- राजस्व मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3)39
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण बैठक का समय बढ़ाना	(3)84
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुरनरारम्भण	(3)85

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 1 मार्च, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप भार्मा) ने अध्यक्षता की।

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Now the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी को हासिल करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और जिनको हमने खो दिया है। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं—श्री दीन दयाल, गांव ढाणी भाभा अहरोद, जिला रेवाड़ी और सरदार इन्द्रजीत सिंह भाटिया। यह सदन इन महान स्वात्रता सेनानियों को भात्— तात् नमन करता है और इनके भाक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के मुख्यामंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के चचेरे भाई श्री राजबीर हुड्डा सुपुत्र श्री फतेह सिंह के 1 मार्च, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता है।

श्री राजबीर हुड्डा लोक निर्माण विभाग, हरियाणा से कार्यकारी अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे एक नेक, ईमानदार और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का सत्यनिश्ठा और लगन से पालन किया तथा सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज सेवा के कार्य में लग गए। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन मुख्य संसदीय सचिव कुमारी भारदा राठौर के छोटे भाई श्री समय सिंह राठौर के 27 फरवरी 2012 को हुए असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। वे एक समाज सेवी एवं विकास मील विचारधारा वाले नवयुवक थे। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर की तरफ से भाोक प्रस्ताव रखा गया है मैं भी अपने दल की तरफ से उसका समर्थन करता हूं। जो स्वतंत्रता सेनानी आज हमें छोड़कर चले गए हैं उनके नाम हैं – श्री दीन दयाल, गांव ढाणी भाोभा अहरोद, जिला रेवाडी और सरदार इन्द्रजीत सिंह भाटिया। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन स्वतंत्रता सेनानियों को भात भात नमन करता हूं और इनके भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से प्रदे 1 के मुख्यमंत्री के चचेरे भाई श्री राजबीर हुडडा और मुख्य सचिव कुमारी भारदा राठौर के छोटे भाई श्री समय सिंह राठौर के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सर्वेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं अपने दल की तरफ से दिवंगतों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दिवंगतों में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम हैं दीन दयाल, गांव ढाणी भाोभा अहरोद, जिला रेवाडी और सरदार इन्द्रजीत सिंह भाटिया। इन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही हमें आजादी मिली है। हमारे मुख्यमंत्री के चचेरे भाई श्री राजबीर हुडडा जो लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियन्ता रहे थे, के निधन पर मैं गहरा भाोक प्रकट करता हूं। हमारे सदन की सदस्या तथा मुख्य संसदीया सचिव कुमारी भारदा राठौर के छोटे भाई श्री समय सिंह राठौर के 27 फरवरी 2012 को हुए असामयिक निधन पर मैं गहरा भाोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सर्वेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by the Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the

House. I feel deeply grieved on the sad demise of Shri Rajbir Hooda S/o Shri Fateh Singh, cousin of Hon'ble chief Minister Shri Samay Singh Rathore, younger brother of Kumari Sharda Rathore, Chief Parliamentary Secretary and two freedom fighters of Haryana. Shri Rahbir Hooda retired as Executive Engineer P.W.D (B&R) Department. He possessed the qualities of an educated experienced and well behaved officer, who served the State with all sincerity and dedication. Shri Samay Singh Rathore lost his life at very young age. He was a great social worker. This is an irreparable loss to the bereaved family. The freedom fighters are always remembered by the society due to their selfless service to the society and deep love for the country and countrymen. I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this Stage, the House stood in silence as mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the question hour.

Students Appeared in SPAT

***919 Shri Bharat Bhushan Batra:** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state-

(a) the district wise number of students that appeared in the SPAT examination in the State together with the amount spent on conducting the said during the period between 2009 to 2011; and

(b) the number of outstanding sports persons/players to whom employment in the state was given in accordance with their qualification during the period between March, 2005 to 2011?

खेल एवम युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री श्री सुखबीर कटारिया: श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) ए.पी.ए.टी स्पोर्ट्स एण्ड फिजिकल एण्टिट्यूड टैस्ट पहली बार वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। राज्य में स्पैट 2010 तथा स्पैट 2011 में उपस्थित होने वाले विधार्थियों की जिलावार सख्या निम्नलिखित है:-

राज्य में स्पैट 2010 में उपस्थित होने वाले विधार्थियों की जिलावार सख्या

क्रमांक	जिला का नाम	खिलाडियो की सख्या
1.	अम्बाला	1752
2.	भिवानी	5000
3.	फरीदाबाद	2335
4.	फतेहबाद	1104
5.	गुडगाव	2445

6.	हिसार	3459
7.	झज्जर	716
8.	जीन्द	2217
9.	कैथल	1196
10	करनाल	1652
11.	कुरुक्षेत्र	1498
12.	मेवात	420
13.	नारनौल	1021
14.	पलवल	1504
15.	पंचकूला	1609
16.	पानीपत	1155
17.	रेवाडी	2545
18.	रोहतक	4000
19.	सिरसा	1248
20.	सोनीपत	3300

21.	यमुनानगर	1185
	कुल	41361

राज्य मे स्पैट 2010 मे उपस्थित होने वाले विधार्थियों की जिलावार सख्या

क्रमांक	जिला का नाम	खिलाडियो की सख्या
1.	अम्बाला	1318
2.	भिवानी	18505
3.	फरीदाबाद	522
4.	फतेहबाद	3087
5.	गुडगाव	1367
6.	हिसार	9541
7.	झज्जर	4013
8.	जीन्द	7188
9.	कैथल	2646
10	करनाल	3850
11.	कुरुक्षेत्र	1387

12.	मेवात	434
13.	नारनौल	7045
14.	पलवल	2747
15.	पंचकूला	966
16.	पानीपत	3671
17.	रेवाडी	3382
18.	रोहतक	6595
19.	सिरसा	3873
20.	सोनीपत	5934
21.	यमुनानगर	827
	कुल	88898

एस.एस.ए.टी. 2010 के आयोन पर कुल 2135643 रूपये की राशि खर्च की गई। एस.एस.ए.टी. 2011 के आयोन पर कुल 2363929 रूपये की राशि खर्च की गई।

(ख) राज्य मे मार्च, 2005 से 2011 तक 361 उत्कृष्ट खिलाडियो को रोजगार दिया गया।

श्री भारत भूशण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो अमाउट मंत्री ने अपने उतर में स्पेट के लिए मैं इन की है यह स्पेट का एग्जाम कडक्ट करने के लिए है या इसमें स्कालरशिप भी शामिल है ?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में 2135643 और वर्ष 2011 में 2363929 रुपये स्टेट के एग्जाम कडक्ट करने का खर्च किए गए हैं।

श्री भारत भूशण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि क्या खिलाड़ियों को जा स्कालरशिप दी जाती है वह अमाउट भी इसमें इन्वोल्व है यह अलग से है?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, स्कालरशिप के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये अगल से दिए गए हैं।

श्री भारत भूशण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्पोर्ट्स पालिसी के मुताबिक and according to qualifications, the sports persons players have been given the employment by the Govt ? मैं यह जानना चाहता हू कि ओलम्पिक, एशियाड और वर्ल्डकप में जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया उनके अलावा अर्जुन अवार्ड भी होते हैं। अर्जुन अवार्ड का अवार्ड तो है वह higher than Olympic players and

higher than all the awards of other sports categories है। इसलिए जो अर्जुन अवार्ड है क्या उनको भी अप्वायटमेंट की पालिसी ने इन्कलूड किया गया या नहीं किया गया ? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुखबीर कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी स्पोर्ट्स पालिसी के तहत जो भी खिलाड़ी एरियन, कामनवैल्थ आदि गेम्ज में पार्टिसिपेट करते हैं और ऐलक्ट्रा आ डिनरी खिलाड़ी होते हैं। उन्हीं को अर्जुन अवार्ड मिलता है। अभी तो अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों की कैटगरी को नहीं लिया गया है लेकिन इसको भी ऐड कर रहे हैं और पालिसी अभी बनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी क्या अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को अप्वायटमेंट देने के लिए सरकार ने कोई अलग से पालिसी नहीं बनाई ?

श्री सुखबीर कटारिया: सर अलग से इस तरफ की कोई पालिसी नहीं है।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल डायरेक्ट इस सवाल से संबंधित तो नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स से ही संबंधित है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्पोर्ट्स मंत्री जी से जानना चाहूँता हूँ कि सरकार ने बहुत सी जगहों पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाये हैं। हमारे ब्लॉक में भी एक स्टेडियम बना लेकिन

उसमे आज तक पानी का कनैव तन और कोच की व्यवस्था नही हुई है। वहा पर कब तक पानी और कोच की सुविधा मिल पायेगी ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप बताईये कि जो ओलम्पिक गेम्ज अब होने वाली है उनमे हरियाणा रीजन के कितने खिलाडी सलैक्ट हुए है ? उसके डिसिप्लिनज क्या क्या है और अभी तक किसनते स्पोर्ट पर्सन्स को इस पालिसी के तहत सरकार द्वारा नौकरी दी जा चुकी है ?

श्री सखबीर कटारिया: स्पीकर सर, जो ओलम्पिक गेम्ज अब होने वाली है उसमे हरियाणा प्रदे त मे विभिन्न गेम्ज मे 9 खिलाडी सलैक्ट हो चुके है जिनमे एथलैटिक्स मे कृष्णा पूनिया व ओमप्रका त राणा, बाक्सिंग मे जय भगवान, मनोज कुमार, विकास व कृष्ण, हाकी मे संदीप सिंह व सरदार सिंह, भूटिंग मे सजीव राजपूत व अनुराज सिंह।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister can you tell me how many players of different games have been given jobs so far by the Government?

श्री सखबीर कटारिया: स्पीकर सर, अब तक भिन्न भिन्न खेलो के 361 खिलाडियो को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा मै बताना चाहूंगा कि इस पालिसी के तहत वर्ष 1999-2005 तक सिर्फ 136 खिलाडियो को नौकरी दी गई थी।

श्री रणदीप सिंह सुरेजवाला: स्पीकर सर, वैसे तो दो बातें मंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से बता दी हैं फिर भी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया है हरियाणा सरकार ने एक Definite Employment Guarantee Scheme बनाई है। इस बारे में जैसा कि श्री भारत भुशण बतरा जी ने पूछा कि हमारे जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं क्या उनका भी कोई रोजगार देने का प्रावधान है। Their policy is very brief, I will just tell you three contours of the policy that will clarify the whole matter. सर अर्जुन अवार्डी हो या दूसरे अवार्डी हो, the medal winners of Olympics Games and Gold Medal Winners in Asian Games, both these categories are given guaranteed Class II Gazetted Officers appointment in Government Department of Board or Corporation. It is for the first time that and State in this country has done so.

Similarly, Silver and Bronze medal winners of Asian Games, Gold and Silver Medal Winners of Commonwealth games and Gold Medal Winners of World Championships or any cup that is organized by recognized Sports Federation they are given guaranteed appointments on a minimum of Class III posts. Participants of Olympics Games, Bronze Medal Winners of Commonwealth Games, Silver and Bronze Medals winners of world championships or any cups and Medals winners of Asian Championships organized by recognized Sports federation will be suitably accommodated as per their qualifications in Government Departments Boards and Corporations. These are recognition for achievements in Sports. They are conferred for achievements in Sports because a player excelled in a

particular sport because he or she gets a gold medal, silver or bronze medal in a particular championships or in a particular cup or in a particular participating game at National and International level. That why consequently Government of India recognizes you by conferment of an Arjuna Award. Arjuna Award is conferment of an honour. Consequently any body who is already here, all Arjuna Award will automatically be covered Sir A point was raised and the Minister answered.

Mr. Speaker: An Hon'ble Member also asked that there is no water connection or sewerage connection in a stadium of her constituency.

Shri. Randeep Singh Surjewala: I straightway answer that Government has already decided that coaches will be appointed in each stadium and process of selection has been completed in many districts and in many districts. It is under process. For purposes of expeditious appointment, we have appointed a committee headed by Deputy Commissioner of the District. My learned friend can check with the Deputy Commissioner and the Hon'ble Minister will also check and come back to her. As soon as appointments are completed in Karnal District, we will make sure that a coach and other ground staff will be appointed.

Mr. Speaker: Hon'ble Minister as you have been the Public Health Minister she wants water connection there.

Shri Randeep Singh Surjewala: Absolutely, Sir We are aware of that and requisite money is also sanctioned for provision of water connection along with appointment of ground staff. We are very conscious about it Sir, for the first time in

the State of Haryana 361 Sports persons were appointed Sir it is for the first time not only were these appointments made but 12 Deputy Superintendent of Police were appointed direct for excelling in Sports One Inspector was appointed 30 Sub Inspectore were appointed 318m Constables and many other were appointed. 37 more Players I can say today itself are being appointed now 5 as Deputy Superintendents of Police, 18 as Inspector and 14 as Sub Inspecors, the Hon'ble Chief Minister has already declared that.

Criteira for Repair of Raods by HSAMB

***934 Shri Ashok Kumar Arora:** Will teh Agriculture Minister be pleased to state the criteria fixed to repair the roads of Haryana State Agriculture Marketing Board?

Agriculture Minister Sardar Paramveer Singh: Sir HSAMB conducts two kinds of repair on its roads Annual repairs and Major reparis Annual repairs involve routine patch work and berms repair, They are undertaken whenever teh need arises on a regular basis. Repairs costing more then Rs. 44000 per Km. are classified as major repairs during the current year. Where major reprirs are required these works are carried out on a case to case basis dependign on the condition of the road.

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि मार्केटिंग बोर्ड की गांव से गांव को और गांव को मडियो से जोडने के लिए जो सडके बनाई जाती है उन पर पिछले कई सालो से आवागमन बढा है जिसके कारण वे सडके जल्दी टूट जाती है तो क्या मंत्री जी बतायेगे कि

मार्केटिंग बोर्ड का निर्धारित मापदंड पी0डबल्यू0डी , (बी एण्ड आर)के मापदंड के बराबर करेगे ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन सडको की रिपेयर कब तक दी जायेगी ?

Sardar Paramveer Singh: Sir we have improved the norms. Earlier this ordinary repair was upto just Rs. 16000 per kilometre. We have revised it to Rs. 44000 per Kilometers. This is for ordinary repair this is for minor repair. It is not for major repairs. For major repairs we have improved the crust thickness and it is on the same pattern that PWD (B&R) is having now.

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया। मेरा सवाल यह है कि मार्केटिंग बोर्ड के जो मापदंड है वह पी0डबल्यू0डी , (बी एण्ड आर) से काफी कम है जिसके कारण वे सडके टूट जाती है मंत्री जी कह रहे है कि 44 हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से सिम्पल रिपेयर की जाती है क्या मंत्री जी बताएगे कि मेजर रिपेयर के लिए कितना खर्च करेगे ?

Mr. Speaker: Let the Hon'ble Minister answer the question.

सरदार परमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, सडको की हालत चाहे कितनी भी खराब हो मेजर रिपेयर मे क्वालिटी के साथ कोई समझोता नहीं होगा (गोर एवम व्यवधान) There is no limit.

श्री अ गोक कुमर अरोडा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेगे कि मेजर रिपेयर के लिए कितना रूपया प्रति किलोमीटर खर्च किया जायेगा?

Sardar Paramveer Singh: There is no limit I am saying it will be on the PWD Pattern. इन सडको की रिपेयर के लिए जितना भी पैसा लगेगा हम उसका प्रावधान करेगे।

श्री अ गोक कुमर अरोडा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेगे कि ये सडके कब तक रिपेयर हो जायेगी ?

सरदार परमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सडके है मै उन सबके बारे मे बता दूंगा। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अ गोक कुमर अरोडा: अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट का इ यू है केवल मेरे हल्के का नही हैं। मार्केटिंग बोर्ड का सडको की रिपेयर का मांपदड पी0डबल्यू0डी , (बी एण्ड आर) से कम है जिसके कारण ये सडके जल्दी टूट जाती है क्या मंत्री जी बताएगे कि ये उस क्राइटेरिया को पी0डबल्यू0डी , (बी एण्ड आर) के पैटर्न पर करेगे या नही ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी कह तो रहे है कि उन सडको को पी0डबल्यू0डी , (बी एण्ड आर) को ट्रांसफर कर रहे हैं। (गोर एवम व्यवधान) बहुत सी रोडज ट्रासफर की है।

श्री अ लोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, उसकी लिस्ट तो हमारे पास आ गई है सवाल यह है कि क्या वे पैटर्न बराबर करेगे या नहीं ?

श्री रणदीप सिंह सुरेजवाला: अध्यक्ष महोदय, यह मामला बी०एड०आर० से जुडा हुआ है इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Let the Hon'ble Minister speak.

सरदार परवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि हम पी०डबल्यू०डी , (बी एण्ड आर) के पैटर्न पर मार्केटिंग बोर्ड की सडको के नार्म फिक्स करेगे या नहीं ? मेरज रिपेयर मे हम पी०डबल्यू०डी , (बी एण्ड आर) के नार्मज अपनायेगे और क्यालिटी मे कोई कमी नहीं आने दी जायेगी लेकिन हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि कितने रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से नार्म फिक्स होंगे। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अ लोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, क्या ये पी०डबल्यू०डी , (बी एण्ड आर) के नार्मज फिक्स करेगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने बता दिया कि पी०डबल्यू०डी , (बी एण्ड आर) के बराबर नार्म फिक्स करेगे, बात खत्म हुई।

श्री जगदी ा नथ्यर: मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हू पिछले सदन की बैठक मे यह सूची जारी की थी कि

आपकी ये सडके गुड कडी ान मे है और ये सडके रिपेयर हो चुकी है। उस अरसे से जब तक सदन की बैठक नहीं हुई तब तक मैं एक एक सडक पर गया हूं और सारी सडके टूटी पडी है। यह झूठी रिपोर्ट आई है और पिछले 7 साल से ये झूठे आकडे पे ा किये जा रहे है अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष: मैं इसका कोई तरीका निकाल रहा हू।

श्री जगदी ा नथ्यर: मेरे हल्के की एक भी सडक रिपेयर नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय जी सात साल से झूठे आकडे पे ा किए जा रहे है। मेरे हल्के की एक भी सडक रिपेयर नहीं हुई। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये (गोर एवम व्यवधान)

श्री जगदी ा नथ्यर: अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के की कुछ सडके बिडकी से बिघोली मन्दिर, सपोरा से मरोली, बिडौग से औरगाबाद और पिगोल से नगरौला ऐसी कई सडके है जो सात साल से रिपेयर नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये (गोर एवम व्यवधान) अजय चौटाला जी पहले आप बोलिये उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

डा० अजय सिंह चौटाला: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने ही एक ये पत्र भिजवाया है जिसमें सभी विधायकों को सूचित किया है।

श्री अध्यक्ष: आपको भी मिला है।

डा० अजय सिंह चौटाला: हा जीए मुझे भी मिला है। जिसमें मेरे इलाके की साठ रोडज का जिक्र किया गया है। परन्तु सर, वहां पर आज हालत यह है कि सडक नाम की कोई चीज नहीं है बल्कि गडडो में से सडक ढूढनी पडती है। कि सडक है या नहीं ? इसके लिए तो माननीय मंत्री जी को विभाग ने गुमराह किया है या फिर माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। जरा बताएं कब तक इस स्थिति को ठीक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी आप बैठिए। हाऊस में अगर कोई स्टैंटमेंट माननीय मंत्री जी ने दी है और वह फ़ैक्चुवली गलत है जैसा कि मुझे बताया गया तो आप इस बारे में मुझे लिख कर भेजे। मेरी व्यवस्था यह है कि उसके लिए मंत्री जी की ऐक्सप्लेनेशन काल करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अरोडा साहब तो मंत्री भी रहे और वे अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं बड़े तजुर्बेकार पार्लियामेटरियन भी हैं, हम इनका रिगार्ड करते हैं इनकी जानकारी में होगा अगर नहीं भोगा तो मैं आपकी अनुमति से सदन को और इनको बताना

चाहूंगा। Speaker Sir, based on excel loan and trafice density, thickbess of the crust and thickness of the base is decided. National Highwasys has separate yardsticks and norms. Other distirct roads in the State have separate yardsticks and norms. State Highways of PWD (B&R) Department have separate yardsticks and norms. Village roads of Marketing Boards have totally separate yardsticks and norms. So, nobody can say that village roads should have thickness of a National Highway. That way precious national resources will be wasted (Interruptions) So, National Highwas will have its norms and PWD will have its norms. (Interruptions)

Mr. Speaker: Hon'ble Minister the member has pointed out that the roads which were developed to faciliated the agriculture uses are being used by the dumper owners and they are breaking these roads and these roads cannot survive in the given circumstances. So what should we do about it? Why do you allow these dumpers on these roads so that they get broken in these days ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir the point is well taken and we have noted it. The fact remains that Indian Road congress has laid down certain norms. For Marketing Board also, as the concern is expressed by my learned friend, we have now decided that the crust thickness will be increased from 225 mm to 400 mm in furure. We have decided that even for Marketing Board Roads.

***1044 Shri Jai Tirath:** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an International Horticulture Marketing Terminal in Sonapat district: if so, the total amount likely to be incurred on the project; and

(b) the time by which the aforesaid Terminal is likely to be completed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh):

Yes Sir, There is a proposal and we are setting up an International Horticulture Marketing Terminal at Gannaur and the likely expenditure on the project is estimated at Rs. 1264.67 crores and the Market is expected to start operations by end of the year 2012. All the Planned activities are, however, expected to be completed by 2015.

श्री आनन्द सिंह दागी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ सभी अंग्रेजी भाषा समझने वाले सदस्य नहीं बैठे हैं। जब भी कोई इस तरह का प्रश्न आता है और उसका उत्तर इंग्लिश में दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न करने वाले मੈबर को ही नहीं पता होता कि उसके प्रश्न का उत्तर जो इंग्लिश में दिया गया है उसका क्या मतलब है। अतः अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज इस तरह की व्यवस्था करने की कृपा करें कि जो प्रश्न है उसका उत्तर हिन्दी में भी माननीय सदस्यों को मिल सके ताकि वे लोग जो अंग्रेजी भाषा से वाकिफ नहीं हैं वे भी आपने प्रश्न के उत्तर से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें।

श्री अध्यक्ष: दांगी जी, सदन में हर सवाल का जवाब हिन्दी भाषा में टेबल पर रखा होता है।

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य का प्रश्न हिंदी में होता है जो अंग्रेजी भाषा में नावाकिफ है अगर उसके प्रश्न का अंग्रेजी भाषा में जवाब दिया गया तो उस माननीय सदस्य के लिए उस जवाब का क्या महत्व रह जायेगा।

Mr. Speaker: Try to make the Minister comfortable with language of Hindi also.

Construction of Road

***944Shri Rajbir Singh Brara:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the main road which leads from Sadhaura road to Barar Village in Barara town of Mullana Constituency is likely to be constructed ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) Sir, this road, which already exists, is likely to be repaired by 31-5-2012.

श्री राजबीर सिंह बरारा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने जानना चाहूंगा कि जैसा कि प्रश्न के जवाब में लिखकर आया हुआ है कि जो सड़क सढौरा से बराडा गांव को जाती है वह सड़क 31.5.2012 तक पूरी हो जायेगी। यह सड़क पिछले दो साल से बंद पडी है। यह सड़क तीन गांवों की

सडको को जोडती है। क्या इसका कोई टैंडर हुआ है अगर हुआ है तो कब तक इसके बनने की सभावना है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त की चिंता वाजिब है इसका टैंडर हो चुका है और क्योंकि हरियाणा में जो स्कोन क्वैरिज है उन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंध लगा हुआ है और माइनिंग पूरी तरह से बंद है इस कारण इसमें देर हुई। यह सडक हरिजन बस्ती के बीच में से जाती है इस पर पानी खड़ा होता है और जो नार्मल क्रस्ट है यदि उस पर पानी खड़ा होगा तो वह फिर सिपेज कर जायेगा। मैंने विभाग को यह भी कहा है कि जहा जहा पानी की स्टैगनेशन है यानि बस्ती के अंदर वहा सी0सी0 ब्लॉकस लगा दिये जाये चाहे कोस्ट थोड़ी बहुत इक्रीज हो जाये। मुझे उम्मीद है कि मई के आखिर तक यह सडक बना देगे।

श्री राजपाल भूखडी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने पूछना चाहता हू कि जागाधरी से जो सरावां रोड आती है उसकी मंत्री जी ने मजूरी दे दी है उसका आधा भाग मंत्री जी ने मजूर कर दिया है और आधे भाग के लिये मैं पूछना चाहता हू कि उसको बनाने का क्या प्रावधान है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपके अनुरोध पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उस मजूर किया है और बाकी के लिए ये लिखकर दे गये है हम उसे प्रोसेस कर रहे है।

श्री भोर सिंह बड गामी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन सड़कों के बारे में मंत्री महोदय सदन में तीन-तीन बार आवासीय दे चुके हैं और समयबद्ध आवासीय है कि इतनी तारीख तक ये सड़कें तैयार हो जाएंगी लेकिन उसके बावजूद भी इन सड़कों पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है इन सड़कों पर कब तक काम पूरा किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: इस पर मैं एक और आवासीय देने का काम करूंगा कि जैसे ही स्थान क्वैरीज खुल जाएगी इन पर काम शुरू कर दूंगा।

श्री अशोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय यह क्वैरीज कब तक खुल जाएगी ?

श्री अध्यक्ष: यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री भोर सिंह बड गामी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि क्वैरीज बंद थी, तो मैं जानना चाहूंगा कि जितना पैसा इस काम के लिए अलोकित हुआ था वह पैसा तो खर्च नहीं हुआ होगा, मैं जानना चाहूंगा कि कितनी राशि बची है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। दो सदस्य

एक साथ बोल रहे है कैसे समझ मे आयेगा, मेरे ही समझ मे नही आया कि क्या कह रहे (गोर एवम व्यवधान)

**Sewerage Treatment Plants and Canal Bases
Water Supply**

***1029 Shri Jagbir singh Malik:** Will the public Health Engineerign Minister be pleased to state—

(a) tht total number of sewerage Treatment Plants and Canacl Based Water Supply schmes lauched by the Government in Gannaur, Kharkhoda and Gohana townships togetherwith the total amount to be incurred on the aforesaid project ; and

(b) whether any delay has occurred in completion of thes projects; if so, whether any responsibility of teh officers/officials for causing delay in this regard has been fixed or not?

जनस्वास्थ्य अभियात्रिक मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहती हू इन्होने थोडा सा डिटेल मै क्वै चन पूछा है इसलिए मुझे डिटेल मे ही जवाब देना पडेगा। गन्नौर टाऊन का जो कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स है उसकी कैपीसिटी 9 एम0एल0डी0 है। और इसकी ऐस्टीमेटिड कास्ट 27.73 करोड है और अप टू डेट ऐक्सपैडीचर 27.70 करोड हम कर चुके है सिर्फ 3 लाख बाकी रहता है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट है उसकी कैपीसिटी 7 MLD and estimated coast is

Rs. 15-8 and upto date expenditure has already has been incurred to the tune of Rs. 15 crores and the rest is in process. We are also carrying out the work forward. Similarly, about Kharkhoda Canal Bases Water Works its Capecity is 4.50 MLD and estimate cost is Rs. 13.91 and expenditure incurred upto date is Rs. 13.88 and the capacity of Sewage Treatment Plant of Kharkhoda Town is 4.5 MLD and cost of project is Rs. 6.50 and expenditure incurred ये कार्य पूरा हो चुका है up to date is Rs. 6.50 crores. The capacity of Gohana Town Canal Based Warer Works is 14 MLD and its estimateed project cost is Rs. 42.35 crores and expenditue incurred upto date is Rs. 23.83 crores and the rest is in teh process. The capacity of Sewage Treatment Plant is 8.30 MLD and the estimated project cost is Rs. 16 crores and teh expenditure incurred upto date is Rs. 11.30 crores और यह 11.30 करोड खर्च हो चके है and the rest is in the process.

Mr. Speaker: There is a second part also of this question

Smt. Kinan Chaudhary: Sir, Hon'ble MLA has also asked whether there was any delay which has occurred for these projects. Unfortunately, the answer is Yes. There has been some delasy but these delays have not been due to any kind of laxitry on the part of the Department यह डिले वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम गन्नौर, खरखौद, और वाटर सप्लाई स्कीम, गोहाना मे इसलिए हुई है due to delay in acquistion of

land, release of Electricity and raw water outel connectiosn, कई जगह पर जैसे गन्नौर मे परमी न लेनी पडती है रेलवेज से and addressing of inter department clearances of Mining, Forest and PW (B&R) Departments. But the work is in process and will be completed very fast.

Mr. Speaker: Can we also fix a target?

Smt. Kiran Chauhary: if you want, I can tell you.

Mr. Speaker: You read that much piece of note, but can orally tell me as this pertains Gannaru also.

Smt. Kiran Chauhary: Sir, I would like to inform you that an added cost on we have put in more money i.e 1156 lacs have already been approved on 19-12-2011 under State Planning of Outlaying Distribution Water in the Town and work is in process and this will be completed by the 30th June of 2012. Similarly sewage in all three areas will be completed by the 30th June, 2012. Similarly the position of sewerage in all the three areas are also same about which he has asked. I have all the details if you wish and I can give it to you, sir.

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे यह बताया है कि ये प्रोजैक्टस डिले हुए है लेकिन इनके विभाग के आफिर् एल की इस काम मे कोई कमी नहीं रखी। क्या ये बताएगी कि इस प्रोजैक्टस के लिए इनके विभाग ने किस विभाग को कब एप्लाई किया, कब इनको इस काम के लिए उस विभाग से क्लीयरेंस मिली ओर क्लीयरेंस को मिलने मे कितनी डिले हुई ? दूसरे ये सारे प्रोजैक्टस कब पूरे होंगे, जो

इनके पूरे होने के भाडयूल में कितनी डिले हुई है और जो डिले हुई है। उससे इनकी कास्टस में कितनी इन्क्रीज हुई है ?

श्रीमती किरण चौधरी: स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि गन्नौर में कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई को बनाने के लिए उसके लिए एस्टिमेट और डिजाईन रेलवे विभाग ने अप्रूव किया है लेकिन रेलवे की परमिशन 25.1.2012 तक भी नहीं आई है आज जानते हैं कि इस प्रोजैक्ट के लिए कितनी प्रॉब्लम है because we are still awaiting the permission. As far as the sewerage is concerned, the position is also same i.e. the estimates and designs have been approved from the Railways on 25-1-2012 and payment has already been made but the permission is yet awaited so, the entire thing is according to circumstances which are beyond our control, So the entire thing is according to circumstances which are beyond our control, इसी तरह से खरखोद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सैंगन के लिए रा. वाटर आऊटलैट जी०डबल्यू०एस० चैनल के लिए चीफ इंजीनियरिंग इंरीगेन ने दिल्ली के इ०आई०सी० इंरीगेन विभाग को लिखा है जिसकी सैंगन 3.11.2011 तक अवेटिड है। ये सारे के सारे प्रोजैक्ट्स if all these sanctions come on time they are likely to be completed by 30-6-2011. As far as Kharkhoda is concerned उसमें एक प्रॉब्लम और भी बहुत जबरदस्त आई है कि तीन में होल्ज है जो मटिण्डा रोड पर है जिस पर काम हैल्डअप हो गया था क्योंकि इस में जमीन के मसले के बारे में कोर्ट से स्टे हो गया था जब कोर्ट से स्टे वेकेट होगा

तभी हम काम को आगे कर सकते हैं इसलिए वहा पर यह सारा का सारा प्रोजैक्ट डिले हो गया है But even then we are now in the process of getting it throught and i believe that the project is likely to be completed again by December 2012. जहा तक गोहाना की बात है वहा पर तीन प्रोजैक्टस है वे सारे के सारे सैग इन हो चुके है और इन सबको हमने 3.11.2009 को बनाना भुरु कर दिया था। तीन बुस्टिंग स्टे इन बनाने के लिए जो कान्ट्रैक्टर बीच मे काम छोडा गया था। उसके खिलाफ क्लाज II के तहत कार्यवाही भुरु हो चुकी है। I would also like the Hon'ble Member to know that as far as the water supply project in Gohana is concerned this is going to be completed by 30-9-2012 और निर्धारित समय के अन्दर हम उसको पूरे कर रहे है और गोहाना मे सीवरेज बनाने का कार्य 30.6.2012 तक समय सीमा मे ही पूरी कर देगे।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister why do not you depute an officer specially to pursure these permissions? Why should we wait for them?

Smt. Kiran Chaudhary: Mr. Speaker Sir, your point is taken. The department is very actively pursuing the whole thing but you know Sir, certain problems come in during the course of acqiosotion of land. Then there are court cases or any other exigenices or other things where the permissions have to be granted. For example like the Railwasy. I mean thes are the places where they go upon their own time. The department has been persisently and consistently pursuign the whole thing and i would like to tell the Hon'ble MLA that is

is for the first time after the Congress has come to power that जहा पर गन्नौर मे एस0टी0पी0 नही थी वहा पर इतने करोडो रूपयो की पहली बार ए0टी0पी0 दी जा रही है। इसी तरह से खरखौदा मे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्टस नही था। अब वहा पर साढे छ करोड रूपये की लागत से वहा पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट बनाने जा रहे है। गोहाना मे जो पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट था उसकी कैपसिटी को बढाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो खर्चा इनके विधानसभा क्षेत्र मे अब तक हमने खर्च किये है वह जुलाई 1999 से फरवरी, 2005 तक 269.1 लाख रूपये था और वर्ष 2005 से लेकर अब तक 55.44 करोड रूपये है जो कि 25 गुना ज्यादा है सरकार इतना पैसा दे रही है ताकि लोगो की जितनी भी समस्याए है उसका समाधान किया जाए। Speaker sir, in this current State Plan, now we have put another 300 lac, which was approved on 4-5-2011 for laying balance pipeling and the work in progress. It will be completed by December 2012 . Speaker Sir, Similary I would like to put on record for the satisfaction of the Hon'ble Members that as far as Kherkhoda is concerned, अध्यक्ष महोदय मै टाइम पास नही कर रही हूं बल्कि मै यह बता रही हूं कि कितना पैसा पहले लगा था और कितना पैसा हम लगा रहे है और इसके लिए Hon'ble Members should be grateful and thanful. यह पैसे हम इनके लिए या उनके लिए नही लगा रहे बल्कि हम सबके लिए काम करना चाहते है। जहा जहा कमी है हम

वहा वहा कही 25 गुना ज्यादा और कही 16 गुना ज्यादा पैसा दे रहे है ।

HUDA SECTOR AT BARWALA

***1096. Shri Ram Niwas Ghorela:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a HUDA Sector in Barwala City ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No Sir.

Extension of Anaj Mandi

***910 Shri Zile Singh Sharma:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the extension of Anaj Mandi at Assandh town; if so, the time by which the extension work of the aforesaid Mandi is likely to be completed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh): Yes Sir, As soon as the suitable land is available, further action for extension of this Anaj Mandi would be taken.

Repair Roads of Market Committee

***958 Shri Raj Pal Bhukhri:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads of the Market Committee in Sadhaura Constituency: if so, the time by which the aforesaid roads likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (श्री परवीर सिंह): जी हा श्रीमान, सढौरा निवार्चन क्षेत्र मे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सभी सडको की मरम्मत 31.12.2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

डा० बिान लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड इनके अडर आता है इसलिए मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि 1.5.2005 से लेकर आज तक रादौर मे कितनी नई सडके बनाई गई है ।

श्री परमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एक सैपरेट प्रान है ।

Industries Minister Ashok Kashyap: Will the irrigation Minister be pleased to state whether there is huge erosion of Agriculture Land every year due to the flow of Yamuna river; if so, the steps taken or likely to be taken to stop the erosion of land of farmers in the State particularly in Indri Constituecny ?

Irrigation Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): No, Sir.

श्री अशोक कश्यप: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के इन्द्री मे लगातार वर्षा से युमना नदी मे बाढ आती है । इससे किसानो की कई एकड फसल तबाह हो जाती है । पिछली बार की बाढ मे तो फसल के साथ साथ किसानो की सैकडो एकड जमीने भी यमुना मे चली गई । यह प्रान मैने पिछली बार भी सैान मे लगाया था तब भी मुझे सरकार की तरफ से ना मे जवाब मिला था । अध्यक्ष

महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि हमारी इन्द्री हल्के किसानों के प्रति इस तरह का रवैया सरकार कब छोड़ेगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा: अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात गलत है कि इनके हलके की सैकड़ों एकड़ जमीन बाढ़ में बह गई। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो केवल 40 एकड़ जमीन बाढ़ से रूक गई थी और 40 एकड़ जमीन में हमने 10 बांध प्रयोज किए थे। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Member, is it the way that मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं और बिना लाल जी आप बीच में बोल रहे हैं? आप तो बहुत समझदार हैं प्लीज आप बैठें।

Sardar Harmohinder Singh Chattha: Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Chair that in the last six years, जब विपक्ष के साथी पावर में थे, उस समय बाढ़ रोकथाम पर 17.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। (विघ्न)

Mr. Speaker: At least let him complete his answer.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा: अध्यक्ष महोदय, जब हम पिछली जानकारी देते हैं तो इनको पीडा क्यों होती है? अध्यक्ष महोदय, इनके समय में 17.78 करोड़ रुपये बाढ़ रोकथाम के लिए खर्च किए गए और अब 96.68 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय साथी को भी बताना चाहूंगा कि इन्द्री

मे भी बाढ रोकथाम के लिए पूरी परयोजल बनाई है। जिससे इन्द्री मे फलड आने की सभावना कम रहेगी।

श्री औम प्रकाश जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हू कि पानीपत मे ड्रेन न0 1 है जिसके लिए पिछले बजट मे पैसे का भी प्रावधान किया गया था।

श्री अध्यक्ष: जैन साहब, यह स्प्रेट क्वै चन है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि यमुना नगर वाई.डबल्यू.एस. मे बाढ को रोकने के लिए ब्लाक बनाने के लिए पैसा दिया गया था। उसमे बडा भारी 44 करोड रूपये का घपला हो गया। जिसमे अनूप सिंह चिफ इजीनियर और अनिल अग्रवाल पर पैनल्टी इम्पोज करने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी काम 90 प्रति त हो गया है। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala: There is no Speech happening here. It is a question hour.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय,.....

Mr. Speaker: Not to be recorded.

Shri Randeep Singh Surjewala: He should have a call attention motion he should have given an adjournment motion, he should have made a specific mention and he should have wrtten to the Minister. How he disrupts the question hour in this fashion? He cannot disrupt the question hour.

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठिये ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर जो पैसा लगा है वह ईमानदारी से लगा है । उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, जवाब आ गया है जो आप कह रहे हैं वह गलत बात है । (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,.....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. He is trying make a speech Please sit down.

Establishment of University in Panchkula

***967 Shri Devender kumar Bansal:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. To establish an Universty in Panchkula>

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkaal Matanhai): No, Sir.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में एजूके इन की अपग्रेडे इन के लिए कई कदम उठाये गये हैं । कई यूनिवर्सिटीज और कालेज एजूके इन के स्तर को बढ़ाने के

लिए खोले गये है जिससे प्रदेश के छात्रों को बहुत सुविधा मिली है। पंचकुला के अंदर 5 हजार छात्र चण्डीगढ़ को माईग्रेट हो जाते है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या कोई प्राईवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी पंचकुला में बनाने पर सरकार विचार करेगी?

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, please give the specific answer regarding any proposal to come up with a Government or Private University in Panchkula?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail: Speaker Sir, presently there is no proposal under the consideration of the Government to establish a University in Panchkula. लेकिन माननीय साथी प्राईवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आये है जिसके तहत 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली है और 3 पाईप लाईन में है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि कोई पंचकुला में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का परपोजल लेकर आता है तो उसको जरूर कंसीडर किया जायेगा।

श्रीमति कवित जैन: स्पीकर सर, मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहती हूँ कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में अब तक कितने प्रोजेक्ट्स आये है?

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदया कजी यह भी बताने की कृपा करें कि राजीव गांधी एजूके इन सिटी में कौन-कौन सी इंटरनेशनल लैवल की यूनिवर्सिटीज आई है?

श्रीमति गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, वैसे तो यह सैपरेट क्वैशन है फिर भी मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि एजूके इन हमारी सरकार की टॉप प्रॉयोरटी पर है। Higher Education is the priority sector of the Government. We want to make an educational hub. (Interruption) हम हरियाणा और विशाखापट्टणम को एक एजूके इन हब बनाना चाहते हैं। राजीव गांधी एजूके इन सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लैवल की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। (गौर एवं व्यवधान) जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है कि राजीव गांधी एजूके इन सिटी के लिए चार यूनिवर्सिटी में से तीन को एल. ओ. आई. इ यू हो चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटी हैं एस. आई. ए. यूनिवर्सिटी जो मानव रचना यूनिवर्सिटी और अटोमोबाइल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एफ. आई. ए. यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद की है इसकी एल. ओ. आई. अभी पैडिंग है। (गौर एवं व्यवधान)

श्रीमति कविता जैन: स्पीकर सर, मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगी कि अब राजीव गांधी एजूके इन सिटी के लिए जमीन एक्वायर की गई थी तो उसमें यह कहा गया था कि राजीव गांधी एजूके इन सिटी में

इंटरनेशनल लैवल की यूनिवर्सिटीज आयेगी। क्या माननीय मंत्री महोदय जी इस बारे में कुछ बतायेंगी?

श्री अध्यक्ष: कविता जी, जो यूनिवर्सिटी वहां पर आ गई है वे भी अब इंटरनेशनल लैवल की बन जायेंगी। There universities will become of an international level.

श्रीमति गीता भुक्कल: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या के साथ-साथ जो माननीय सदस्य भाोरगुल कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हम इंटरनेशनल लैवल की लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजूकेन सिटी में लेकर आ रहे हैं जिसका बिल भी अति गिघ आने वाला है।

Mr. Speaker: That is an achievement. I must compliment you. National Law University is a big thing for Haryana. Now next question please.

Construction of ROB

***999. Smt. Savitri Jindal:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to stat-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Railway Over Bridge at Suryanagar in Hisar;

(b) if so, whether the matter has been brought into the notice of the Ministry of Railways by the Government. and

(c) if the reply to part (b) above be in affirmative, the present position

Industries Minister (Shri Randdeep Singh Surjewala):

(a) No, Sir.

(b) & (c) Question does not arise.

श्री सवित्री जिंदल: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर हिसर में मेरे द्वारा बताई गई जगह पर बाई-पास बिजीबल नहीं है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समस्या का कोई और कारगर हल हो सकता है जिससे वहां पर भाहर के निवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो चिंत जताई है मैं भी उससे अपने आपको जोड़कर यह बताना चाहूंगा कि जो सूर्या नगर का इलाका है यह हिसार-जाखल और हिसार-रेवाड़ी रेवले लाईन के बीच में हिसार भाहर के अंदर सिचुएटिड है और अब यह इलाका नगर पालिका के अंदर नगर आता है। यहां पर हुडा ने सैक्टर 1 व सैक्टर 4 और सैक्टर 3 व सैक्टर 5 भी डेवैल्प किया है और सूर्या नगर भी हुडा की परिधि के अंधार ही आ जायेगा। अभी अभी यहां पर आर. ओ. बी. के लिए सफिांट ट्रैफिक नहीं है लेकिन जो वहां पर एक रेलवेज को बोलकर उसको सैक्टर 1 व सैक्टर 4 और सैक्टर 3 व सैक्टर 5 की डिवाइडिंग रोड पर सिाड पर सिाफ्ट कर दिया है। अगर वहां पर आवागमन में कोई व्यवधान है

तो उसे इससे आसानी मिलेगी मिलेगा और जैसे ही वहां पर आर. ओ. बी. के लिए सफ़ि एंट ट्रैफिक अवेलेबल होगा तभी हम वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की प्रपोजल को नॉर्म्ज के मुताबिक कंसीडर करेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, माननीय विधायिका जी ने जो डबल फाटक के ऊपर ओवरब्रिज की बात कही है और उसके बाद जिंदल इण्डस्ट्रीज के साथ बने ओवरब्रिज की भी बात कही है। यह थिक्कली पापूलेटिड एरिया है और इस क्षेत्र में भाहर में भाहर की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। यह तक थिक्कली पापूलेटिड एरिया है और इस क्षेत्र में भाहर की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। जहां तक ट्रैफिक की बात है यह हो सकता है कि वहां पर ओवरलोडिड ट्रक्स वगैरह न जा रह हो लेकिन जो भाहर का आम ट्रैफिक है वह सबसे ज्यादा इस एरिया में है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि मंत्री जी इसको दोबारा कंसीडर करें। दूसरी बात मैं अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं जो कि हिसार भाहर के अंदर ही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर एक बाई-पास सैगान किया है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। वहां पर भी इसी प्रकार से दो फाटक आते हैं Sir, you will appreciate कि अगर बाई-पास बनेगा तो ओबिईसली उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक होगा। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां पर ओवरब्रिज बनाने के लिए भी वे इस मामले को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के साथ टेक-अप करें। क्या इस बारे में

बारे में कोई लैटर भेजेंगे ताकि वहां पर भी बाई-पास मंजूर करवाया जा सके? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुछेक ऐसी जगह पर रेलवे लाईन के दोनों तरफ सड़के बनी हुई है लेकिन वहां पर रेलवे फाटक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में पी. डब्ल्यू. डी. क्या बंदोबस्त करेंगी? क्या इसके लिए कोई प्रावधान सरकार के पास है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो श्रीमति सावित्री जिन्दल जी ने पूछा था और सम्पत सिंह जी आपने भी आपको उस चिन्ता से जोड़ा था कि यहां पर काकी ट्रैफिक है। उस बारे में मेरा कहना है कि हमने अभी सर्वे करवाया है जिसके मुताबिक वह भारत सरकार के रेलवे ओवर ब्रिज के नामॅर्ज में कवर नहीं होता लेकिन फिर श्री मति सवित्री जिन्दल जी ने और श्री सम्पत सिंह जी ने कहा है इसलिए हम इस बारे में पी. सी. यूज का फ्रै । सर्वे करवा लेते हैं अगर यह नामॅर्ज में कवर होता होगा तो सरकार को इसकी मूट करने में कोई समस्या नहीं है।

श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सूरजपुर-रामपुर-सियुड़ी से पिंजौर-नालागढ़ रोड़ स्थित सुखोमाजरी-बसौला बाई पास है जिसके लिए 2009 में 33 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन इस काम को भुरू करने में देरी क्यों हो रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता दुरुस्त है यह एक सैप्रेट प्र न है। इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। मुझे जहां तक ध्यान है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बतला देता हूं कि हमने इसको बी.ओ.टी. आधार पर बनवाने के लिए बात की है और नै नल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि वे इसको टेकअप करने के लिए तैयार है। अगर माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहते हैं तो वे मुझसे पूछ लें मैं सूचना इकट्ठी करके उनको कल बतला दूंगा?

तारांकित प्र न संख्या 979

(इस समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्र न नहीं पूछा गया।)

Construction of ROB at Gharaunda

***1005. Shri Narender Sangwan:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Railway Over Bridge near village Kohand no NH-I, Assand road, in District Karnal; if so the details thereof?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No, Sir.

श्री नरेन्द्र सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैंने रेवले ओवर ब्रिज के बारे में बंत्री जी से पहले भी पूछा था और उस

समय भी इनका जवाब ना में ही था। यह मामला तो कोहंड का मामला है लेकिन इससे धरोड़ा कस्बे का मामला था जहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसका जवाब मंत्री जी ने ना में दिया और अब भी जवाब ना में दे रहे हैं। हम रहती है जिसने भी प्र न पूछते हैं मंत्री जी उसका जवाब ना हमें ही देते है।

Mr. Speaker: No need to answer.

डा० वि न लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, अपने पिछले सै न में कहा था कि आप अपनी मांग के बारे में लिख कर भेज दिया करें। हम उस बात को मानते है और मैने माननीय मंत्री जी को दो महीने पहले इनके ऑफिस में जा कर किसी पुल के बारे में लिख कर दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसका जवाब कब तक आ जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और सांगवान साहब को भी मैने पिछली बार भी कहा था कि नै नल हाईवे का ग्रेडियंट इस पुल से देखें तो वह नॉर्मस मे कवर नहीं होता। हमारा नॉर्म 1x30 है इस इस पर रिफाइनरी का भी ट्रैफिक आता है। इसका जो नै नल हाईवे से डिस्टेंस है वह इसका परमिट नहीं करता कि वहां से हम फ्लाई ओवर बना सकें। अगर इसको बनाया गया तो वह सीधा नै नल हाईवे पर जा इसका हमने इग्जामिन करवा लिया है। ट्रैफिक भी जस्टीफाई करता है। There is no space or gradient available.

We cannot possible cause accident. नै 1नल हाईवे पर पुल सीधा नही उतारा जा सकता ।

Mr. Speaker: Alright, this is well-understood and well taken.

To Increase the Load of Transformers

***975. Shri Prithvi Singh:** Will the Power Minister be pleased to state the time by which load of transformers in Narwana Constituency is likely to be increased to meet out the of motores installed on tubewells?

बिजली मंत्री: (कैप्टन अजय सिंह यादव): श्री मान, वांछित कार्य तीन महीनों में पूरा हो जाएगा ।

15.00 बजे

कर्नर रघबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैने 2010-11 में भी मंत्री जी से पूछा था कि कादमा पॉवर हाउस को 33 के.वी. का तो नही बनाएंगे लेकिन उसका अपग्रेडे 1न 15 MVA से 20 MVA कर देंगे । आज एक साल हो गया है अब 5 MVA का ट्रांसफार्मर भी वहां नही पहुंचा है ।

श्री अध्यक्ष: सवाल क्या है आपका? Please बैठिए आप ।

कर्नल रघबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उसको अपग्रेड करके उसको 132 KV का करेंगे या वो 5 MVA घटाएंगे या बढ़ाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सैप्रेट प्र न है। इसके लिए माननीय सदस्य अलग से लिख कर दे।
(गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: It is separate question.

श्री कृष्ण लाल पंवार: स्पीकर सर, जैसा कि मेरे साथी पृथ्वी सिंह जी ने प्र न पूछा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के कारण किसानों की नलकूपों की मोटर जल जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री ज सै ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने नरवाना में कोई ऐसा सर्वे करवाया है कि कौन-कौन से ट्रांसफार्मर या पावरहाऊस ओवरलोड है और क्या उनको अपग्रेड करवाया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: आप नरवाना के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा आप नरवाना में बिजनेस कर रहे हो।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, मेरा बिजली महकमे से वि ोश लगाव है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर नरवाना में कुल 73 ट्रांसफार्मर है जिसमें से 26 का हमने ऑगूमैंट कर दिया है और जो बाकि बचे है उनकी अगले तीन महिने में हम ऑगूमैंट कर देंगे। पूरे स्टेट में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निमम में 3121 और दक्षिण में 2425 ट्रांसफार्मर है जिनमें से 797 और 200 क्रम 1: उत्तर और दक्षिण में हमने ऑगूमैंट कर दिये है इसके

अलावा 1259 ट्रांसफार्मर्ज उतर में और 1949 दक्षिण में बचे हुये है, उनके ऊपर तकरीबन 3675 लाख रूपये खर्च होंगे तथा उनको भी हम अगले तीन महीने में ऑगूमैंट कर देंगे।

Merger of C&V Cadre with T.G.T Cadre

***1050. Shri Singh Barshami:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to merge C&V cadre (of teachers) with TGT cadre;

(b) whether it is a fact that in view of (a) above, the ratio of number of posts of Middle School Head Masters, TGT, Lecturers etc. Will change; and

(c) if the reply to (b) above, is in affirmative, whether the interests of the employees, category wise, for promotion, shall be protected by maintaining their existing ratio of promotion?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail):

(a) No, Sir.

(b)& (c) Question does not arise.

श्री भोर सिंह बड़ामी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब ना में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो Classical और Vernacular Teacher है इनका अलग से कोई

प्रोमो इन का प्रावधान किया है या नहीं ताकि इनको भी टी.जी.टी. के बराबर सुविधा मिल सके, इनको भी प्रोमो इन मिल सके, क्या इसका कोई मामला विचारधीन है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्र न किया था कि क्या मर्जर का कोई प्रपोजल है, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे पास मर्जर को कोई प्रपोजल नहीं है लेकिन हमने हमारी एप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार C&V कैडर को डिमनिसिग और ड्राईग कैडर कर दिया है और जहां तक आपने प्रोमो इन की आत कही है, जिस तरह इनकी प्रोम इनज पहले होती थी उसी प्रकार एग्जस्टिंग स्नोरियो में होती रहेंगी।

तारांकित प्र न संख्या 1007

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय श्री राजेद्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Disposal of Sewerage Water

***1057. Shri Ganga Ram:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is fact that there are no proper arrangement for the diposal of sewerage water released from Rewari City; if so, whether there is any proposal under the consideration of the govt. for preper disposal of sewerage water in the aforesaid city?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary): Sir, there is an arrangement for the disposal of partially treated sewage water of Rewari City into the escape channel of Irrigation Department. However, due to objection of Irrigation Department, an alternative system to carry the partially treated sewage water from Rewari City to Massani Barrage is being explored.

Construction of Road

***993. Col. Ragbir Singh:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Chang road to Balkara via Dhadi Chillar in Badhar constituency for which an assurance was given by the PWD Minister during February-March, 2011 Session; if so, the reasons for which the action has not been taken so far together with the terms by which the aforesaid road is likely to be constructed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjwala): No Sir. An assurance was made for roads where available consolidation path is 6 karams wide. For this particular road, width of consolidation path in hadbust of village Changror is only 4 Karams. स्पीकर सर, कर्नल साहिब आज मुझसे मिले भी थे और इन्होंने ये कहा कि मौके पर जो कंसोलिडे ान पाथ है वो चार करम नही बल्कि छह करम है तो मैंने ये कहा है कि कर्नल साहिब अगर कोई फ़ैक्चुअल त्रुटि है तो बैठकर इस चैक करवायेंगे तथा मैं डिपार्टमेंट को भी बोलूंगा।

अगर कंसोलिडे एन पाथ चार करम की बजाय छः करम है तो सड़क बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं।

Construction of Bye-Pass

***904. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that there was proposal for construction of bye-pass near Pinjore from Surajpur to Sukonajrn Bassolan; if so the reasons for which the work of aforesaid Bye-pass has not been started so far?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes, Sir. The construction of this road could not be started so far because earlier it was decided that this road would be constructed by HUDA but later on this link was included in the proposed 4-laning project of Pinjore-Nallagrah (HP) Section of NH-21A. स्पीकर सर, इसके अलावा जो उन्होंने सप्लीमेंटरी में भी पूछा था ये उसके अंदर एड कर लिया गया है और इसको अब नै नल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है (गोर व विघ्न)

To attach the Dhanies with Panchayat/Municipality

***1074. Shri Krishan Kamboj:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that various Dhanies, surrounding Rania City, have nether been attached with any Panchayat nor with any the Municipality; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to attach/include these Dhanies with any of the Panchayat of Municipality; if so, the details thereof?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) Yes, Sir.

(b) The Government is considering to attach these Dhanies with the nearest Panchayat. स्पीकर साहब, हमने यह देखा है कि यह ढाणियां किसी पंचायत से एडेड नहीं थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं कि इन ढाणियों को जो क्लोजैस्ट पंचायत है उनके साथ एड कर देंगे।

श्री कृष्ण कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो ढाणियां हैं उनमें कई वोटर रह रहे हैं। यह ढाणियां न तो भाहर के अंदर आती हैं और न ही गांव के अंदर आती हैं। अतः या तो भाहर क्षेत्र 2 किलोमीटर बढ़ाया जाये या इन ढाणियों को नगरपालिका के साथ जोड़ा जाये या फिर इन ढाणियों को गांव की पंचायत के साथ जोड़ा जाये।

श्री अध्यक्ष: कंबोज जी ये तो डिमांड है, आप सवाल पूछो। (विघ्न)

Sh. Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, the demand is accepted. The Hon'ble Chief Minister has already

ordered आपकी आत वाजिब है इन ढाणियों की नजदीकी पंचायत के साथ मिला दिया जायेगा।

Mr. Speaker: Shri Kamboj ji, you demand is accepted. All the twenty question have been taken up today. Hon'ble Members, now the question hour is over.

'अतारांकित प्र न एवं उत्तर

विभिन्न मामले उठाना

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion.

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, हमने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने अपने कालिंग अटैं इन मो इन दिये थे उनका क्या हुआ।

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हमारे ये कालिंग अटैं इन मो इन बहुत ही जरूरी है। (गोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप एक-एक करके बोलें, सभी एक साथ न बोलें। (गोर व व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए।

मौहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: आप एक-एक करके बोलिये। Nothing is to be recorded.

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे) (गोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इनकी एक आदत बन चुकी है कि ये जीरो आवर में कोई मिनिंगफुल बात नहीं होने देंगे (गोर एवं व्यवधान)।

श्री मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: इलियास जी, मैं आपके अनुरोध को अस्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आप सभी बैठ नहीं जायेंगे और मुझ से बोलने की पहले परमिशन नहीं लेंगे तब तक मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इलियास जी, पहले आप बैठकर हाथ खड़ा करें कि मैं बोलना चाहता हूँ उसके बाद ही मैं आपको अलाऊ करूंगा।

श्री मोहम्मद इलियास: सदर साहब, हमारी पार्टी के सम्मनित सदस्यों द्वारा पाला गिरने से किसानों की फसल को हुए नुकसान के बारे में जो कालिंग अटैचमेंट दिया था उस पर बोलने के लिए जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी भी हूँ। हरियाणा प्रदेश में पाला गिरने से

किसानों की फसल को बड़ा भारी नुकसान हुआ है चाहे वह सरसों की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो। यह सर्वविदित है कि गेहूं की फसल के लिए सर्दी बहुत जरूरी होती है लेकिन इस साल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बर्फ पड़ने के कारण बहुत ज्यादा पाला पड़ा है जिसके कारण गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में तो बर्फ पड़ी ही नहीं। क्या हरियाणा के किसी आखिरी गांव में बर्फ पड़ी है? (गोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। विज जी, मैं खड़ा हुआ हूँ आप बैठ जाइए। मैं एक महत्वपूर्ण व्यवस्था विषय को यहां पर उठाया गया, इसके बारे में सारे सदन को सोचना चाहिए कि वह विषय केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा कि जितना महत्वपूर्ण विषय आप यहां उठा रहे हैं, उसका सारा महत्व समाप्त हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस विषय में मेरे साथ आप को ऑपरेट करें।

श्री अ लोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कालिंग अटै इन मो इन का फेट बताएं। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded whatever is saying without my permission. (Interruption)

श्री अ लोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपके इतना समझाने का क्या इन पर कोई असर हुआ है? (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अ लोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने हरियाणा में भारी पाले के कारण फसलों को हुए नुकसान के बारे में जो कालिंग अटै इन मो इन दी थी, आप उसका फेट बता दें।

श्री अध्यक्ष: आपका यह मो इन डिसअसलाऊ हो चुका है। (गोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री जगदी ा नैथर: अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने नगर पालिकाओं, नगर परिशदों और नगर निगमों में ठेके/तदर्थ आधार पर सफाई कर्मचारीयों की

सेवाओं को नियमित करने संबंधी जो कालिंग अटैं इन मो इन आपकी सेवा में दिया था, उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: आपका यह मो इन भी डिसअलाऊ हो चुका है (गोर एव व्यवधान) आप सभी आपनी आपनी सीटों पर बैठ जाएं

गोस्वामी गणे ा दत सनातन धर्म महाविद्यालय, सैक्टर-32,

चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि गोस्वामी गणे ा दत सनातन धर्म कॉलेज, सैक्टर-32, चण्डीगढ़ के छात्र आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो आपने आपको राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल के सदस्य कहते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि सदन की कुछ मर्यादाएं हैं और दे ा अगली पीढ़ी क्या ि िक्षा लेकर जाएगी? यह पीढ़ी यहां सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठी हुई है, इन बातों से दे ा की यह अगली पीढ़ी क्या ि िक्षा लेकर जाएगी? यह पीढ़ी सोचेगी कि क्या सदस्य एक इतने जिम्मेदार स्पीकर से ऐसा व्यवहार करते हैं। हमको कम से कम सदन की मर्यादाओं का तो निर्वहन करना चाहिए। सदन की

मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

चेयर पर आक्षेप करना/निलम्बन प्रस्ताव को वापस लेना

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने हरियाणा में विद्यालयों में राईट-टू-एजुकेशन एक्ट के तहत बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका फेट क्या है?

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी, पहले आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। (गोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इलियास, श्री जगदीश नैय्यर, श्री फूलसिंह खेड़ी और पृथ्वी सिंह नम्बरदार और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अनिल विज सदन की वैल में आ गये और जोर-जोर से बोलने लग गये)

Mr. Speaker: Please go back to your seats (Interruptions).

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप यह कागज ले लीजिए। आप हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir[papers cannot be given to the Hon'ble Speaker by a Member like this. (Interruption)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। ये माननीय सदस्य हाउस की वेल में आकर इस प्रकार से आपको कोई कागज न तो दे सकते हैं और न ही माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस प्रकार से कोई कागज लेकर उसे कंसीडर करना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर विज, आप इस तरह से वेल में आकर चेयर के सामने नहीं बोल सकते। आप अपनी सीट पर जाइये। मैं आपको बोलने का समय जरूर दूंगा आप इस तरह से वेल में आकर कुछ भी कहें, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी सीट पर जाइये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर,

Mr. Speaker : Not to be recorded. आप अपनी सीट पर जाइए, उसके बाद मैं आपको बोलने का समय दूंगा। आप मुझे कुछ भी डिक्टेट करोगे वह मैं नहीं मानूंगा। (गोर एवं व्यवधान)
No, no please. It is not a matter of joke. आप इसे मजाक समझते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। He cannot run a dialogue like this.

श्री अध्यक्ष : विज जी, आपको यह कोई राईट नहीं है कि आप हाउस को इस तरह से डिस्टर्ब करें और हाउस को चलने न दें। Please go back to your seats. (Interruption) Please go back to your seat. You cannot speak here. Go back to your seat. you do not know how to speak. You cannot speak here. Vij Sahib, you can't speak without my permission (Interruption). I warn you Mr. Vij. (Interruption) Please go back to your seat. I warn you Mr. Vij. (Interruption).

Now, the Parlimentary Affairs Minister will move a motion.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That Shri Anil Vij, M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of the present Session.

डॉ० अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, Vij Sahib cannot cast aspersion on the Chair like this. I strongly object it. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: Can you blackmail me? I cannot be blackmailed by anybody.

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कोई ब्लैक मेल वाली बात नहीं है, सबका चेयर के प्रति सम्मान है।
(गोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, he cannot cast aspersions on the Chair. It is totally unacceptable conduct.

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अनिल विज जी की सस्पेंशन वापस लें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर इस हाउस में हो रहे हैं और उन पर सप्लीमेंट्रीज का पूरा मौका मिल रहा है फिर सदन की वैल में आकर ब्लैकमेल करके यह कहना कि हमें बोलने दो नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे ठीक नहीं है?
(गोर एवं व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हम तो रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि हमें बोलने का पूरा समय दे दिया करें। हम में से किसी की सप्लीमेंट्री तो पूछने ही नहीं दी गई और न ही हमारे प्रश्नों का कोई जवाब आ रहा है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या इधर से भी तीन प्र नों पर मैंने कोई सप्लीमेंट्री नहीं होने दी थी? जब कोई सप्लीमेंट्री थी ही नहीं तो मैं कैसे कोई सप्लीमेंट्री होने देता। (गोर एवं व्यवधान)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा तो नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अजय सिंह जी, आप उनको आहिस्ता—आहिस्ता समझा तो रहे हैं लेकिन ये कब समझेंगे ये पता नहीं। ये कहीं और बैठे हैं और आपकी बात कम मानते हैं।(गोर एवं व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात को सभी मानते हैं। (गोर एवं व्यवधान) आप सामने बैठने वालों की सारी बातें न माना करो बल्कि हमारी भी कुछ माना लिया करो। (गोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, If Hon'ble Member assures that he will not cast any aspersions on the Chair, I will withdraw my motion.

श्री अध्यक्ष: चेयर पर एस्प नि करना गलत है।

Shri Randeep Singh Surjewala: It is not acceptable.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठिए (गोर एवं व्यवधान)

श्री भोर सिंह बड़ामी: अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अनिल विज जी की सस्पैँ उन वापिस ले लें।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, आप बैठ जाइए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का एक मौका दे दो।(तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Alright, Mr. Vij, you are not sitting. (Interruption) You are not acceding to my request. Please sit down. (Interruption) आज बिना पूछे खड़े नहीं होंगे। आप केवल हाथ रेज करेंगे, बोलेंगे नहीं। बस, अगर आप अब भी बिना मेरी परमि उन के बोलेंगे तो I read this motion, आप हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, अब मेरा हाथ खड़ा है। (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I read the motion because he is not amending himself.

Shr Sher Singh Barshami : Speaker Sir, please withdraw this motion.

Mr. speaker: Alright, I withdraw it, as senior Members are requesting to withdraw this motion but Hon'ble Member Shri Anil Vij should behave in the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, हम आपको विनास दिलाते हैं कि अनिल विज जीअब चेयर पर एस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं चेयर रिगार्ड करता हूँ और मैं अपनी तरफ से आपको कोपरेटिव बनाने के लिए एस्पॉन्सिबिलिटी करता हूँ लेकिन आप मुझे बोलने का मौका जरूर दे दिया करें।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, श्री अनिल विज इस सदन के वरिष्ठ और जिम्मेवार हैं। चाहे वे विपक्ष में हैं फिर भी हम सब एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते और एक दोस्त होने के नाते इनका आदर करते हैं। चाहे हम सत्ता पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों परन्तु हम सबकी एक मर्यादा है और इस सदन की भी मर्यादा है कि जो स्पीकर हैं और जो हम सबके अधिकारों के कस्टोडियन हैं हम सब उनकी चेयरकी गरिमाका ध्यान रखें। हम आपस में कई बार वाद विवाद और उत्तेजना कर लेते हैं पर आखिर में speaker Sir, you are the custodian of the house. अगर चेयर पर हम एस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो यह अनुचित है और निंदनीय है। माननीय सदस्य ने बैठते हुए यह कहा है कि वे चेयर का हाइस्ट रिगार्ड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि चेयर के प्रगति कम से कम ये अपनी टिप्पणियों पर नियंत्रण रखेंगे। दूसरे साथी अजय सिंह चौटला जी और अरोड़ा जी ने भी उनके बिहाफ पर यह कहा है कि उनकी सस्पेंशन वापसली जाए

तो मैं समझता हूँ कि उनकी ए योरेंस को मानते हुए यदि आपकी इजाजत हो तो I withdraw it.

Mr. Speaker: Alright. motion is withdrawn and this matter is closed now.

नियम 30 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.

Industries Minister (Shri 'Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government business on Thursday, the 1st March, 2012.

Sir, I also beg to move-

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and government Business be transacted on Thursday, the 1st March, 2012.

Mr. Speaker : Motion moved-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 1st March, 2012.

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 1st March, 2012.

Mr. Speaker : Question is-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government business on Thursday, the 1st March, 2012.

AND

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 1st March, 2012.

(The motion was carried)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में पारदर्शिता संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Member, I have received a Calling Attention Notice No.7 from Shri Bharat Bhushan Batra, Mla regarding transparency in Public Distribution (PDS) in Haryana. Mr. Batra may please read his Calling Attention Notice.

Shri Bharat Bhushan Batra: I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that transparency in Public Minister, Dr. Manmohan Singh as also a number of National Leaders over a period of time. PDS is a key driver for percolation of benefits to given by way of subsidy by Central and State Government for providing adequate food security in terms of food grains, pluses, oil, sugar, kerosene oil etc. through PDS. Government, administrators, social organization and policy analysts have repeatedly pointed out the fact of non-availability of these benefits to the poor in PDS on account of its inherent leakages and pilferage at various steps in the distribution hierarchy. He has further requested the Government to make a statement on the floor of the House regarding total number of PDS beneficiaries in the State, quantum of benefits provided through PDS and steps taken to make PDS more effective, transparent and reliable as also to ensure that leakages/pilferages in the system are plugged once for all by use of Information Technology or any other measure.

Mr. Speaker: Now, the concerned Minister will make a statement.

वक्तव्य

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): भारत सरकार द्वारा दिये गये दि ॥ निर्दे ॥ों पर, अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई) तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

(बी.पी.एल.) करने वाले लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण विकास विभाग तथा भाहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा क्रम 1: ग्रामीण व भाहरी क्षेत्रों में की जाती है। भारत सरकार द्वारा ही राज्य में बी.पी.एल. और अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या निर्धारित की जाती है। भारत सरकार ने हरियाणा हेतु अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की अधिकतम सीमा 3.02 लाख परिवार तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य परिवारों की अधिकतम सीमा 4.86 लाख परिवार, इस प्रकार कुल 7.89 लाख को बी.पी.एल. परिवारों के रूप में मान्यता प्रदानकी है। जबकि ग्रामिण विकास ओर भाहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 12.97 लाख है। इस समय भारत सरकार 7.89 लाख बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न का आबंटन कर रही है। जबकि हरियाणा सरकार ने बचे हुए 5.08 लाख बी.पी.एल. परिवारों को भी बी.पी.एल. दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इन परिवारों को राज्य बी.पी.एल. परिवारों के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा दिये गये ए.पी.एल. के खाद्यान्न का एक हिस्सा राज्य बी.पी.एल. परिवारों को उपलब्ध करवाया जाता है और दरों के इस अन्तर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस उद्देश्य के लिये इस वर्ष 43.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. सरकार द्वारा आबंटित किये गये आव यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग के पास जिला, ब्लॉक और जमीनी स्तर पर एक व्यापक संरचना है। मिट्टी के तेल के इलावा अन्य आव यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में कानफ़ैड एक थोक विक्रता नियुक्त करती है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने 9364 उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की है जिसमें से 2699 भाहरी क्षेत्र में तथा 6665 ग्रामीण क्षेत्र में है। गत् वर्ष राज्य सरकार द्वारा 5.81 लाख मिट्टिक टन गेहूँ का आबंटन विभिन्न श्रेणियों जैसे अन्त्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल., राज्य बी.पी.एल. और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) वाले लाभार्थियों को किया गया जिसमें लगभग 435 करोड़ रुपये की सबसिडी दी गई। इमें से लगभग 27 करोड़ रुपये की सबसिडी हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई।

3. राज्य सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये हैं। लक्षित परिवारों को आव यक वस्तुओं के वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए गांवों एवं वार्डों में निगराना समितियों का गठन किया गया है जिन्हें वास्तविक वितरण पर चौकस नजर रखने का अधिकार है। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिशदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यनवयन में एक निर्णायक भूमिका निभाने का अधिकार दिया गया है जिसमें नया राशन कार्ड बनाने, डिपो आवंटन करने हेतु नाम की सिफारिश करना व वास्तविक

वितरण कार्य प्रणाली की निगरानी करना आदि शामिल है। जिला
 िकायत निवारण समिति की मासिक बैठक में सार्वजनिक वितरण
 प्रणाली की समीक्षा की जाती है। िकायत यदि कोई हो तो,
 सभी सदस्यों की उपस्थिति में उसका निपटान किया जाता है।
 वर्ष 2011.12 के दौरान खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य
 की दुकानों की जांच हेतू विशेष अभियान चलाया गया। वर्तमान
 वर्ष में, दोशियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का वर्णन निम्न
 प्रकार है है :-

(1)	पुलिस में दर्ज मामले	19
(2)	गिरफ्तार व्यक्ति	06
(3)	लाईसेंस रद्द	137
(4)	सुरक्षा राशि जप्त (रु०)	6.75 लाख
(5)	मिट्टी के तेल के थोक व्यापारी लाईसेंस रद्द / निलंबित	2

4. राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
 लाने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा राज्य को भारत सरकार के

स्मार्ट कार्ड पायलट प्रोजैक्ट को भुरू करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह पायलट प्रोजैक्ट केवल हरियाणा और केन्द्रीय भासित प्रदे ा चण्डीगढ़ में ही लागू किया गया है। इस प्रोजैक्ट से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली गड़बडियों को उचित तकनीकी समाधान प्राप्त होगा। इस प्रोजैक्ट पर कुल 137.00 करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी। इस प्रोजैक्ट पर राज्य द्वारा कार्य भुरू किया जा चुका है।

5. राज्य के लगभग 56 लाख परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार स्मार्ट राशन कार्ड जारी किये जाएंगे। स्मार्ट राशन कार्ड पर विभिन्न श्रेणियों के परिवारों के लिए अलग-अलग रंग की धारी (अन्त्योदय अन्न योजना के लिए गुलाबी, बी.पी.एल. के लिए पीली और ए.पी.एल. के लिए हरी) होगी। आवेक उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त करने के लिए परिवार के 3 सदस्यों के उंगलियों के निशान स्मार्ट कार्ड में संग्रहीत किये जायेंगे तथा आवेक उपभोक्ता वस्तुएं अधिकृत प्राप्तकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के बाद ही जारी की जायेंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लेनदेन वास्तविक उपभोक्ताओं को ही हुआ है। हरियाणा में स्मार्ट कार्ड प्रोजैक्ट की विशेषता यह है कि इसका भारतीय विनिश्चि पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किये जा रहे आधार कार्ड के साथ समावेश किया गया है।

6. भारतीय विनिश्चि पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए. आई.) द्वारा पूर्ण बायोमीट्रिक पुनर्मिलान करने के बाद खाद्य एवं

पूर्ति विभाग द्वारा ये कार्ड जारी किये जायेगे जिनमें यह सुनिश्चित होगा कि फर्जी तथा नकली राशन कार्ड बनने का सिलसिला हमें 11-हमें 11 के लिए समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त आवधिक वस्तुओं की मासिक पात्रता भी स्मार्ट राशन कार्ड की चिप में संग्रहीत की जायेगी।

7. प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के मालिक को एक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित प्रत्येक परिवार की मासिक पात्रता निहित होगी। उचित मूल्य जाने वाले सामान की प्रक्रियामें सहायता करेगा। यह उपकरण लाभार्थी के कार्ड और उंगलियों के निशानों का सत्यापन करने में सक्षम होगा।

(श्री महेन्द्र प्रताप सिंह)

8. परियोजना के पहले चरण में चार खण्डों अमबाला, सिरसा, सोनीपत व धरौंडा को प्रायोगिक आधार पर चुना गया है। इन चार खण्डों में सभी परिवारों के 12 साल से ऊपर के सभी सदस्यों की दसों उंगलियों के निशान लेने हेतु विधिवर आयोजित किये गये है। इसके अलावा परिवार में 5 साल की उम्र से ऊपर के सदस्यों का आईरिस डाटा भी नुर्नमिलान हेतु लिया गया है। यह डाटा यूआईडी को पुर्नमिलान व आधार नम्बर जारी करने के लिए भेज दिया गया है।

आज तक 6.40 लाख निवासियों का डाटा डिजीटल किया गया है। जिसमें से 5.80 लाख निवासी परिवारों में भाग ले चुके हैं तथा 4.32 लाख को यूआईटी संख्या जारी की जा चुकी है। आवक तकनीकी ढांचे को हरियाणा राज्य डाटा केन्द्र में स्थापित कर दिया गया है तथा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मुख्यालय में एक विशेष आई.टी.सेल स्थापित कर दिया गया है। परियोजना के जून 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को कितना (गेहूँ, भूगर, करोसीन ऑयल) राशन दिया जाता है और उसका सारा खर्चा कौन वहन करता है? इसी तरह से ए.पी.एल. का कितना भोयर बी.पी.एल. में कन्वर्ट किया जाता है? आज के दिन सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यह है कि ए.पी.एल. कार्ड धारकों को कोई रिलीफ नहीं मिलता। APL card is above poverty line उनका राशन बी.पी.एल. में कन्वर्ट किया जाता है बाकी राशन मार्केट में बिकता है। इसका कारण यह है कि ए.पी.एल. कार्ड धारकों 10 किलो राशन मिलता है और 10 किलो राशन लेने के लिए ए.पी.एल. कार्ड धारक डिपू होल्डर के पास नहीं जाते। मंत्री जी आपने जवाब में बतायें कि ए.पी.एल. का कितना राशन कन्वर्ट किया जाता है और कितना राशन नॉन यूटीलाईज्ड राशन में जाता है? आज के दिन बी.पी.एल. की एक ज्वलंत समस्या हमारे सामने है और बी.पी.एल. कार्ड बनाने के

साथ-साथ इस पूरे सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए क्योंकि जब एक बार राशन कार्ड बन जाता है फिर उको बाद में नॉर्मल फुलफिल करने के कारण काटते हैं इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो वह क्यों होता है, क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट में मिनरी प्रॉपर वर्क करती है या नहीं करती है और उसके बाद उसमें क्या मॉनिटरिंग है? गलत बी.पी.एल. कार्ड को बनाने के लिए who is responsible? क्या कन्ज्युमर रिस्पॉन्सिबल है या सरकार के अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है? ये मेरा पहला सप्लीमेंट्री है। मंत्री जी पहले इसके बारे में बतायें उसके बाद मैं अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष मोहदय, जैसा कि मैंने कहा है कि पी.डी.एस. एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है उस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि पी.डी.एस. सबे कलए नहीं है। इस बारे में पहली बात तो यह है कि इसमें जा ए.ए.वाई हें वे गरीबी रेखा से भी नीचे हैं और एक वे है जो बी.पी.एल. है। जैसा कि मैंने इमें भुरु में ही कहा था कि गांवों में डी.आर.डी.ए. द्वारा ग्रामीण इलाकों में और अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा भाहरों में किये गय सर्वो द्वारा तकरीबन 12.97 लाख परिवारों को आईडेंटिफाई किया गया है। जो समस्या माननीय सदस्य जी ने उठाई है यह समस्या सारे देा में ही व्याप्त हैं। जहां तक हमारे राज्य में इस समस्या की बात है वह सारे देा के दूसरे तमाम राज्यों से बहुत कम है। हमारे यहां

आबादी और यूनिट के लिहाज से तकरीबन 56 लाख के करीब ए. ए.वाई. और बी.पी.एल. कार्ड हैं। हमारी यूनिट्स 2 करोड़ 48 लाख के करीब हैं। यहां पर फर्जी कार्डों की समस्या नहीं है अगर इस बारे में कहीं कोई समस्या है तो वह ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. कार्ड के बीच की समस्या है। आज हमारे प्रदेश की आबादी 2 करोड़ 55 लाख के करीब है अर्थात् कार्डों और यूनिटों के अंदर बोगस की समस्या नहीं है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य और सदन को यह बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. कार्डों की संख्या को 12.97 लाख पर फिक्स कर दिया है। अभी तक 7.89 लाख कार्ड ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये हैं और जो 12.97 लाख में से तकरीबन 4.68 लाख परिवार ऐसे हैं जो बकाया बच गये हैं इनको भी हमने कवर करने का प्रयास किया है ए.ए.वाई. कार्ड के माध्यम से जो गेहूं अलॉट होती है उसमें से तकरीबन आधा गेहूं जिकी सबसिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है वह उन परिवारों को स्टेट बी.पी.एल. कार्ड के माध्यम से हम दे देते हैं। जो हमारे अब तक के सर्वे के मुताबिक 12.97 लाख कार्ड है उन पर 28 करोड़ रुपये के करीब सबसिडी है। इसको इयरमार्क तो 43 करोड़ रुपये किया गया था लेकिन 28 करोड़ रुपये के लगभग सबसिडी सरकार की तरफ से दे करके उनको वह राशन कार्ड मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह किया है कि कितना-कितना लिफ्टिंग एलोकेशन अलग-अलग कैटेगरी का है। यह भी मैं सदन और माननीय सदस्य को बताता हूँ वर्ष 2011-12 के दौरान 2

लाख 34 हजार 300 टन गेहूं अलॉट किया गया जिसमें से तकरीबन 2 लाख 19 हजार टन गेहूं लिफ्ट किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 1 लाख 3 हजार 342 टन गेहूं अलॉट किया गया जिसमें से 98 टन गेहूं अलॉट किया गया है इसके अतिरिक्त 2011-12 ए.ए.वाई. में भारत सरकार द्वारा 3 लाख 50 हजार टन गेहूं अलॉट किया गया। यह सारे साल का है महीनेवार यह तकरीबन 35 हजार टन के करीब बनता है जिसमें से 2 लाख 19 हजार 800 टन लिफ्ट किया गया। इस गेहूं का स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों को 4.88 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से हम आधा गेहूं ए.ए.वाई. के परिवारों के लिए और बाकी का आधा बी.पी.एल. परिवारों के आबंटन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि तकरीबन 15.16 हजार के करीब बनता है।

श्री भारत भूशण बत्तरा: अध्यक्ष, महोदय, असलियत में ए.पी.एल. राशन कार्ड होल्डर्स राशन नहीं लेते वे 10 किलो लेने जाते हैं। तो 9 किलो राशन तो वैसे ही मिलता है और उसमें से भी 1 किलो चक्की वाला काट लेता है, उसका वह क्या करेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि ए.पी.एल. का जो राशन है उसको एस.बी.पी.एल. में कन्वर्ट कर दिया जाये उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन मिल सकता है जिससे जो 2 रुपये 15 पैसे की सब्सिडी है वह भी बढ़ जाये। स्पीकर सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो राशन के डिपो होते हैं उनमें

तकरीबन 300 से 1200 तक राशन कार्ड होल्डर होते हैं जिनमें 300 बी.पी.एल. के होते हैं। एक डिपो के लिए 2700 रूपये मिलते हैं तो ऐसे में 2700 रूपये में कौन डिपो चलायेगा और कैसे चलायेगा? इससे आप समझ सकते हैं कि ये पिलफ्रिज और लीकेज कहां पर है? इस पर भी सरकार को चैक रखना चाहिए। इस इन्सपैक्टर कितने डिपोज को चैक कर सकता है। 60-70 डिपोज एक इन्सपैक्टर के पास होते हैं और वह रैगूलर चैकिंग नहीं कर सकता। इसका भी कोई प्रावधान किया जाता चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्वाइंट आउट किया है वह काफी हद तक सही है। लेकिन जहां तक ए.पी.एल. की बात है हमने इन बातों के मध्यनजर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको एलोकेट नहीं किया है। उसमें से आधा गेहूं जो हम स्टेट बी.पी.एल. में कन्वर्ट कर सकते थे वह हमने कर दिया है और इसी वजह से हमने उसको रोका है। लेकिन फिल्ड से माँग फिर बढ़ रही है जिनमें आप जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वे भी कह रहे हैं कि ए.पी.एल. को भी राशन दिया जाना चाहिए। जो लेने वाले हैं वे ले लेते हैं लेकिन यही सही है कि इसमें से डायवर्सन की सम्भावना काफी है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं कि 2700 रूपये में डिपो होल्डर डिपो को कैसे चला रहा है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनका यह सवाल बहुत वाजित है। 1991 में भी यह सवाल उठाया गया था तब तो एक डिपो होल्डर को 500 रूपये ही मिलते थे, उस समय जो उत्तरी भारत की थ्री मैन कमेटी थी मैं भी उसका मैम्बर था। हमने यह सवाल उठाया था कि एक तरफ तो हम डिपो होल्डर पर अंकुश लगाते हैं और ईमानदारी की उम्मीद करते हैं और दूसरी तरफ बेईमानी के लिए खुला छोड़ते हैं। जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो वह कुछ न कुछ तो करेगा ही। उस समय इनका मार्जिन बढ़ाया गया। आज के दिन यह 2700 रूपये नहीं है। मेरे हिसाब से यह 1500 से 2000 रूपये के आसपास है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: मंत्री जी, इसके लिए कुछ कीजिए ना।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : इसके लिए जो मार्जिन है उसको भारत सरकार फिक्स करती है। सब्सिडी सरकार दे रही है। इससे ज्यादा कंज्यूमर पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इससे ज्यादा या तो स्टेट को वहन करना पड़ेगा। स्टेट पहले ही 285 करोड़ रूपये की सब्सिडी दे रही है। लेकिन यह चिन्ता वाजिब है। इसके लिए हम भारत सरकार से फिर आग्रह करेंगे। यह केवल हरियाणा का ही इश्यू नहीं है बल्कि पूरे देश का है और इसमें मार्जिन बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक स्तर पर

पंचायत स्तर पर और कमेटी स्तर पर भी विजिलेंस कमेटी मौजूद है और उनकी रिपोर्टें डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस में भी और जिला परिषद् में भी आती है उनका निवारण भी चाहे कोई चोरी की है और चाहे डायवर्सन की है, किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लाई जा रही है जो कि आधार कार्ड से जोड़ कर चलाई जायेगी। यह हमने चार ब्लॉक्स में चालू की है। इसके भुरू होने के बाद इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगेगा कि यह डायवर्सन न हो।

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पंचकूला जिले बी.पी.एल. कार्ड से मिलने वाला मिट्टी के तेल का कोटा बंद कर दिया गया है? अगर बंद कर दिया है तो क्यों किया गया है? अगर यह कोटा दिया जा रहा तो एक ए.पी.एल. कार्ड पर कितना कोटा दिया जा रहा है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, ए.पी.एल. का कोटा तो सब जगह ही बंद कर दिया गया है। तीन-चार महीने से बी.पी.एल. के कोटे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। उसमें से कुछ हिस्सा मिट्टी के तेल का हम स्टेट बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स के नाम से बांटते हैं। (गौर एवं व्यवधान)

श्री प्रदीप चौधरी: सर, हमारा एरिया आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मामला उठाया है इसी वजह से ये ए.पी.एल. कार्ड बंद कर दिए गये हैं। अगर इनकी डिमांड है तो इसको बांटना भुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है मंत्री जी, आपका जवाब क्लीयर है।
Shri Ashok Arora want to make a suggestion please.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बत्रा जी ने कहा कि डीपू होल्डर कोई भी व्यक्ति हो जब तक उसको उसकी मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से चोरी की संभावना बढ़ेगी। अगर चोरी होगी तो BPL के कार्ड होल्डर का राशन कटेगा। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सरकारी दुकानें खोल कर उनसे वितरण कराए तो हो सकता है कि इसमें कुछ कमी आ जाए क्योंकि पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी दुकानें खोल कर राशन का वितरण कराया था। आप इस काम को किसी अन-एम्पलाइड आदमी की DC रेट पर कराएँ तो इससे चोरी भी बचेगी और काम भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मंत्री जी से एक अनुरोध और करूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर आज रसोई गैस की काला बाजारी बहुत जोरों पर है। इसके बारे में भी आप महकमें की तरफ से ऐसा प्रबन्ध करें ताकि काला बाजारी को रोका जा सके क्योंकि आज रसोई गैस लेले में इतनी लूट मच रही है कि जितनी लूट कभी नहीं हुई इसके बारे में भी विचार करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion on the Governor's Address will be resumed. Shri Parminder Singh Dhul will speak now.

श्री परमिन्द्र सिंह ढूल (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम जी ने जो अभिभाषण 23 तारीख को पढ़ा उसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की गई है। विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया गया है। पेज नं० 3 पर किसानों के बारे में बताया गया है। पेज नं० 6 पर सिंचाई से सरोकर बताया है। पेज नं० 10 पर ग्रामीण विकास, पेज नं० 13 पर शिक्षा के बारे में और पेज नं० 15 पर युवा एवं खेल के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे अभिभाषण के अन्दर जो विवरण दिया गया है, यदि वह उस विवरण के बारे में इस वर्ष कैग की रिपोर्ट के साथ अवलोकन करें जो मानवीय गवर्नर साहब के भाषण के बाद इसी महान सदन में पेश की गई तो यह अभिभाषण झूठ का पुलिन्दा साबित होता है। (CAG) कैग की रिपोर्ट में जींद जिले के बारे में पेज नं० 4 के पैरा नं० 1.513 में लिखा है:—

“ विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास गतिविधियों कार्यान्वयन की स्थिति तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए

जीन्द जिला केन्द्रिक लेखा परीक्षा संचालित की गई थी। जांच ने प्रकट किया कि जिला योजना समिति ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। जिला में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना तथा डाक्टरों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप यह निम्नलिखित—मृत्युदर, जन्मदर तथा मृत्युदर को कम करने और जन्मपूर्व देखभाल, संसृष्ट प्रवासों इत्यादि में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में 777 स्कूलों के मरम्मत कार्यों के निष्पादन की मानिट्रिंग की कमी थी, जोकि मानिट्रिंग की जानी चाहिए थी। कई स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएँ नहीं थी। 2006-11 के दौरान किए गए 8969 नमूनों में से कुल 851 नमूनों में जीवाणु विज्ञानी सम्मिश्रण थे।”

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अगर इनका अवलोकन पूरे सिलसिलेवार किया जाये तो किसी भी रूप में आज यह गवर्नर साहिब का भाषण किसी भी तरह से विकास करने हेतु गतिविधियों को आवृत्त करते हुए पंचवर्षीय सद्व्ययोजना तथा एक संगठित जिला योजना तैयार नहीं की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ देखभाल सुविधाओं में अंतराल चिन्हित करते हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किये गये थे, जहां स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं में डाक्टरों की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, चालिस परसेंट डाक्टरों की कमी थी तथा मूल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अंतराल चिन्हित करने हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किये गये थे, जहां स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं में डाक्टरों की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, चालिसपरसेंट डाक्टरों की कमी थी तथा मूल स्वास्थ्य

देखभाल सेवाओं के प्रदान करने हेतु अपर्याप्त सुविधाओं थीं। लगीग 20 से 22 परसैंट अन्य स्टाफ की कमी दिखाई गई। अध्यक्ष महोदय, इसी कैग की रिपोर्ट के पेज नं0 71 पर 2006 से 31 मार्च 2011 तक जींद जिले के समेकित विकास के लिए मात्र 185.45 करोड़ रूपये दिये गये, उसमें से भी 14 करोड़ 75 लाख रूपये आज भी बकाया हैं। इससे ग्रामीण विकास का जो वास्तविक चेहरा है वह माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो लिखा है उसको पढ़ कर पता चलता है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अंतराल चिन्हित करने हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण किया जाना उपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया कि जिले में ऐसा कोई कभी सर्वेक्षण किया जाना उपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया कि जिले में ऐसा कोई कभी सर्वेक्षण किया सर्वेक्षण करवाया ही नहीं गया, यह कैग की रिपोर्ट के पेज नं0 72 पर लिखा है। अध्यक्ष महोदय, सी.एच. सी. और पी.एच.सी. की की हमारे जिले में बहुत भारी कमी है। लगातार कहने के बाद आज भी 46 सी.एच.सी. और पी.एच.सी. कम है। यह मैं नहीं कह रहा बल्कि यह तो कैग की रिपोर्ट कह रही हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के पेज नं0 75 पर लिखा है कि 6432 कोल्ड चैन उपकरणों में से 1722 आज भी उपकरण खराब पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट के पेज नं0 78 पर लिखा है कि 2006 और 2011 के दौरान 91.99 करोड़ रूपये का आबंटन प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया जिसमें से केवल 81 प्रतिशत खर्च किया गया। इसके कारण हमारे जिले के प्राथमिक

स्कूलों की स्थिति आज भी अत्यंत नाजुक है। आज भी जिले के अंदर चाहे प्राचार्य हैं चाहे मुख्याध्यापक हैं इनके अंदर 60 परसेंट की आज भी कमी है। ये सब आपकी सरकार में है, मंत्री जी (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे 2008 में सरकार में जाकर पत्थर लगाकर बड़े जोर-जोर से बाई-पास के निर्माण की घोशणा की थी। जोकि 2009 में भुरू होकर के दिसम्बर 2009 तक पूरा होना था। इसके लिए 17.71 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये लेकिन आज भी केवल 3.57 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। कैंग ने जब वहां के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि यह काम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास माल अवेलेबल नहीं था जबकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की किताब में लिखा है कि उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि प्रदे 1 में अन्य जगह भी काम हो रहे थे।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): प्वाँयंट ऑफ आर्डर, सर। स्पीकर सर, सदन के पटल पर भी यह बात दी गई थी लेकिन भायद माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं होंगे। जिस एजेंसी ने बाई-पास के निर्माण का काम लिया था वह एजेंसी सीमित समय के अंदर काम नहीं कर पाई। हमने उसका कान्ट्रैक्ट ट्रमिनेट कर दिया और उसकी ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही भुरू कर दी और उसे ब्लैक लिस्ट का नोटिस दे दिया। 29 फरवरी यानि जो माह अभी खत्म हुआ है, उस दिन जो नया टेंडर था उसे खोला गया है और दोबारा से उस काम को किसी

नई एजेंसी को अलॉट करके बहुत जल्दी वह पूरा कर दिया जायेगा। मैटीरियल की समस्या है, यह सबको मालूम है पर इसके बावजूद भी दूसरे पड़ोस के राज्यों से मैटीरियल लाकर भी हम यह बाई-पास के निर्माण का काम पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे।

Mr. Speaker: Yes, Hon'ble Member, you may continue, please.

श्री परमिन्दर सिंह दुल: इसी रिपोर्ट के पेज नं० 87 पर पैरा नंबर 2.3.15.1— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत रजबाहों और नहरों की सफाई के आदे दिये गये लेकिन उन आदे गों की हमारे जिले में पालना नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज वहां भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, इन सबसे मुझे बड़ी चिंता हो रही है। सिंचाई के बारे में बड़ा कुछ कहा गया। हमारे इलाके के अंदर सुंदर ब्रांच है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2611 थी लेकिन 1966 के बाद से आज तक उसकी सफाई न होने की वजह से वह दोनों तरफ से पूरी तरह से अटी पउत्री है और 10-10 फुट बंद है। 2008 में नहर महकमें द्वारा 5 करोड़ रुपये के लगभग की राशि खर्च करके सुंदर नहर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनकी रेजिंग की गई लेकिन इसके बावजूद वह नहर किसी भी दिन 1300-1400 क्यूबिक से ज्यादा नहीं चली। सिर्फ एक बार 2010-11 में बरसात के दिनों में वह तीनदिन कुछ ज्यादा चली थी। सिर्फ तीन दिन वह 1700 क्यूबिक के आसपास चली थी जिसकी वजह से हमारे जींद

जिले और भिवानी जिले को नुकसान हुआं 1966 से आज तक न हांसी ब्रांच की सफाई हुई है न सुंदर ब्रांच की हुई हैं सर, आज किसान को बिजली नहीं मिलती, समय पर खाद नहीं मिलता। उसे घंटों रात की लाइन में लगकर पांच कट्टे यूरिया खाद के मिलते हैं आज किसान को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में किसान किस तरह से सिंचाई के कार्य पूरे कर लेगा। अध्यक्ष महोदय, आज यह बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आप मनरेगा स्कीम का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे कि मेरे जिले में वर्ष 2008-09 में 22130 पंजीकृत परिवार थे उनमें से केवल मात्र 210 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। इसी तरह से वर्ष 2009-10 में 24999 पंजीकृत परिवार थे उनमें से केवल मात्र 96 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया जो कि प्रति गाँव के हिसाब से 038 था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: दुल साहब, अब आप वाइंडअप करें।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : सर, मेरे एक-दो प्वाँयंट बाकी रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल: धन्यवाद सर, सर, 2010-11 में पंजीकृत परिवारों की संख्या 27075 थी उनमें से केवल मात्र 137

परिवारों को रोजगार दिया गया, ये भी प्रति 100 के हिसाब से 0.50 बनता है। मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से आंकड़े आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज सदन में हमारे खेल मंत्री जी ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में बड़ा दावा किया कि सरकार द्वारा गोल्ड मैडलिस्ट खिलाड़ियों को नौकरियां और उनके गांव के विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। मेरे हल्के के गांव फतेहगढ़ से मनीशा दलाल और अकालगढ़ गांव से कप्तान सिंह गोल्ड मैडलिस्ट हैं। इन दोनों को नौकरी मिली है और न ही गांव को विकास के लिए 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है मेरे हल्के में ग्रामीण क्षेत्र में एक निडानी स्पोर्ट्स स्कूल है वहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से खिलाड़ी तैयार किये जाते हैं और वे खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर गोल्ड मैडल प्राप्त करते हैं। उनको दी जाने वाली सारी सुविधायें सरकार ने बंद कर दी हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इन भावों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण से सहमत नहीं हूँ क्योंकि यह तथ्यों से मेल नहीं खाता। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी): सर, आपने मुझे इस सदन में जो बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर विकास की असत्य गौरव गाथा प्रस्तुत की है उस पर विचार रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सर, आज हमारा प्रदेश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आज प्रदेश पर लगभग इस साल के अन्त तक 52000 करोड़ रुपये का कर्जा हो जायेगा यानी हर आदमी के ऊपर 25000 रुपये कर्जा है। आज जो बच्चा हरियाणा प्रदेश में जन्म ले रहा है वह 25000 रुपये का कर्जा अपने सिर पर लेकर जन्म ले रहा है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) सर, हमारा फिस्कल डैफिसिट बढ़ रहा है। हमारा रेवेन्यू डैफिसिट बढ़ रहा है और जो फाईनैंगिएल डिस्प्लिन हमें एडेहर करना चाहिए और जो फाईनैंगिएल रिसर्पोन्सिबिलिटी एक्ट हमने पारित किया है जिसके तहत सन् 2012 तक हमें रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम उसको एचीव कर पायेंगे। सर, पर-कैपिटा इनकम के बारे में बताया गया है कि हमारे प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम बढ़ रही है और इसके बारे में ओर भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। जी.डी.पी. हमारा 9.6 प्रति शत है और औद्योगिक विकास दर हमारी 7.9 प्रति शत है। सर, पहले मैं पर-कैपिटा इनकम के बारे में बताना चाहता हूँ। सर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो पर-कैपिटा इनकम 1,09,227 रुपये होने की संभावना दी गई है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि आज हमारी पर-कैपिटा इनकम 1,09,227 रुपये है जो वास्तव में सही नहीं है। पहले ये जो आंकड़े हैं ये प्रदेश की उन्नति के प्रतीक नहीं हैं। Sir, this is the mean value of the total Income

of the State divided by the population of the State. सर, आप इसे ऐसा उदाहरण मान सकते हैं कि मान लो आपके पास 100 रूपये है और मेरे पास 10 रूपये है तो हमारी पर-कैपिटा इन्कम 55 रूपये होगी और मेरे 10 रूपये की वैल्यू 10 रूपये ही रहेगी 55 रूपये नहीं हो जायेगी। ये आंकड़े पूरी तरह से मिसलीडिंग हैं और इस तरह से प्रदेश को इसमें कोई ईनाम नहीं मिलता क्योंकि पहले नम्बर के इस प्रदेश में जिसमें गरीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल. परिवार राशन कार्ड बनाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आज पंचकुला जिले में राशन कार्ड बनाने के लिए संघर्ष करने वालों के जुलूस को हमारे अध्यक्ष लीड करके आये हैं। इस सरकार में लोग राशन कार्ड बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसी भी गांव में और किसी भी मौहल्ले में जब हम लोग जाते हैं तो लोग हमारे से सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बनवाने की बात करते हैं। हमारा प्रदेश गरीब और निर्धन हुआ है। ये जो आंकड़े है ये ऐसे है जो एन.सी.आर. और गुड़गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे बड़े धनी व्यक्ति जरूर है लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं लगाया जा सकता कि आज हमारा सारा प्रदेश धनी है या हमारे प्रदेश की बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है या उन्नति हुई है। ये आंकड़े वाजिब नहीं है। सर, जो पर-कैपिटा इन्कम के आंकड़े हैं वे उन 5 प्रतिशत लोगों के (16.00 बजे) हैं जिनके पास देश की 38 प्रतिशत सम्पत्ति है। बाकी के 95 परसेंट लोग जो है उनके पास 62 परसेंट सम्पत्ति है। Speaker Sir, gap is widening between the

haves and have-nots. सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जो 77 परसेंट पॉपुलेशन है वह प्रतिदिन 20 रुपये से कम कमाती है। भारत सरकार ने जो बी. पी.एल.का आधार प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से भाहर में 32 रुपये तक रोज कमाने वाला और गांव में 26 रुपये तक रोज कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इसके साथ-साथ इस बारे में भी बता दें कि जब सेंटर में इनकी सरकार थी उस समय यह रेंजों कितना था? (गौर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदय, इनमें यह बहुत बुरी आदत है कि जब भी कोई बात कहो तो ये कहते हैं कि कलकत्ता होता था तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि कल आदमी जंगल में रहता था और नंगा घूमता था तो इका मतलब यह नहीं है कि वह आज भी नंगा घूमे। उपाध्यक्ष महोदय, हम आगे की बात कर रहे हैं। (गौर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विज साहब, आप कंटीन्यू करें। (गौर एवं व्यवधान)

श्री नरेण्डा भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष: इसको रिकॉर्ड न किया जाये। नरेण्डा भार्मा जी, आप बैठिए। विज साहब, आप कंटीन्यू करें।

श्री मौहम्मद इलियास: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री नरे ा भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय,

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करें और उनको सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाए।

श्री उपध्यक्ष: हाउस में जो अनपार्लियामेंट्री भाब्द कहे गए हैं वे रिकॉर्ड न किए जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, विज साहब ने एक चिंता जाहिर की है और वह चिंता यह थी कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उनकी चिंता वाजिब है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और विज साहब की सहमति से एक बात कहकर अपना स्थान ले लूंगा कि एक जमाना था जब एक सरकार दिल्ली में इंडिया भाइनिंग का नारा लेकर आई और बहुत सारे लोक लुभावने वायदे इस दे ा की गरीब जनता में किए। यह सच है कि इस दे ा के अंदर आजादी के बाद गरीब ओर अमीर के बीच की खाई धीरे-धीरे बढ़ी है। जब दिल्ली में यू.पी.ए. की सरकार आई तो मनरेगा दिलाने के लिए 40 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा राि ा देने का काम किया गया। यू. पी.ए. सरकार के इस काम की तारीफ आपकी पार्टी ने भी की है

और दूसरी विपक्षी दलों ने भी की है। (विघ्न) इसी तरह दिल्ली की यू.पी.ए. की सरकार डा० मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में नैशनल रूरल हैल्थ मिशन लेकर आई जिसके तहत आखिरी गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम किया गया है। नैशनल रूरल डिवैल्पमेंट मिशन के तहत एक लाख करोड़ से अधिक की सबसिडी अलग-अलग फॉर्म में गरीब आदमियों तक पहुंचाकर आज यू.पी.ए. की सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि गरीब और अमीर की खाई को पाटा जाये जो बढ़ती जा रही है। हम इण्डिया भाईनिंग का चमकता चेहरा दिखाकर इस देश की गरीबी को छुपाना नहीं चाहते। हम इस देश की गरीबी और गरीबों को ऊपर उठाकर उन्हें स्वाभिमानी और सवालम्बी बनाकर एक बराबरी का दर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देने का प्रयास कर रहे हैं। (विघ्न)

डा० अजय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इनको 65 साल राज करते हुए हो गये और ये लगातार गरीबी को ऊपर उठा रहे हैं। (गौर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अजय जी को बताना चाहूंगा कि हम 65 साल की बात कर देंगे परन्तु ये लोग यह बात भूल जायेंगे जब इनकी सरकार थी तो ये लोग दस-दस रुपये गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ईजाफा किसानों को देकर उनको चलता कर दिया करते थे। (गौर एवं व्यवधान) एन.डी.ए. की इण्डिया भाईनिंग का क्या हुआ

गुर्जर साहब यह आपको पता है। अजय सिंह जी उस समय एम.पी. थे और ये भी इण्डिया भाईनिंग की सरकार में शामिल थे। इनके पांच सदस्यों के समर्थन से उस समय वह सरकार चलती थी। उसके बाद जब अजय जी उस सरकार को छोड़कर गये उसके बाद भी इन्होंने किसान के पूरे मूल्य के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि गेहूं और चावल का किसानों को पूरा मूल्य दिया जाये। उस समय दस-दस रूपये प्रति क्विंटल का भाव बढ़ाया जाता था। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उस समय अजय जी ने कभी अनुरोध नहीं किया कि किसान की फसल का मूल्य बढ़ाया जाये। अगर ये चाहते तो उस समय समर्थन वापिस ले लेते (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता उस समय इनकी कया मजबूरियां थी और ये क्यों एन.डी.ए. की सरकार को समर्थन देते रहे लेकिन सच्चाई यह है कि जब से सैंटर में यू.पी.ए. की सरकार आई तब से किसान की हालत बदली और डाक्टर मनमोहन सिंह तथा श्रीमति सोनिया जी की सरकार ने 72 हजार करोड़ रूपये का कर्जा एक कलम से किसानों का माफ किया गया। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से व्यवस्था बदलेगी और दे 1 में तबदीली आयेगी। उस तरह से नहीं आयेगी जैसे गुर्जर साहब कह रहे थे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदय, मे इतना ही कहना चाहूंगा कि—

तेरे हर सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा,
तेरे एक-एक लपज को मुकम्मल किताब कर दूंगा,
कह दो विरोधियों से थोड़ा इंतजार करें,
वक्त आने पर मुकम्मल हिसाब कर दूंगा। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मानसिकता में यही अंतर है। आदर और मित्रता की बात कहकर ये विरोध और प्रतिरोध के नजरिये से देखते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक भोर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं मुझे बीच में इन्ट्रप्श न किया जाये। सर, 6 महीने के बाद सै न हो रहा है और केवल 8 सीटिंग्ज रखी गई हैं इसलिए जो 400 प्र न लगे हैं वे पूरे लिस्ट नहीं हो रहे। इस बारे में मैं उपाध्यक्ष महोदय सुझाव देना चाहता हूँ और आप कर सकते हैं कि जितने भी हमारे तारांकित प्र न हैं जो लग नहीं पाते वे एक उनको अतारांकित कर दिया जाये लेकिन विभाग की तरफ से जवाब दे दिया जाये। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज डेमोक्रेसी में हालत यह हो गई है कि हमारे दे ा में ओर प्रदे ा में आफिसर्ज रिप्लाइ नहीं देते। ऐसी हालत है कि या तो हमारा प्र न लगता ही नहीं और लगता भी है तो उसका जवाब नहीं आता है अगर किसी का उत्तर भी आ जाता है तो उस पर अमल नहीं होता। इस बारे में मैं

कुछ एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा कि मैने सदन में कुछ प्र न उठाये और उनका 'हां' में उत्तर आया। (विधन)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर विधान सभा सचिवालय की कार्य प्राणाली के बारे में श्री विज को किसी प्रकार की कोई रिक्वायत है तो उसके बारे में वे आपको लिखित में दे सकते हैं क्योंकि इस समय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है न कि विधान सभा सचिवालय का मामला इस समय चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अनिज विज जी, आप कृपया गवर्नर एड्रेस पर ही बोले।

श्री अनिल विज: डिप्टी स्पीकर सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि हम सब यहां बैठकर जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। जैसे सदस्यों को सदन में आवासन दे दिया जाता है। किसी सदस्य द्वारा कोई विषय उठाने पर सरकार द्वारा उस बारे में आवासन दे दिया जाता है लेकिन उस समय कोई अमल नहीं होता यह बात भी ठीक है कि इस बारे में विधान सभा में आवासन समिति का गठन भी किया हुआ है लेकिन वह तो किसी भी मामले को 5 से 10 साल के अंदर देखती है इतने लम्बे समय के बाद तो बहुत देर हो चुकी होती है। पिछले सत्र के दौरान मेरा अम्बाल कैंट में हाउस टैक्स

की रिकवरी के बारे में क्वै चन था। मंत्री जी ने तब मुझे हाउस में यह कहते हुए आ वासन दिया कि आप बिल की कॉपी मुझे दे देना मैं उसे देख लूंगा कि ये बिल किसने और कैसे दिये हैं। अगर गलत बिल इ यू हो गये होंगे तो उन्हें वापस ले लिया जायेगा और अगर किसी ने बिल जमा करवा दिये होंगे तो उस अमाउंट को आगे के बिलों में एडजस्ट कर दिया जायेगा। यह इस सदन में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था लेकिन इसके बावजूद किसी ने वे बिल वापिस नहीं लिये और इन बिलों की रिकवरी के लिए सारे के सारे भाहर में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी के नोटिस जारी कर दिये गये। इस सदन में दिये गये आ वासनों के बारे में सरकार क्या एक न लेती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह आ वासन दिया था कि 1857 की जो क्रांति अम्बाला छावनी से आरम्भ हुई थी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: अनिल विज जी, अब आप कृपया गवर्नर एड्रैस पर आ जायें।

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब हमें कही और बोलने नहीं दिया जाता तो जब मौका मिलेगा तभी हमें सारी बातें बोलनी पड़ेगी। हमें अपने हल्के की बात भी करनी होती है और सदन की बात भी बोलनी पड़ेगी। हमें अपने हल्के की बात भी करनी होती है और सदन की बात भी बोलनी होती है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कर रहा था कि

मुख्यमंत्री जी ने 10 मार्च, 2010 को सदन के अंदर आ वासन दिया था कि अम्बाला छावनी में 1857 की आजादी की लड़ाई की जो पहली क्रांति हुई थी उसके भाहीदों की याद में अम्बाला कैंट में एक मैमोरियल बनाया जायेगा लेकिन अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तीन बार जमीन सुनिश्चित करने के लिए तारीख तय की गई लेकिन उससे आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि सरकार के पास भाहीदों के लिए समय ही नहीं है। इसी प्रकार से इण्डियन ऑयल के डिपों को रिफिट करने की बात कही गई थी जिसके ऊपर यहां पर 'हां' में जवाब दिया गया था लेकिन वहां पर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। इसी प्रकार से वैट की बात कही गई थी कि सिलैण्डर से वेअ हटाया जायेगा लेकिन इस बारे में भी अभी तक कोई काम नहीं किया गया जबकि सरकार द्वारा भाराब से वैअ कुछ कम किया गया है। इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से हमारे भाहर में जो साइंटिफिक इण्डस्ट्री है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। Sir, Ambala was known as a city for scientific goods. जो कि आज के समय में पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे नहीं है अगर वे यहां बैठे होते तो जरूर कुद रिलीफ देते। इस इण्डस्ट्री को वैट से रिलीफ की आवश्यकता है क्योंकि बाकी प्रदेशों में या तो इस इण्डस्ट्री पर वैट नहीं है और कहीं है भी हो तो वह मात्र 4 प्रतिशत जबकि हमारी स्टेट के अंदर यह टैक्स 12 प्रतिशत है। मैं चाहता हूं कि इस टैक्स को खत्म किया जाये

ताकि अम्बाला की जो साईटिफिक इण्डस्ट्री है, जिसके कारण अम्बाला की सारे वि व में अपनी वि ेश पहचान है, उसको बचाया जाये। जब इण्डस्ट्री की बात आयेगी उस समय इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। यह छोटी सी बात मैने पहले कह दी है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो सारे प्रदे ा के व्यापारियों के ऊपर जो फार्म 38 है उसे अगर खत्म किया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी और अगर सरकार उसको लिमिट 25 हजार है और सभी व्यापारी इसकी मांग कर रहे है कि उसकी लिमिट बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी जानी चाहिए। उपध्यक्ष महोदय, आज प्रदे ा में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल हुआ है। मंत्री जी इस बात को अन्यथा न ले क्योंकि मैं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। जिस दिन से इस सरकार ने प्रदे ा की बागडोर सम्भाली है तब से क्राइम रेट डबल हो गया है। 2005 में जहां रेप के 461 थे वही आज के दिन 717 हो गये है। इस प्रकार से 2005 किडनैपिंग के 493 मामले थे जो कि आज 950 हो गये है। 2005 में अगर चोरी घटानाएं 8649 होती थी जो कि आज 16234 हो गई है। 2005 की बात की जाये तो 2005 में डकैती के 88 मामले थे जो कि आज बढ़कर 146 हो गये है। इसी प्रकार से अगर मर्डर की बात की जाये तो 2005 में 782 केस थे। (तोर एवं व्यवधान)

श्री नरे ा भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जाये कि अपराधियों को संरक्षण कौन देता था? आपको सभी सदस्यों की

भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। कभी विज साहब गालिब बनकर खड़े हो जाते हैं और कभी बड़ी-बड़ी भूमिका बाधते हैं। बाकी सदस्यों को भी तो बोलना है। ये गवर्नर ऐड्रेस पर तो एक भाब्द भी नहीं बोल है। ये रैली की तरह से भाषण कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल जी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकार्ड ऑकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ हालांकि यह विडम्बना है कि पुलिस विभाग ने 2005 के बाद आपनी वेबसाईट पर इन ऑकड़ों को अपडेट नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि यह गलत चीज है और यह लोगों तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये ऑकड़े मैंने हासिल किये हैं और ये करेक्ट ऑकड़े हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। सर, मेरे काबिल दोस्त श्री अनिल विज जी सारी व्यवस्था के ऑकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पे 1 करनेका प्रयास कर रहे हैं। वे यह भूल रहे हैं कि जब ये भी 1999-2005 में उस सरकार का हिस्सा थे और उसके बाद जिन्होंने इनकों बीच में ही छोड़ दिया और अब ये दूसरी जगह चले गये हैं और अब की बार हरियाणा में इनकी पार्टी किसके साथ जायेगी इस बात कोई फैसला नहीं हुआ है। There was a complete ban on registration of FIR during the Government when Shri Anil Vij's party was part of power in Haryana. An FIR could not be the consent of those in power at the first time, we have permitted it. crimes and of FIR (Interruptions) For the First time, we

have permitted it Crimes and criminals were given protection at that point of time. I am saying on record with some sense of responsibility that those who were convicted for murder, those who were convicted for NDPS, were released by the Cabinet. at that point of time, Such a shameful act. They were released by the Cabinet. Those who were convicted under NDPS Act right upto the Supreme Court. those who were convicted for molestation charges. those who were convicted for murder and those who were convicted for dacoity, were released by their Government of which Shri Anil Vij was a part. On a top of that, non-criminals were kept in police custody in jails. The then people who were in power and some of them who are convicted by Courts in Rohtak Jail and other Jails. That was the atmosphere. Crimes and criminals were given protection and we have to leave Haryana and Ch. Bhupinder Sing Hooda led Congress Government ensures that the law and order and the rule of law prevails in the State, that is what we have done. Sir.

श्री उपाध्यक्ष: विज साहब, कंकल्यूड कीजिए।

श्री अनिल विज: सर, मेरा सारा टाईम तो ये खा जाते हैं। सर, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अपने चारों साथियों का समय भी ले रहा हूँ। सर, मैंने रिकॉर्ड से आँकड़े बताने की कोशिश की है डिप्टी स्पीकर सर, मैं क्राईम के बारे में बात कर रहा हूँ। सर, रोजना घटनाएँ हो रही हैं, अगर एवरेज लगायें तो रोजाना तीन कत्ल होते हैं, दो बलात्कार होते हैं, एक लूट की घटना होती है और एक दहेज हत्या होती है। अभी कई

चर्चित कांड भी हुए है। करनाल में पूर्व सरपंच की हत्या का कांड, कुरुक्षेत्र में स्वीटी हत्या कांड, रोहतक में मुख्यमंत्री की कांस्टीच्यूएं गी में सी. जे. एम. के घर का ताला तोड़कर चोरी की गई। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जयवीर सिंह): डिप्टी स्पीकर सर, 6 फरवरी को एक गाड़ी पकड़ी गई जिसका नम्बर और फोटोग्राफ भी साथ है, वह वेरना गाड़ी है, उस पर लालबती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है। I.N.L.D. और उस गाड़ी पर हरी झंडी लगी हुई थी। मेरे पास एक आई. आर. की कॉपी है। (गोर एवं व्यवधान) (इस समय माननीय अध्यक्ष पदसीन हुए।)

Mr. Speaker: Vij Ji your time is getting over.

श्री अनिल विज: नहीं सर, मुझे तो बोलने ही नहीं देना है। Sir, my time has been eaten away by all these Members.

Mr. Speaker: You are speaking for the last 28 minutes.

श्री अनिल विज: सर, मैं दो मिनट भी नहीं बोला हूँ। मैं अपने चारों मैबरों का टाइम लेना चाहता हूँ (गोर एवं व्यवधान)

श्री नरे ग. भार्मा: ये प्रजातंत्र का हनन कर रहे हैं और लोगों के समय को बर्बाद कर रहे हैं, पर अपनी बात थोप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपने चारों सदस्यों का भी टाइम ले रहा हूँ जबकि एक बार भी उन्होंने इसका इस बात के लिए समर्थन

नहीं किया कि हम उसको टाईम दे रहे हैं। ये अपनी बात जबरदस्ती थोप रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप इनको address करते हुए ऑनरेबल मेंबर कहिये, माननीय सदस्य कहिये, ये कहने का क्या मतलब है?

श्री नरे । भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: You have two more minutes please.

श्री कृष्ण पाल गर्जर: अध्यक्ष महोदय, अभी अनिल विज जी बोले ही कहां है।

श्री अनिल विज: सर, प्रदेश की कानून-व्यवस्था का दिवाला निकाला हुआ है। मैंने आंकड़ों सहित बात रखने की कोशिश की है। हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री जी बैठे हैं। हमारे प्रदेश की सड़कों का भी बुरा हाल पड़ा है। वर्ष 2010 में सारे प्रदेश में 10934 एकसीडेंट हुए हैं, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसमें 4724 लोगों की जान गई है। जिन लोगों की जान गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेवारी ओटनी पड़ेगी। मेरा सैपरेट क्वेश्चन भी था। साहा स्कूल का इंसीडेंट भी हुआ है, पानीपत में भी इंसीडेंट हुआ है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इंसीडेंट्स हुए हैं जोकि एक गंभीर चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, यह बातें अगर हम इस महान सदन के अंदर नहीं रखेंगे तो और कौन सा मंच है जहां हम इन बातों को रखें? क्या कमी

सरकार इनके ऊपर विचार करेंगी? आज इंपलॉइज की बात की गई है। आज प्रदेश में नौकरियों की जिस प्रकार सतिजारत हो रही है वह सबको सामने है। नये लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर रही आज तो पुराने लगे हुए कर्मचारियों का भी भाषण किया जा रहा है जिसका थोड़ा सा चित्र मैं आपका दिखलाना चाहता हूँ। सरकार ने गैस्ट टीचर भर्ती कर लिये। एक नई टर्म निकाल दी गैस्ट टीचर की। अध्यक्ष महोदय, आज उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है कि where they will go? उनका क्या होगा? आज उनके वेतन में भी बहुत बड़ी भिन्नता है। आज जो एक गैस्ट टीचर जे.बी.टी. है उसको 14 हजार रूपये मिलते हैं और जो रैगूलर है उसको 28 हजार रूपये मिलते हैं। अध्यक्ष को उनको नौकरी पर रखा भी जायेगा या नहीं। आज कई गैस्ट टीचर तो 50 साल की उम्र क्रास कर चुके हैं।

Mr. Speaker: Hon'ble Member, the matter is in Court. Please do not comment on this.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, कोर्ट केस तो खत्म हो गया है। उनका तो अभी निपटान हुआ भी नहीं था कि सरकार ने एक लाख पात्र अध्यापको की फौज और तैयार कर ली। वे भी रोजना भटकते रहते हैं। वह बेचारे कहां जायेगे और कब उनको रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, कल कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल भी हुई कि उन्हें पक्का किया जाये।

Mr. Speaker: Thank you very much. You have finished your time. आपके 32 मिनट हो गये।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, 32 मिनट तो दूर की बात अभी तक तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर पूर्वक बोल रहा हूँ और आपको मेरी बात सुननी चाहिए। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मुझे जो भी मिनट्स मिलते हैं उसमें से सारे मिनट्स तो यह नरे । भार्मा खराब कर देता है।

श्री अध्यक्ष: विज साहिब, आप ऐसे मत बोलिये इनको माननीय सदस्य कहिये।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, अभी सी.पी.एस. साहिब ने कुछ बिंदुओं/पॉइंट्स पर विस्तार से अपना जवाब दिया जोकि उनका राईट है। जो उन्होंने बोलने में टाइम लिया उस टाइम को मेरे टाइम से काटना चाहिए और इसके साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम लिखकर दिया है कि जो टाइम हमारी पार्टी को बोलने के लिए मिलेगा उस सारे टाइम पर मैं ही अपने दल की तरफ से बोलूंगा और बजट पर जो चर्चा होगी उस पर हमारी पार्टी के दूसरे सदस्य बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: विज साहिब, क्या आप चेयर का निर्देशित कर रहे हैं?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूँ यह तो हैल्दी ट्रेडींग है और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: सम्मनित सदस्य, आपने मुझे निर्दिष्ट किया है। You cannot direct me.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउस के कास्टोडियन हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है विज साहिब, बोलिये और केवल दो मिनट में ही कम्पलीट कीजिये, दूसरे मेंबर्स को भी बोलना है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बहुत बोलना है। मुझे इम्प्लॉय की बात कहनी है जिनके भाविश्य को खराब किया जा रहा है। मैं भूना भुगर मिलज की मात करना चाहता हूँ जोकि 158 एकड़ में मीनरी युक्त है उसको 40 करोड़ रुपये का चैक आया वह बाऊंस हो गया। आज भूना भुगर मिलज के 500 कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, वे बेचारे कहां जायेंगे? आज उनका भविश्य अंधकारमय है। अध्यक्ष महोदय, चह जो पी.पी.पी. और फ्रॉंचाईज का सिस्टम चलाया गया है (तोर एव व्यवधान)

श्री नरेण्डा भार्मा: स्पीकर सर, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ कि एम. आई. टी. सी. के जो कर्मचारी हटाये थे वे कहां जायेगे? (तोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास: स्पीकर सर, नरे जी बगैर आपकी इजाजत के कैसे बोल रहे हैं? बोलने के लिए खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर हाथ उठाकर परमिशन ली जाती है?

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आपको कम से कम बैठे-बैठे हाथ उठाकर यह तो कहना चाहिए था कि मैं बोलूंगा।

श्री नरे जी भार्मा: स्पीकर सर, माननीय साथ बोल रहा था और मैंने अपनी इजाजत ली है।

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आप बैठ जाइये।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो ठेकेदारी प्रथा है, यह खत्म की जाए।

Mr. Speaker: Vij Sahib, Plesase take the business the House Seriously.

श्री अनिल विज: सर, मैं सीरियसली ही ले रहा हूँ। यह जो ठेकेदारी प्रथा है इससे ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारीयों का बहुत भाषाण हो रहा है। सर, मैं आपके समक्ष पंचकूला का ई.पी. एफ. स्कैम रखना चाहता हूँ। जो सफाई कर्मचारी नगर परिशदों में होते हैं उनका ई.पी.एफ. कटता है, वह राशि उनके खातों में जमा होनी चाहिए लेकिन ठेकेदार उस राशि को संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा नहीं करवाते हैं। पंचकूला का मामला तो सामने आया है। पंचकूला ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर भाहर में ऐसा हो रहा है। इसमें 320 रुपये सफाई

कर्मचारी के कटते हैं और 80 रुपये कंट्रैक्टर ने अपनी तरफ से जमा कराने होते हैं। 500 कर्मचारी हैं और एक साल में कुल मिलाकर यह राशि 43 लाख 20 हजार रुपये बनती है। यह तो अकेले पंचकूला की बात है इस प्रकार हरियाणा की किसी भी कमेटी में यह पैसा जमा नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत भारी भोशण कर्मचारियों का हो रहा है। इसी तरह से बिजली बोर्ड में जो लाइनमैन लगे हुए हैं उनकी ड्यूटी के वक्त किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलते समय सदन में कोई असत्य बात न कहें। हमारे विभाग में यदि कोई लाइनमैन ड्यूटी के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जाती है।

Mr. Speaker: Anill Vij Ji, You have finished your time. Please conclude your speech. I am calling next speaker to speak.

श्री अनिल विज: सर, मैं अब हल्के की दो बातें कह देता हूँ। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की माली हालत बहुत खराब है। ओल्ड-ऐज पेंशन नहीं मिल रही है। मैं दो बातें और करूंगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्ति विवाह

भानुन योजना को सरकार द्वारा चलाए हुए लगभग डेढ़ साल हो गया है। लोगों के विवाह के बाद बच्चे भी हो गए हैं लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला।

शिक्षा मंत्री (श्रीमति गीता भुक्कल मातनहैल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि उनकी नॉलेज में यदि कोई ऐसा केस लम्बित है तो जरूर बता दे, हम उनके खाते में पैसा डाल देंगे और माननीय सदस्य की समस्या का जरूर समधान करेंगे।

श्री अनिल विज: सर, गवर्नर साहब के ऐड्स पर श्री विनोद भार्मा जी ने यहां प्रस्ताव मूव किया था और उस पर बोलते हुए उन्होंने उनेको बातें कही थी, उनके साथ ही यह भी कहा कि अम्बाला में आई. एम. टी. की सीपना पर दोबारा विचार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से वहां के लोगों ने संघर्ष करके पंजोखरा में जो आई.एम.टी. लग रही थी, उससे जान छुड़ाई। इसके पक्ष में वे कहते हैं कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। अगर रोजगार मिलता है तो वे अपने हल्के में आई.एम.टी. लगवा ले। मेरे हल्के का क्यों ना आ कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विज साहब, अब आप लास्ट लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, ऐग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी बातें यहां पर की गईं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, अप अपने हल्के की बात करिए। आप अम्बाला कैंट की बात नहीं कर रहे हैं। वहां के लोगों क्या सोचेंगे। प्लीज, अब आप बैठ जाइए।

श्री अनिल विज: सर, लॉ एण्ड आर्डर का मामला है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब सदन चल रहा है और मामनीय मंत्री और मुख्यमंत्री सदन से बाहर ब्याना देते हैं, सदन गरिमा का ध्यान रखते हुए उनको जो कहना है वह सदन के अन्दर कहना चाहिए। हमारे कैप्टल यादव साहब ने कहा कि रिजर्वे उन नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से कल पीपली में किसानों की बात हुई है। We have a right to know, Sir. क्या बात हुई है? कब यह matter resolve होगा? कब प्रदेश में भान्ति होगी? यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। आपका मैटर कम्प्लीट हो गया है। आपको बजट पर फिर बोलने का समय देंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराना, एस. सी.): स्पीकर सर, 23 फरवरी, 2012 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण पढ़ा है उसको पूरा पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि सरकार ने बड़े बलग-बाग दाये किये कि आज हरियाणा प्रदेश में किसानों को बहुत बिजली दी जा रही है, उद्यमियों को बहुत बिजली दी जा रही है। स्पीकर सर, आज प्रदेश के अन्दर

बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां सरकार किसानों को 20-22 घण्टे बिजली देने की बात करती है वहां किसानों को 4-6 घण्टे बिजली भी नहीं मिलती है आज की मौजूदा सरकार ने सबसे ज्यादा बिजली का प्रोड्यूस करने का दावा किया है। पिछली बार सदन में आपने मुझे कहा था कि मैं कई सुझाव दिया था कि दीन पर अमल जरूर करेगी उस समय भी मैंने इस सदन में एक सुझाव दिया था कि दीन बन्धु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर की 300-300 मैगावाट की दो यूनिट्स हैं जो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार के समय में उसका टैण्डर लगाया गया था लेकिन उस टैण्डर का ऐसी कम्पनी को टैण्डर दे दिया जिसके द्वारा सारी मीनिंगरी चाईना से मंगाई गई। पिछली बार एक यूनिट को इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रैसिपिरेटर को डकट टूट कर नीचे पड़ गया था इसलिए इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रैसिपिरेटर को ठीक करवाने के लिए और उस दौरान जो लौस हुआ उसको मिलाकर कम से कम 500-700 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान हुआ। अब की बार 25 दिसम्बर 2011 को दूसरी 300 मैगावट दो नम्बर यूनिट में जो टरबाईन होती है उसमें 540 डिग्री का टैम्प्रेचर का प्रेशर एल.पी. और एच.पी. गलैण्ड में जाता है जब इस टरबाईन के अन्दर चला गया जिससे की ड्रेन में जो पानी था वह वैक्यूम प्रेशर से टरबाईन के अन्दर चला गया जिससे टरबाईन का रूटर खराब हो गया उसके बाद स्टीम को कन्डैन्सड किया जाता है है लेकिन उसके नीचे जो ड्रेन लगी होती है वह यू आकार लगी हुई होती है जबकि होना यह चाहिए

कि एच.पी. गलैण्ड की ड्रैन डायरेक्ट जाए और एल.पी. की डायरेक्ट जाए। जब टरबाईन को रोलिंग किया गया है तो कम्प्रेसर से उसमे पानी एन्टर कर गया और रूटरन खराब हो गया। उस रूटर को ठीक कराने के लिए 25 सितम्बर से सरकार की आंखे नहीं खुली और सरकार को 75 लाख यूनिट पर डे का और उत्पादन न होने के कारण कम से कम 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 25 सितम्बर, 2011 से जनवरी, 2012 तक इस टरबाईन का रोलर ठीक नहीं करवाया गया जिस पर 2 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। अगर नया रूटर लेकर आयेगे तो कम से कम 100 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इसके अलावा स्पीकर सर, उसका जो पी.एल.एफ. हुआ वह वर्ष 2010-2011 में 62.6 प्रति ता और वर्ष 2011-12 से 41.14 प्रति ता हुआ है इस प्रकार जनरेटन बहुत कम हुआ है। इसी प्रकार से पानीपत थर्मल पावर प्लांट का 8.11.2011 को इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रैसिपिरेटर होता है उसका डाक्ट भी टूटकर नीचे गिर गया क्योंकि उसके अन्दर ऐंटा भर गई जबकि एनवार्यनमेंट और फोरेस्ट मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने यह कहा है कि इस ऐंटा का 100 प्रति ता यूटिलाईजेटन होना चाहिए लेकिन वहां एम्बुजा सीमेंट फ़ैक्टरी जोकि कम रेट पर ऐंटा उठाती थी और ऐंटा प्लांट का आपरेटन करती थी और इस इस प्लांट की मेन्टीनेंस का सारा खर्च वहन करती थी सरकार ने उस कम्पनी को दौड़ा दिया। अब थर्मल प्लांट की मेन्टीनेंस पर करोड़ों रुपये खर्च होता है परन्तु ऐंटा का यूटिलाईज न होने के कारण ई.एस.पी. टूटकर

नीचे गिर गया। फिर सरकार ने सोचा कि प्रदेश के लोग इस बात के लिए उन्हें टोकेंगे इसलिए इन्होंने एक चालाकी की कि जो स्टैंड बाई लाइन होता है, उस स्टैंड बाई लाइन को चलाया और उसमें तेल फायर किया। अध्यक्ष महोदय, उसमें दो करोड़ का तेल जलाया गया है और 12 करोड़ का हमारा जैनरे इन लोस हुआ। उसके बाद टरबाइन में वायबरे इन आने के कारण टरबाइन भी बैठ गई और वह यूनिट आज तक बंद पड़ा है और इससे एक बहुत इंसिडेंट वहां हो सकता है। पानीपत थर्मल प्लांट पर ऐ 1 डाईक है जिसका 3 किलोमीटर का रेडियस है। सातवें-आठवें यूनिट की सारी ऐ 1 उसमें जाती है। पूरे हिन्दुस्तान में कोई भी ऐ 1 डाईक 4 मीटर से ज्यादा ऊपर तक नहीं उठाई गई लेकिन इस सरकार में पानीपत की थर्मल प्लांट की उस ऐ 1 डाईक की ऊंचाई 20-22 मीटर है और 8 मीटर तो उसमें केवल राख से वाइडनिंग किया गया है। आज उसके यह हालात है कि वह ऐ 1 डाईक ऐ 1 से ओवर फली हो चुका है और कभी भी वहां से लीकेज होने के बाद वहांपर बहुत बड़ी कैज्युलिटी हो सकती है। सुताना गांव उसके साथ पड़ता है। सुताना गांव की 300 एकड़ जमीन में उस ऐ 1 डाईक से सेम आ चुकी है। वहां पर कई सालों से फसल नहीं हो रही है। वहां के किसान बार-बार सरकार से कहते हैं कि हमारी जमीन एक्वायर कर ली जाए लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिजली पैदा करने के बाद जो सुचयाड़ होता है वह खुखड़ाना और सुताना गांव की 55 एकड़ जमीन में आ जाता है और वहां के

किसान 25 रो रहे है कि हमें इसके लिए मुआवजा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप कभी वहां से गुजरें तो देखें कि वहां एक तलाब बना हुआ ह। (विघ्न) 1979 में पहली यूनिट ने जैनरे इन भुरु किया था (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकि इन फौजी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि माननीय साथी ने यह कहा कि 25 साल से किसान वहां रो रहा है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये 5 साल तक मौन करके चले गये इन्होंने उस समय किसान की सुध क्यों नहीं ली? (गोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, खुखडाना गांव उसके साथ अटैच है और वहां ऐ ग आ जाती है इसलिए चौधरी ओम प्रका ग चौटाला ने 25 एकड़ जमीन गिफ्ट करने के लिए सैव इन 4 का नोटिफिके इन किया था। हमारी सरकार जाने के बाद उस स्कीम को इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और मजबूरन लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से अब डायरैव इन हुई है। चौधरी ओम प्रका ग चौटाला ने गांव के लोगों को सहूलियतें देने के लिए उस जमीन को गिफ्ट करने के लिए सैव इन 4 का नोटिफिके इन किया था।

श्री रामकि इन फौजी: उस समय किस भाव में जमीन को गिफ्ट करने का डिसेजन हुआ था?

श्री कृष्णा लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 4 के तहत उस समय गांव को रिफ्ट करने के लिए जो रेट होता था वह किसान को मिलना था। उस समय का जो मार्केट रेट था वह किसान का मिलना था।

श्री अध्यक्ष: उस समय क्या रेट था?

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, उस समय कम से कम 4-5 लाख रुपये प्रति एकड़ एग्रीकल्चर का रेट था। यह वर्ष 2000 की बात है और 2000 के बाद महंगाई बहुत बढ़ी है। जमीनों के रेट बहुत बढ़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गांव के लोगों को सहूलियतें देने के लिए गांव को रिफ्ट करने के लिए के लिए उस जमीन का सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि चूंकि यह बड़ा सैसटेटिव मामला है इसलिए मंत्री जी को वहां तुरंत दौरा करना चाहिए नहीं तो वहां बहुत बड़ा सैसडेंड हो सकता है इसके इलावा मैंने एक सवाल मैं एक रिक्वेस्ट यह भी की थी कि उस गांव 700 एकड़ जमीन ऐक्टिव ड्राईक में चली गई जिसमें से 300 एकड़ जमीन सेम में है। किसनों के पास अब खेती करने के लिए कम जमीन बची है वहां डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा है जहां लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। लोगों बार-बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे इस डेढ़ किलोमीटर टुकड़े का रास्ता बना दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा उन लोगों

की भावना की कद्र करते हुए वह टुकड़ा अवश्य बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में डी ग्रेड का कोयला मिलना चाहिए लेकिन एफ ग्रेड का कोयला कमी है। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स की प्रोड्यूसिंग डाउन होने की बात है उसका मेन कारण कोयले की कमी है हमारे थर्मल प्लांट्स में डी ग्रेड का कोयला मिलना चाहिए लेकिन एफ ग्रेड का कोयला मिल रहा है इसमें क्या घोटला हो रहा है कि हमारे खेदड़ प्लांट की डेली कैपैसिटी 20 से 25 हजार टन कोयले की है। 9 रैंक प्रतिदिन कोयला लगता है और नार्मल के मुताबिक 21 दिन का कोयला एडवांस में होना चाहिए लेकिन वहां एक दिन का कोयला भी एडवांस में नहीं होता है। इसी तरह से पानीपत थर्मल प्लांट की कैपैसिटी 25 से 28 हजार टन कोयला प्रतिदिन की है। वहां 10 रैंक प्रतिदिन कोयला लगता है। वहां डेली जो कोयला जाता है वह यूज हो जाता है इसी तरह से यमुनानगर थर्मल प्लांट की कैपैसिटी 15 हजार टन कोयला की है वहां भी कोयला नहीं मिल रहा। खेदड़ थर्मल प्लांट में मानंदी कोल, उड़ीसा से कोयला आता है जिसमें 48 से 50 प्रतिशत राख है। इसको कोल कम्पनीज में पानी से वाश करके लाया जा रहा है। पानीपत थर्मल प्लांट में वैस्टर्न कोल लिमिटेड कम्पनी से कोल आता है उसमें से 32 प्रतिशत राख है। इसी तरह से यमुनानगर में सेंट्रल कोल लि0 से कोयला आता है और उसमें 35 प्रतिशत राख है। अध्यक्ष महोदय, जो हम इण्डोनेशिया से कोयला मंगवाते हैं उसमें क्लोरिफिक वैल्यू 5600-5700 होनी चाहिए। पूर्व एम.डी. ने श्री राम

लैब से उसकी कर क्लोरिफिक वैल्यू चैक करवाई जो कि 4100 निकली। इस तरह से घटिया कोयला लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोयले की खरीद में जो गड़बड़ियां हो रही है यहां मैं उसका जिक्र कर रहा हूं इस तरह मंत्री जी ध्यान दें। एक रिटायर्ड बी.एस. अहलावत को निगम का चीफ आपरे इन फयूल मैनेजमेंट का इंचार्ज लगा रखा है। उस पोस्ट पर एक सरकारी अधिकारी को लगाया जाये तो गड़बड़ी करने पर उसे डर रहेगा। एक रिटायर्ड आदमी लगा रखा है जो मजे काट रहा है। अध्यक्ष महोदय, खेदड़ प्लांट के अंदर क्लोरिफिक वैल्यू 4000 की बजाय 2800-3000 के करीब है और यमुनानगर में क्लोरिफिक वैल्यू 4000 की बजाय 3400 आ रही है। पानीपत में क्लोरिफिक वैल्यू 4100 की जगह 3500-3600 आ रही है। इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोयले की कंजम्प इन की बात है वर्ष 2003 में 0.744 किलो ग्राम कोयला प्रति यूनिट कंज्यूम होता था और अब 0.168 किलों ग्राम कोयला प्रति यूनिट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए इस मामले को ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें करोड़ों रुपये लोगों की जेबों में जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा मामला है इसकी मंत्री जी इंक्वायरी करवाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यमुना नगर ओर खेदड़ थर्मल प्लांट्स में रिलायंस कंपनी ने कर्मचारीयों की कॉलोनी बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये देने के लिए कहा था लेकिन आज तक कॉलोनी नहीं बनी। सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन कॉलोनी नहीं बनी है। वहां प्लांट में यदि कोई खराबी

हो जाती है तो इंजीनियर हिसार से आता है जिसमें 3-4 घण्टे का समय बरबाद हो जाता है और प्लांट डाउन रहते हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात करती है लेकिन सरकार ने दस दिन पहले इस बारे में पॉलिसी बनाई है। पहले उद्योगों के लिए 70 किलोवाट तक का ट्रांसफार्मर निगम लगाता था और सारा खर्चा निगम ही वहन करता था लेकिन अब पॉलिसी के तहत यह कर दिया गया है कि जिन उद्योगों में 50 किलोवाट तक का लोड है वे अपना अलग से ट्रांसफार्मर लगवायें और ट्रांसफार्मर का सारा खर्चा उद्यमियों को ही उठाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक ट्रांसफार्मर पर एक लाख से डेढ़ लाख रुपये खर्च होता है और सामान का अलग खर्च होगा। सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल तक जिस उद्यमी ने अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया उसके बिल से 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सैल्फ फाईनैस स्कीम के तहत किसानों को ट्यूबवैल्ज के कर्नैकान देने थे, किसानों को पैसे भी जमा करवाये हुए कई कई साल हो गये लेकिन कर्नैकान नहीं दिए गए हैं। बिजली से संबंधित ही मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले सैकड़ों वर्षों में मंत्री जी ने आवेदन दिया था कि प्रदेश में जहां कहीं भी चाहे बाहर है या गांव है अगर उनमें लोहे की पोल होंगे तो उनको बदल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी आज के दिन देखते होंगे कि बहुत से गांवों और भाहरों में लोहे की पोल लगे हुए हैं जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और काफी कैल्यूलिटी हो जाती हैं इसलिए सरकार की तरफ से जी

हाऊस में ए योरेंस आया है। उसके मुताबिक तुरंत लोहे के पोल हटावाकर पत्थर के पोल लगवाये जायें इस प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक उरलाना कला गांव है जो बहुत बड़ा गांव है उसके अंदर 33 के.वी.ए. के पॉवर हाऊस के अंदर 6.3 और 8 एम. वी.ए के दो ट्रांसफार्मरज है, उनको अपग्रेड करके 10 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर लगाये जाये जिससे इलाका वासियों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो सके। यह बात माननीय मंत्री जी के नोटिस में भी है। इस बारे में हाऊस में जो ए यारेंज आया था उसको दो वर्ष हो चुके है लेकिन अभी तक भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ एक बात मैं यह बताना चाहूंगा कि गांव सीक के अंदर 132 के.वी.ए के पांवर हाऊस का ए योरेंस भी हाऊस के अंदर आ चुका है लेकिन अभी तक वहां पर भी काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से 220 के.वी.ए. का पॉवर हाऊस इसराना के पास बिजारा गांव में लगवाने को ए योरेंट आया था लेकिन आज तक वहां पर काम चालू नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मरज लगवाये जाने की अप्रुवल है लेकिन आज तक भी ट्रांसफार्मरज अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार से नारा गांव के अंदर 2.10 एम.बी.ए. के दो ट्रांसफार्मरज मंजूर है और सरकार की तरफ से अप्रुवल आ चुकी है लेकिन आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदे 1 में जब पांच साल में चुनाव आते है तो कहती है कि हम गरीब के हितैशी है। आज की प्रदे 1 सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदे 1 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अधिकारी व कर्मचारी है उनके बैकलॉग को कम्पलीट करने के लिए

भी कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उनकी कुल संख्या 2694 और उसमें 539 आरक्षित हैं और लगे हैं 133 जोकि टोटल का 5 परसेंट है। इस प्रकार से बैकलॉग है 406 का। इसी प्रकार सैकण्ड क्लास में 10 हजार 611 टोटल पद हैं और लगे हुए हैं 2122 इनमें से 988 आरक्षित हैं जो कि 9.3 प्रति शत है और बैकलॉग है 1134 का। इसी प्रकार से क्लास थ्री में कुल पद 1 लाख 96 हजार 447 हैं जिनमें से लगे हुए हैं 39279 और 25173 आरक्षित हैं जो 22.83 प्रति शत है और बैकलॉग है 14,116 का। इसी प्रकार से बोर्ड्स और निगमों में भी यही स्थिति है। प्रथम श्रेणी के कुल पद हैं 2990, आरक्षित हैं 600 और 99 कर्मचारी लगे हुए हैं यह टोटल का 3 प्रति शत और 511 को बैकलॉग है। इसी प्रकार से सैकण्ड क्लास में 3120 कुल पद हैं, 624 चाहिए, 190 लगे हुए हैं और ये टोटल का 6 प्रति शत है और इस प्रकार से शिक्षा विभाग में पूरे हरियाणा प्रदेश में डी. ई. ओ. और बी. ई. ओ. 5 परसेंट, लैक्चरर की 6 परसेंट, जो जे.बी.टी. की 11 परसेंट, प्रिन्सिपल की 4.4 परसेंट, मास्टरज की 4.9 परसेंट और क्लार्कों की 7 परसेंट है। यह हालत आज प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग की है। सर, जिस प्रकार से हम ड्यूटी पर आते हैं (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातहेल): स्पीकर साहब, अभी हमारे साथी ने बैकलॉग की बात कही है। इस बारे

में एक बात तो मैं माननीय सदस्य से जानना चाहती हूँ कि ये जिस बैकलॉग की बात कर रहे हैं वह किस वर्ष तक का है। मैं इनको यह बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार के समय में बैकलॉग को क्लीयर करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है। दूसरी जो इन्होंने शिक्षा विभाग में डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. की बात की है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगी कि क्लास 1 और क्लास 2 के पदों पर पदोन्नति में रिजर्वें कितनी थीं?

श्री कृष्ण लाल पंवार: स्पीकर सर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ ये सभी कुछ अखबारों में आया है। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: पंवार जी, आपका समय हो गया है। मैं यह कहूँगा कि आप फीगर्ज की बात छोड़िए और आंकड़ों की बात को भी छोड़ दीजिए लेकिन आपकी जो स्पीच है यह बड़ी पॉजिटिव है इसलिए मैं आपको सिर्फ 30 सैकिंड और दे रहा हूँ।

श्री कृष्ण लाल पंवार: स्पीकर सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं प्रदेशों के पुलिस कर्मचारी हमें टोकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी प्रदेशों पंजाब ने पुलिस वालों को जे.बी.टी. के बराबर स्केल दिया है इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेशों के अंदर भी (विघ्न)

श्रीमति गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूँ वे ऑकड़ों को क्लैरिफाई कर लें कि से ऑकड़ों कहां से इकट्ठे किये हैं और यह बैकलॉग किस वर्ष का है?

श्री कृष्णा लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, ये ऑकड़े 31.11.2008 से अपटूडेट हैं। मैं एक बातक कहना चाहता हूँ कि पुलिस कर्मचारियों को पंजाब पैटर्न पर स्केल दिये जाये। इसके अलावा मेरे हल्के की कुछ सड़के हैं जैसे खन्दरा से बालचतान वाया, धर्मगढ़, इसस सड़क को आ वासन हाऊस में आया था लेकिन काम भुरू नहीं हो पाया है। इसी प्रकार अलपुर से अहर का वर्क अलॉट हो कर काम भुरू हो चुका था उसके बाद बंद है इसराना से भाउपुर आया कारद का भी काम बंद है। स्पीकर सर, इसराना से कम से कम 10-12 सड़के हैं जिनके टेंडर हो चुके हैं जिन पर काम चालू नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अनिल धन्तौड़ी (गहबाद, एस. सी.):अध्यक्ष महोदय, अपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमें युवा सदस्यों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद। लगभग 7 वर्ष पूर्व हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में

कमान आई। माननीय मुख्य मंत्री जी नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए जानकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत योजना तैयार की गई थी। तभी करने, निवे 1 को बढ़ाने को बढ़ाने, कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने, ग्रामीण व भाहरी दोनों ही क्षेत्रों का विकास करने, राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, मानवीय गारिमा के साथ समावे 1 और प्रदे 1 की उन्नति को सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता करने तथा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर और निश्चित रूप से अग्रसर है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश के विकास का लम्बा सफर तय किया है। It is written in part 3 of the Governor's Address that-

“I am hope to note that my Government has made significant gains in all these fieds and the State has come a long way. As per Quick Estimate, the State economy has achieved a growth rate of 9.6% in Gross State Domestic Product during the year 2010-11. The average growth rate of industrial production was 7.9% during the year 2010-11 as per index of the industrial production”

श्री ओम प्रकाश चौटाला: धन्यवाद तो उसका भी करना चाहिए जिसने आपको यह लिख कर दिया है।

श्री अनिल धन्तौड़ी: चौटाला साहब, मैं खुद लिखता हूँ। आप यहां सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटा हूँ चौटाला जी कृपया मेरा सहयोग करें।

Mr. Speaker: You are making a wonderful point. Carry on please.

Shri Anil Dhantori: Sir, I want to read our further that-

“As per the Advance Estimates for the year 2011-12, the per capita income of Haryana is expected to be Rs. 1.09.227 at current and the State ranks second, after Goa, amongst all the State” (Interruption)

Mr. Speaker: We must encourage young legislators.

17.00 बजे

श्री अनिल धन्तौड़ी: माननीय चौटाला जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया बीच में रुकावट पैदा न करें। माननीय अध्यक्ष जी सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हरियाणा देश में औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। पिछले 7 सालों में बिजली के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हुई है। वर्ष 2004.05 की तुलना में राज्य की अपनी बिजली के उत्पादन क्षमता तीन गुणा हुई है। (विधन) जनता से पूछ कर देखिए जनता यहां विराजमान है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से खेलों के क्षेत्र की बात करें तो खेलों के विकास के प्रति एक अभिनव और

समग्र दृष्टिकोण से हरियाणा के खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पदक लाओ और पद पाओ, नीति के अनुसार हमारे हरियाणा में आज खिलाड़ीयों का बहुत मान और सम्मान दिया जाता है हमारे देश के अनुरूप राज्य में अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या अधिक है। आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत की 72 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से ऊपर है और 47 प्रतिशत भारतीय 20 वर्ष से कम आयु के हैं। यह जरूरी है कि युवा भावित की क्षमता को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने युवाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 को युवा वर्ष घोषित किया है। सरकार खिलाड़ियों के लिए स्थान, समय और संसाधन अधिकार के तौर पर उपलब्ध करवा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निवेश किया गया है। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है, उनकी सरकार में नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। माननीय अध्यक्षजी मेरे विधान सभा क्षेत्र भाहबाद मारकंडा के दो अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ीयों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने डी.एस.पी. की नौकरी प्रदान की है। सुरेन्द्र कौर पूर्व महिला हॉकी टीम कप्तान और पुरुष वर्ग में हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप जी को भी डी.एस.पी. की नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों को हरियाणा पुलिस में भी विभिन्न पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्तियां दी हैं। The Federation of India Chambers of

Commerce and industries ने हरियाणा को खेल के क्षेत्र में Best Sports State for the year अवार्ड के लिए भी चुना है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम चलाकर गरीब व आम जन के लिए सुविधा मुहैया करवाकर लाभ दिया है। E.S.I. निगम और फरीदाबाद में 550 करोड़ की लागत से 500 बिस्तरों का एक अति आधुनिक मैडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है जो वर्ष 2013 तक चालू होने की सम्भावना है। सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 145 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। मेवात, सोनीपत और करनाल में तीन मैडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री चौ० भूपेद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है?

श्री अ तोक कुमार अरोड़ा: भाहबाद में मोरी-पोरी का जो मैडिकल कॉलेज है उसको भी मान्यता दिलवा दो। (गोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अरोड़ साहब ने जो मोरी पीरी मैडिकल कॉलेज की चर्चा की है, वह तो एक फेमिली ट्रस्ट है।

श्री अध्यक्ष: यह फेमिली ट्रस्ट क्या है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, एस.जी.पी.सी. का ठपपा लगाकर मीरी पीरी नाम से एक मैडिकल कॉलेज बना रहे हैं और उसकी बाकायदा सदन में चर्चा हुई और उसमें यह पाया गया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है और उनके जो पुत्र है, उन्हीं के बहुत नजदीकी व्यक्ति, पूरी उम्र के लिए उसके ट्रस्टी है। हमारे श्रद्धालु चढ़ावे के तौर पर गुरुद्वारा साहिब में पैसा चढ़ाते हैं। हरियाणा के गुरुद्वारों के गुल्लक से जो पैसा आता है, उस पैसे से बनने वाले मैडिकल कॉलेज का निर्माण सम्पूर्ण किया ही नहीं जा रहा है। हरियाणा के गुल्लक का पैसा एस.जी.पी.सी. हरियाणा में खर्च करने की बजाय पंजाब में ली जाती है। आदरणीय चौटाला जी मौजूद हैं उन्हीं की बात वे मानते हैं, वही इसको पूरा करवाएंगे। यह नौजवान तो कोफ़ी कर सकता है।

श्री अनिल धन्तौड़ी: अध्यक्ष जी, ग्रामीण इंफ़्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा ग्रामीण आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। (गोर एवं व्यवधान) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी 2012 तक..... (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Leader of the Opposition is speaking.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष जी, विरोधी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसा अदायरा है जो समुचे सिख

समुदाय को रिप्रेजेंट करता है लेकिन उसको भी यह लोग पारिवारिक बताकर उसकी खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहिब, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट के अंदर तो काम नहीं करती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष जी, सिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से तो बहुत कॉलेज बने हैं तथा अनेक सार्वजनिक हित के कार्य भी किये गये हैं।

Mr. Speaker: Not a family trust.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था है जिसके पास किसी स्टेट से भी ज्यादा पैसा आता है वह उस पैसे का प्रयोग लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं और उस संस्था की इस पवित्र सदन में खिल्ली उड़ाना समूचे सिख समुदाय का अपमान है इसलिए (गौर एवं व्यवधान)। यह मैं जो बता रहा हूँ यह असलियत है। यह सारे सिख समुदाय का अपमान है.....।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): चौटाला साहब, आप सारे सिख समुदाय को बीच में क्यों लेते हो?

श्री अध्यक्ष: चट्ठा साहिब, मैं आपको भी बोलने के लिए समय दूंगा, प्लीज, आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, विरोधी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इलेक्ट्रिक बाडी है और समूचे सिख समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करती है। यहां समूचे सिख समुदाय का अपमान किया जा रहा है। अतः अरोड़ा जी ने तो माननीय सदस्य से यह कहा था कि यह हमारे जिले का मामला है, एक अच्छा काम होने जा रहा है, हम आपके साथ हैं, उसके लिए प्रयास करें। यह तो सहमत थे इस बात के लिए, लेकिन यहां पर तो खिल्ली उड़ाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष: चट्टा साहिब, अब आप बोलिये।

सरदार हरमेहिन्द्र सिंह चट्टा: स्पीकर साहब, इनको सारे समुदाय के बीच में नहीं घसीटना चाहिए (गौर एवं व्यवधान)
Please, that is not the way. Sir, he is dragging the entire community into a college affair (Noise & Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, चट्टा को आपकी बात को कंप्लीट करने दीजिये। मैं आपकी भी सुनूंगा उनको कहने तो दीजिये। (गौर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Yes, I know it is मुझे पता है लेकिन उन्हें अपनी बात करने दीजिये (गौर एवं व्यवधान)

Sardar Harmhinder Singh Chattha: Everybody knows that it is an elected body.

Mr. Speaker: Chattha Sahib, you may please continue.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: िारोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक फेमली का ट्रस्ट है वह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ट्रस्ट नहीं है। अगर यह गुरुद्वारा प्रबंधक का ट्रस्ट होता तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनोनीत सदस्यों का नाम भी इसमें कही न कहीं भामिल होता। चौटाला साहिब वहां तो इंडीविजुअल नाम है। बादल साहब का नाम है, उनके लड़के का नाम है, उनके रि तेदारों का नाम है और अन्य किसी का कोई नाम नहीं है (गोर एवं व्यवधान) मै ये प्रार्थना करता हूं कि इस बात को लेकर सारे सिख समुदाय को न घसीटें। यह तो महज एक कालेज की बात है (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी न सिर्फ पूरे सदन को बल्कि पूरे समूचे सिख समुदाय को गुमराह कर रहे है। िारोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इलैक्ट्रिक वॉडी है और यह जो मोरी-पोरी के नाम से जो कॉलेज बन रहा है यह िारोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ही बन रहा है। (गोर एवं व्यवधान) यह बात अलग है कि पद की गरिमा को कायम न रखकर के एक कमेटी के चट्ठा साहब चेयरमैन बन गये जो अलग से िारोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बांटने का प्रयास कर रही थी।

श्री भोर सिंह बड़गामी: चट्ठा साहिब, स्पीकर होने के नाते तो उस समय आपको उसका चेयरमैन बनना भी नहीं चाहिए

था। (गोर एवं व्यवधान) आपने तो पद की भी गरिमा नहीं रखी।
(गोर एवं व्यवधान)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर सर, अनफारचुनेटली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वोटर मैं तो हूँ लेकिन ये तो वोटर भी नहीं है। He is not the voter. He absolutely knows nothing about the Gurudwara Parabandhak Committee. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी एक कमेटी है। अगर यह कॉलेज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन हो तो बात ठीक लगती है लेकिन जबकि नाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, पैसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है और वहां पर नाम है बादल परिवार के सदस्यों का, यह बात सरकार को बुरी लगी है। (गोर एवं व्यवधान) चौटाला साहिब, आप किस बात को लेकर तड़फते हो (गोर एवं व्यवधान) आपके तो मित्र है। आप बादल साहिब से जाकर कह दो (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं। श्री ओमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वह कॉलेज बनाया जा रहा है और यह कह रहे हैं। कि बादल परिवार का नाम वहां पर क्यों है। यह कैसे किया जा रहा। (गोर एवं व्यवधान)

Sardar Harmohinder Singh Chattha: Speaker Sir, it is not headed by the Gurudwara Prabandhak Committee. It is headed by the Chief Minister of Punjab.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: चौटाला साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, इन्होंने तो स्पीकर पद की गरिमा को ही बिगाड़ने का काम किया है। स्पीकर सर, आप पता कीजिये हम आपसे इस मामले में रूलिंग चाहते हैं कि क्या स्पीकर के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी कमिटी के चैयरमैन बन सकते हैं? (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Yes, I will give my ruling.

श्रीमति सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला साहब का बताना चाहूंगी कि सभी सिख एस.जी.पी.सी. के अंडर हैं, यह गलत है। मैं भी सिख हूँ और मैं इसको बताना भी चाहूंगी कि दिल्ली कमिटी है, महाराष्ट्र की अगल कमिटी है। सारे हिन्दुस्तान के सिखों को एस.जी.पी.सी. रिप्रजेंट नहीं करती है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री चौटाला जी ने मेरा नाम लेकर यह कहा कि यहां एस.जी.पी.सी. की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की जा रही है, अगर मुझे सही सुना। साथ ही इन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि यह जो मैंने स्पेसिफिक बात कही है, यह गलत है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी आदरणीय हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरे पिता की उम्र के हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार

की बात कहकर सदन को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हम सब सिख मर्यादाओं व संगठनों का सम्मान करते हैं। इस मामले में अध्यक्ष महोदय, आप एक कमेटी का गठन कर लें जो कि चौटाला साहब को भी सम्मन कर ले और मुझे भी सम्मन कर ले। उसमें मीरी पीरी ट्रस्ट का रिकार्ड भी मंगवा लें। मैं फिर दोहराता हूँ। मीपी पीरी ट्रस्ट के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल व उनके बेटे लाइफ टाइम ट्रस्टी हैं। (गौर एवं व्यवधान) एस.जी.पी.सी. का पैसा हरियाणा पंजाब के सिखों की मेहनत और खून पसीनें की कमाई का पैसा है और उस पैसे का उपयोग एक परिवार नहीं कर सकता। इस बात को व्यवधान में डालकर ये हाउस को बरगला नहीं सकते। (गौर एवं व्यवधान) ये यहां जवाब दें कि एस.जी.पी.सी. का पैसा क्या किसी एक व्यक्ति की बापौती है। हमारे सिख भाई एक-एक पैसा जोड़कर जो गुल्लक में डालकर आते हैं किसको अधिकार है कि उस पैसे का इस्तेमाल केवल एक परिवार कर ले। किसको अधिकार है कि उस पैसे से ट्रस्ट बना दी जाए और उसमें केवल बादल साहब व उनका बेटा पूरी जिंदगी के लिए ट्रस्टी बन जाएं, चट्टा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उनका नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, यदि मेरी बात गलत है तो मरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए, अन्यथा चौटाला साहब पर प्रिविलेज किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए तैयार हूँ लेकिन इसके लिए रिकॉर्ड मंगवाया जाए कि तमाम जो

मीरी पीरी है (गोर एवं व्यवधान) वह एस.जी.पी.सी. तत्वाधान में बन रही हैं या किसी ट्रस्ट के लोगो के सहयोग से बन रही है। यह तो रिकॉर्ड की चीज है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: ये तो आपके सामने ही मानने लग गए हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कहा है इन्होंने? (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: ये कह रहे हैं कि हां साहब, वे लाइफ ट्रस्टी है और उनके नाम पूरी जिंदगी के लिए मैडीकल कॉलेज कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये हमें आ असत्य बोलते हैं और हमें आ हाउस को गुमराह किया जाता है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भोर सिंह बड़मा जी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि हमारी विधान सभा ने तो उनको ट्रस्टी नहीं बनाया है (गोर एवं व्यवधान) ट्रस्टी तो कोई भी हो सकता है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये भी देखा जाये कि क्या ये कॉलेज विरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में बन रहा है या किसी ट्रस्ट के हिसाब से बन रहा है? ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि इस कॉलेज के लिए बादल साहब व उनके बेटे को लाइफ ट्रस्टी बना दिया गया है। तत्वधान में किसी के भी बने। पूरी उम्र के लिए मुझे ट्रस्टी बना दिया जाये तो उस कॉलेज का असली मालिक होगा कौन? (गोर एवं व्यवधान) क्या एस.जी.पी.सी. के पदाधिकारी है आदणीय बादल साहब?

सरदार चरणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में सिर्फ 5-7 गुरुद्वारे है (गोर एवं व्यवधान) जिनकी गोलक का 63 परसेंट पैसा एस.जी.पी.सी. के पास जमा होता है भोश 15 परसेंट पैसा सिखी के प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाता है और बाकी का पैसा एस.जी.पी.सी. में जमा हो जाता है लेकिन देखा हर गुरुद्वारे का काम जाता है।(गोर एवं व्यवधान) सिर्फ पांच या सात गुरुद्वारों को थोड़ा सा पैसा एस.जी.पी.सी. में जाता है। (गोर एवं व्यवधान) इसके बावजूद एस.पी.जी.सी. सभी गुरुद्वारों को सुन्दर बनाने के लिए 5-5 लाख रूपये की राशि देती है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे गुरुद्वार बहुत ही सुन्दर बने है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, बात यहां से भारु हुई थी कि मैडिकल कॉलेजिज तीन बनाये गये है। मैंने धन्तौड़ी जी से यही कहा था कि आपके अपने भाहर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहां से आप एम.एल.ए. चुनकर आये

है उसको भी आप बनवा लीजिए। अगर एस.जी.पी.सी. किसी भी ट्रस्ट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज बनाकर कुरुक्षेत्र, भाहबाद मारकण्डा के लोगों को सुविधा देना चाहती है तो सरकार उस सुविधा को क्यों नहीं लेना चाहती है। अगर इस ट्रस्ट में बादल साहब का नाम शामिल है इसलिए सरकार यह सुविधा नहीं लेना चाहती।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने कभी मना नहीं किया है। इसमें व्यवस्था का प्र न उठा था कि मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण भाहबाद में कौन कर रहा है? उस कॉलेज के ट्रस्टीज कौन है और उस कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है और कौन उसका निर्माण करना नहीं चाहता? बादल साहब का पूरा जिम्मा आदरणीय चौटाला जी की पार्टी के पास हरियाणा और पंजाब में हैं फिर ये उस कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं करवाते।

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज का निर्माण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार ने उस कॉलेज का एन.ओ.सी. रोका हुआ है। सरकार एन.ओ.सी. दिला दे तो हम कुरुक्षेत्र के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं और हम उस कॉलेज को बनावायेंगे।

श्री अध्यक्ष: जब चौटाला साहब जो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ने एक बात कह दी फिर पार्टी के दूसरे सदस्यों को बात बोलनी नहीं चाहिए।

श्री अनिल धन्तौड़ी: अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2012 तक 67.68 लाख रुपये मानव दिवस सृजित किये गये हैं। इनमें से 51 प्रतिशत मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए तथा 36 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के लिए सृजित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के तहत 12.676 विकास कार्य प्रारम्भ करवाए गये। मनरेगा के तहत श्रमिकों को 170 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है जोकि देश के राज्यों के सर्वधिक है। भारत सरकार ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया देने के लिए वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया। प्रथम चरण में इसे चार जिलों नामतः कैथल, मेवात, भिवानी, और झज्जर के 12 खण्डों में शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत गर्ई है। अब से निधियां ग्राम पंचायतों को सीधे ही हस्तांतरित की जायेगी और उन्हें 10 लाख रुपये तक के कार्य अपने स्तरों पर शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि हरियाणा एजुकेशन का हब बनाया जाए। अनेक कॉलेजिज और यूनिवर्सिटीज स्थापित किए जा रहे हैं। और युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय

मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सड़क और परिवहन सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर जिले में नई सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

Mr. Speaker: Thank you very much.

श्री अनिल धन्तौड़ी: अध्यक्ष महोदय, मेन पुलों पर ओवर ब्रिज बनाये जा रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को सुविधा हो।

श्री अध्यक्ष: कितने ओवर ब्रिज बनाये गये हैं?

श्री अनिल धन्तौड़ी: अध्यक्ष महोदय, 17 ओवर ब्रिज बनाए गये हैं। कानून व्यवस्था के लिए माननीय श्री भूपन्द्र सिंह हुड्डा की सोच है कि प्रदेश में सुशासन को सुविचारित रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला सोनीपत ने खरखौदा, जिला हिसार में बरवाला और जिला कुरुक्षेत्र में भाहबाद तीन नए उपमण्डल बनाए गए हैं। विशेषता यह है कि इसमें दो विधान सभा क्षेत्र भाहबाद और खरखौदा दोनों ही विधान सभा क्षेत्र सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको उपमण्डल का दर्जा दिया है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय की सोच दूरदर्शी है कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाए जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र भाहबाद मारकंडा को उप-मण्डल का दर्जा दिया है। गुड़गांव और फरीदाबाद की तर्ज पर अम्बाला और पंचकूला में

पुलिस आयुक्त प्रणाली भुरु की गई हैं। हरियाणा प्रदे 1 अन्य राज्यों की तुलना में निर्णायक रूप से अग्रणी है। हरियाणा की अर्थव्यस्था बड़ी तेजी से विकसित हो रही है जिसका प्रभाव दे 1 भर में महसूस किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमति सुमिता सिंह (करनाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अन्तर्गत इस बात पर पूरी तरह से सहमति वक्त करती हूँ कि हमारा प्रदे 1 हरियाणा बड़ी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी वर्तमान सरकार की जो नई-नई जन-हित की नीतियां और कार्यक्रम है उनको सरकार बड़े प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इसके नतीजे हर क्षेत्र के अंदर सार्थक उपलाब्धियों के रूप में सामने आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, प ु पालन, ग्रामीण एव भाहरी विकास, स्वच्छ पेयजल, कृषि सिंचाई एव जल संरक्षण, बिजली, उद्योग, सड़क एवं परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, युवा एव खेल, स्वास्थ्य एव चिकित्सा, महिला सक्तिकरण, बाल विकास, लैंगिक संतुलन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भासन एवं कानून व्यवस्था और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण आदि शामिल है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास की गति को बाधित करने वाली

बुराइयों के खिलाफ डट कर सघर्ष मिल है। इसमें सबसे बड़ी बुराई भ्रष्टाचार है। सरकार द्वारा हर स्तर पर ऐसी नीतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे रोजगार के अवसरों के संदर्भ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने पारदर्शी और न्यायसंगत नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार मुक्त भासन को सुभासन की अहम प्राथमिकता में शामिल किया गया है। माननीय राज्यपाल के अभिभक्षण में प्रस्तुत हरियाणा के विकास के आंकड़ों आगे आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि हमारा प्रदेश हरियाणा देश के अंदर एक नया तरक्की की मिसाल बनकर आगे आ रहा है। जिसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी दूरदर्शी सोच और प्रगति मिल नेतृत्व को जाता है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमति इंदिरा गांधी जी इस बात पर जोर देती थी कि कड़ी की कार्य प्रणाली में स्पष्ट रूप से दिखता है कि वे कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्के इरादे से हरियाणा को बड़ी तेजी से प्रगति के पथ पर आगे ला रहे हैं। हमारे प्रदेश की जो तरक्की है इसकी मिसाल देश के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्यों और पाकिस्तान के अंदर भी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सबके बावजूद भी प्रदेश की तरक्की की बेहतरी के लिए और बहुत कुछ करना बाकी है जिसे हमें एक लक्ष्य बनाकर बेहतर से बेहतर नीतियों के साथ आगे बढ़ना है। विकास के हमारे जो ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उसमें मैं हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि अपने प्रदेश के विकास के लिए आप सब

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सरकार का समर्थन करें। प्रदेा की तरक्की जो सदियों में होनी थी वह वह द्दों में होगी और जो द्दों की तरक्की है वह चंद वर्षों में होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहूंगी। आज के दिन जो पर्यावरण है वह न केवल हमारे प्रदेा या द्दों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विशय है। आज से दो द्दों पहले जब हरियाणा में नै नल हाई वे या दूसरे रोडज पर निकलते थे तो दोनों तरफ बहुत हरियाली नजर आती थी परंतु अब हम देखते हैं कि इन पर हरियाली पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अध्यक्ष महोदय, अब हमें चाहिए कि हम हरियाणा प्रांत में बहुत ज्यादा वृक्षारोपण करके ऐसी क्रांति लाये जो पूरे द्दों में मिसाल बनकर रह जाये। इसमें हम पचांयती राज संस्थाओं और दूसरे संगठनों की भी मदद ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निवेदन करती हूं कि हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है और हमारी जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको संगठित कर राष्ट्रिय स्तर पर उजागर करने के लिए एक महत्वकाक्षी योजना के रूप में एक संग्रहालय स्ीपित करें जिसमें महाभारत काल से लेकर अब तक जो हमारे युद्धवीर, स्वांतत्रता सेनानी और साहित्य कला से संबंधित जो विेश स्मृतियां हैं वे सभी संगठित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य या मधुमेय रोग भी कहा जाता है यह बीमारी सुनामी की तरह उतरी भारत में मानव भारीर का नुक्सान पहुंचा रही है। आज के दिन ग्रामीण क्षेत्र में भी यह बीमारी फेल रही है। इस बीमारी

का मुख्य कारण हमारा लाईफ स्टाइल है और इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में फर्मीलाईजर और कैमीकल्ज का इस्तेमाल तथा बाजार में खाने में मिलावट और नकली दवाईयों है। यह बीमारी आज के दिन सुनामी की तरह आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से पोलियो और टी.बी. की बीमारियों को समाप्त करने के लिए सरकारी तौर पर अभियान चलाये जाते हैं उसी तरह से इन बीमारी को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगें आपके माध्यम से रखना चाहूंगी कि हमारे करनाल भाहर के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। वह पार्किंग का कोई स्थान नहीं है और भाहर के अन्दर से निकलने में बहुत मुश्किल होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि करनाल भाहर में पार्किंग की व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो करनाल नगर निगम की बिल्डिंग भाहर के अंदर बनी हुई है जिसके कारण ट्रैफिक की भी समस्या आती है वह आज बहुत पुरानी हो गई है। वह बिल्डिंग बहुत जर्जर कंडीशन में है इसलिए एक नई और मॉडर्न बिल्डिंग करनाल नगर निगम की भाहर से बाहर बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं करनाल का बस स्टैंड भाहर से बाहर बनाने के लिए पिछले 7 साल से कह रही हूँ और इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था और हमारे पार्लियमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वि वास दिलाते हैं कि अगले सत्र से इन से पहले बस स्टैंड बनवा दिया जायेगा। इस बार मैं आवासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। (विधन) अध्यक्ष महोदय,

माननीय विपक्ष के साथी महिला को तो बोलने दे, जब इसकी बारी आये तब ये बोल लें। अध्यक्ष महोदय, हमारे करनाल भाहर के अंदर 50 से 60 अनअथोरईज्ड कॉलोनीज है उनकी तरफ से ध्यान दिलाना चाहूंगी। मंत्री जी यहां बैठे हुए है मेरी बात भी सुन रहे है। हमारे वहां जो अनअथोरईज्ड कालोनीज है उनको जल्दी से जल्दी एप्रुव किया जाये क्योंकि जिन कॉलोनीज का रैजोल्यू इन एप्रुवल के लिए भेजा गया था वे कॉलोनी अभी एप्रुव भी नहीं हुई है और दूसरी अनएप्रूव्ड कॉलोनीज वहां बनने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, करनाल के सदर बाजार एरिया में जूता उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। आज के दिन वह जूता उद्योग बंद होने के कागार पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि करनाल के अंदर जूता उद्योग बंद न हो क्योंकि वहां पर वे अपने घरों में जूते बनाने का काम करते है। उसके लिए करनाल के अन्दर कोई स्पे टाल भू हब बनाया जाए और वहां पर उनको स्पे टाल रिबेट भी दी जाये। इसके साथ-साथ मैं एक जनरल बात भी करना चाहूंगी कि मि 10 परसेंट महिलाओं विधान सभा में चुनकर आई है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे सभी साथियों को महिलाओं के प्रति इज्जत और आदर का भाव दिखाना चाहिए क्योंकि महिलाओं की इज्जत करने के हमको संस्कार दिये जाते है। लेकिन जब वे बोलना भुरू करती है तो हम यहां कुछेक सदस्यों को महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते है हुए देखते है इससे हमें बहुत दुःख होता है। हमें उम्मीद है कि आगे से ऐसा मौका नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय,

आपने मुझे महामहिमा राज्यपाल महोदय क अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

Mr. Speaker: My observation is that was found lacking the other day. this should not be happened again.

डॉ० बि।न. लाल सैनी (रादौर): स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 23.02.2012 को दिये अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जो भी बोलूंगा वह इस अभिभाषण के विरोध में बोलूंगा। सर, मैं अभिभाषण के विरोध में इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो बातें इसके अन्दर लिखी और वही पाप इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान से पढ़वाकर किया जिसे हमने सुना। सर, यह आपने भी देखा होगा कि जिस समय महामहिमा जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उस समय उनके माथे पर सिलवटें आई हुई थी क्योंकि वे बहुत नाराज थे और वे इसको पढ़ना नहीं चाहते थे। मैं इस अभिभाषण के पैरा नम्बर 53 पर बोलने से पहले अगर आप नाराज न हो तो मेरा आपसे एक छोटा सा प्र।न है।

श्री अध्यक्ष: आप मुझ से प्र।न क्यों करना चाहते हैं?

डॉ० बि।न. लाल सैनी: स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई सरपंच बनता है तो वह सारे गांव का सरपंच होता है या फिर अपने घर का ही सरपंच होता है? मैं

अपनी बात इस प्रकार से भुरु करना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मंत्री सुरजेवाला जी एक बहुत अच्छे मंत्री है। मैं इसको एक बात कहना चाहूंगा कि ये केवल कैथल के ही मंत्री नहीं है ये यमुनानगर के भी मंत्री है और सारे हरियाणा प्रदेश के भी मंत्री है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको सिर्फ कैथल तक ही सीमित नहीं करना चाहिए कभी यमुनानगर के अंदर भी आकर देखना चाहिए कि वहां की सड़को का क्या हाल है? मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में आये हम इनका दिल से स्वागत करेंगे, इनको अच्छी जगह ठहरायेंगे, अच्छा खाना भी खिलायेंगे। इसके साथ-साथ अगर से बुरा न माने तो मैं इनको यह भी कहना चाहूंगा कि आपने साथ ये अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर आये। वे भी हमारी मेहमान होंगी। हमारे जिले चार विधान सभा क्षेत्र हैं। उन चारों विधान सभा क्षेत्रों की 400 सड़को की हम इनको एक लिस्ट देंगे। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय उनमें से सिर्फ कोई चार सड़के की चुन लें और उन चारों सड़को पर ये सुबह-सुबह नहा धोकर जिस प्रकार से ये विधान सभा में आते है अच्छे सफेद कपड़े पहनकर, भाल ओढ़कर पूरी तरह से तैयार होकर उन सड़को पर घूमने के लिए जाये। (गोर एवं व्यवधान) वहां पर आगे-आगे पुलिस की जिप्सी होगी और पीछे-पीछे इनकी गाड़ी होगी। हम इनसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि ये अपनी कार के भी डोर खुले रखें उन्हें बंद न करें। जब ये आधे घंटे तक उन सड़को पर घुमकर आयेगे अगर इसकी धर्मपत्नी इनको पहचान ले कि ये उनके मंत्री जी ही हैं तो ये

समझे कि हमारी सड़के बहुत अच्छी है। और अगर पहचान न पायें और यह कहें कि आपने ये क्या हाल बना लिया है आपने तो सफेद कपड़े थे ये इतने गंदे कैसे हो गये, चलो दोबारा से बाथरूम में जाओ और नहाकर दूसरें कपड़े बदलकर आओं तो फिर यह समझों कि हमारी सड़को का ना हो चुका है। सर, यह बिलकुल सच्ची बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में सड़कों की वजह से एक पोस्ट मार्टम रोजाना होता है यानि 30 दिन में 30 आदमी परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। अभी अपने एक बात कही थी कि अगर आपको अपनी मांग बनवानी हो, अपनी बात कहनी हो तो मंत्री जी को अलग से लिख कर भेजी। आपके कहने के अनुसार मैंने 2 चिट्ठियाँ माननीय मंत्री जी को 2 महिने पहले लिखी थी नेकिन उनका जवाब आज तक नहीं आया है। यहां तो मंत्री जी एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। चौटाला साहब जब अपनी बात कह रहे थे तो मंत्री जी 15 बार खड़े हुये जैसे स्प्रिंग लगे हुये हो और मैं दो महीने से इंतजार कर रहा हूं मुझे मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला। हमारे कृषि मंत्री जी ने एक पत्र का जवाब मुझे जरूर दिया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बतरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अगर अपनी बात कहनी है तो वे मर्यादा में रह कर ही अपनी बात कहें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार आरोड़: इसमें इन्होंने कौन सी बात अमर्यादित कही है?

श्री अध्यक्ष: अब ये आगे से मर्यादा में ही बोलेंगे।

डॉ० बि।न.लाल.सैनी: अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने मर्यादा से बाहर कुछ कहा हो तो मैं अपने भाब्द वापिस लेता हूँ। सरदार परमवीर सिंह हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने लिखा है कि आपके रादौर विधान सभा क्षेत्र में हमारी 88 सड़कें हैं। 88 में से 38 सड़कें हालत में हैं बाकी 50 बैड कंडि।न में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि हमारी 88 की 88 सड़कें बुरी हालत में हैं। मंत्री जी को एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1999 से लेकर 1.4.2005 तक जब हरियाणा में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने रादौर विधान सभा क्षेत्र में 58 सड़कें बनवाई थीं। यह रिकॉर्ड की बात है लेकिन जब इनकी सरकार 7 साल में केवल 3 नई सड़कें बनी हैं। एक तरफ से 58 सड़कें बनीं और दूसरी तरफ इन्होंने केवल मेरे हल्के बनाई हैं और ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरे हल्के की बात नहीं है हमारे पूरे जिले की बात करूँ तो चौटाला साहब के समय में 183 सड़कें बनी थीं और अगर किलोमीटर की बात की जाये 308 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनीं। अगर इस सरकार की बात की जाये तो हमारे 4 विधान सभा क्षेत्रों में 21 रोड़ बनाये गये हैं और अगर 22वीं सड़क बनी हो तो मुझे बता दें। कहां तो एक तरफ 183 और दूसरी तरफ 21। उत्तर प्रदेश में जाकर बयान देते हैं कि अच्छी, चौड़ी सड़कें देखनी हो

तो हमारे सरकार में आकर देखें। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार जिले का दौरा जरूर करें। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के पैरा नं० 21 का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें थर्मल प्लांट का जिक्र किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कहीं भी घोषणा करते हैं तो वह पूरी होती है। मुख्यमंत्री जी ने थर्मल प्लांट का जब नींव पत्थर रखा, पहले चौटाला साहब ने रखा था, फिर इन्होंने भी दोबारा से रखा है। सर, मेरे पास सात साल पुराना अखबार है इन्होंने 28.8.2005 को जब इसका नींव पत्थर रखा, उस समय वहां लगभग पांच हजार आदमी होंगे। उनके सामने जब अनाउंस किया तो इन्होंने दो बातें कही कि एक तो जिन गांव के किसानों ने जो जमीन दी है मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं स्टेज से अनाउंस करता हूँ कि जिन परिवारों की जमीनें आई है, उनके परिवार के एक-एक सदस्य को इसमें नौकरी देंगे। उस टाइम हमारे मंत्री थे कैप्टन अजय सिंह यादव जी, वह भी वहां प्रैजेंट थे, उनके सामने ये बात कहीं थी, लेकिन आज तक भी वह अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। स्पीकर सर, अभी 26 जनवरी को हमारे बिजली मंत्री जो पहले वित्त मंत्री थे, वे वहा गए थे और उनसे जब अकबार वालों ने, मिडिया ने पूछा कि आपने ये नौकरीयों की अनाउंसमेंट की थी किन्तु ये अनाउंसमेंट आपने पूरी नहीं की तो स्पीकर सर, हमारे मंत्री जी ने यह कहा कि मेरे को तो पता नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं। जबकि उनकी फोटो भी मुख्यमंत्री जी के साथ छपी हुई थी। यह फोटो तब की है और ये मैंने संभाल कर

रखा हुई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिनकी जमीन गई है, उन परिवारों के बच्चों को नौकरी दी जाए। यह बहुत अच्छी बात होगी।

Mr. Speaker: Thank you very much your time is over.

डॉ० बिपिन लाल सैनी: स्पीकर सर, मुझे 5 मिनट का समय और देने की कृपा करें।।

श्री अध्यक्ष: आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है, अभी अन्य सदस्यों को भी बोलने है, माजरा जी ने बोलना है, कविता जी ने बोलना है। आप बजट पर भी बोल लेना। (गौर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि उस फोटो में मैं साथ था। मैं उस समय बिजली मंत्री नहीं था। गलत बात यहां हाउस में कहना अच्छी बात नहीं है। (गौर एवं व्यवधान)

डॉ० बिपिन लाल सैनी: मंत्री जी, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। ये फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहां थे, ये आपकी फोटो है। मैं गलत होऊंगा तो मैं आप से माफी मांग लूंगा। आप यहां आकर के देख लीजिए क्योंकि मैं तो अध्यक्ष महोदय, की इजाजत के बिना आपकी सीट पर नहीं आ सकता।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किान फौजी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई प्वायंट आफ आर्डर तो बताएं?

श्री राम किान फौजी: स्पीकर सर, आपके माध्यम से साथी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने चौटाला साहब के कार्यकाल के बारे में कई बार यहां कहा। ये अच्छी बात है, वे आदरीण हैं। (गौर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने मुझे परमी तान दी है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सैनी साहब ये बताएं कि चौटाला साहब ने अपने छः साल के कार्यकाल में बिजली के कितने कारखाने लगाए? उन कारखानों का नाम बताएं कि कौन सा कारखाना लगाया, व उनमें कितने नौकारीयां दी? (गौर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is the last line.

डॉ० बि तान लाल सैनी: सर, पिछली बार भी यहा बात थी कि पहला चरण पूरा हो गया और दूसरे का काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या छोटी-छोटी नहरों का काम भी चरणों में होगा और उसके भी चरण बनाए जाएंगे? इससे अच्छा तो ये है कि इस काम को बंद ही कर दो। इस सरकार को बने हुए आज साल साल हो गए है मगर इन नहरों के चरण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। इस हिसाब से 21 साल में तीन चरण पूरे होंगे तब ये नहर चलेंगी।

श्री अध्यक्ष: क्या आप दादूपुर नहरके अगेंस्ट है?

डॉ० बि।न. लाल सैनी: स्पीकर सर, दो नाले हैं जो कि बरसाती नाले हैं, एक राक्षी नदी है और दूसरे चतंग है। जब ऊपर बरसात होती है तो उनका पानी आता है और पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। दूसरी तरफ वह नहर खुद रही है, जिनके कारण उसमें आकर वह पानी भर जाता है। तीन साल से किसनों का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बावजूद इस नहर के काम पूरी नहीं किया जा रहा है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी चट्टा साहब इस विषय पर मुझसे नाराज हो गए थे। वे कह रहे थे कि नहर का काम तीन चरण में पूरा होगा। बताओ नहर तीन चरण में कैसे पूरी होगी? स्पीकर सर, पुलों का जिक्र आया। मेरे जिले में तीन पुल हैं वैसे चार पुल हैं, जिनके ऊपर से हमारे जिले में लगभग 30 प्रतिशत गांवों के लोग यमुनानगर भाहर में आते हैं और वहां से जाते हैं। उन चार पुलों में से तीन पुल टूटे पड़े हैं जिनकी वहज से हमारे जिले के 30 परसेंट लोगों को कम से कम 20 किलोमीटर का चक्कर काटकर भाहर में जाना पड़ता है। और इसी तरह 20 किलोमीटर चक्कर काटकर वापिस आना पड़ता है विशेषतौर में जो छोटे-छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनका इतना लम्बा चक्कर काटने से बहुत समय खराब होता है। उनके माता-पिता को उन्हें छः बजे तैयार करके बस में बैठना पड़ता है ताकि वे समय पर स्कूल पहुंच सकें। इसी तरह भाम इतना लम्बा 20 किलोमीटर का चक्कर काटकर जब वापिस बच्चे घर आते हैं तो भाम के छः बजे जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का, सोने का तथा खाने का सिस्टम

खराब हो जाता है। स्पीकर सर, इतना बुरा हाल आज मेरे हल्के में इन टूटे पुलों की वजह से हो चुका है।

Mr. Speaker: Thank you, Saini ji आप बैठिये! आपके दूसरे मेंबर मोहम्मद इलियास जी एक मिनट के लिए बोलेंगे।

मोहम्मद इलियास: स्पीकर सर, क्या मैं भी एक मिनट ले सकता हूँ?

श्री अध्यक्ष: मोहम्मद इलियास जी, अगर आप ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो मैं इनकी आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो मुझे एक मिसाल देकर सरकार की पोजी उन बताने की अनुमति दे।

श्री अध्यक्ष: इलियास जी, मैं आपके बोलने की अनुमति दे सकता हूँ मिसाल देने की नहीं (विघ्न)

मोहम्मद इलियास: सदर साहिब, आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष: इलियास जी, यदि आपके साथी सैनी साहब बैठ जायेंगे तब आपको मौका दूंगा। एक समय में दो आदमी कैसे बोल सकते हैं?

डा० बि। न. लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मेरी अभी बहुत बातें बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने यह कहा है कि जहां तक बोलने के समय की बात है बोल सकते हैं। लेकिन अभी खत्म करें क्योंकि मैं कविता जी को नैकस्ट स्पीकर के लिए इन्वाइट कर चुका हूँ। (विधन) वह एक महिला सदस्य हैं उनको सम्मान के तौर पर आपको बोलने का मौका देना चाहिए। वैसी सैनी साहब आपने अपना दृष्टिकोण बड़े अच्छे ढंग से रखा है, अब आप बैठिये। I am so happy with you.

श्री अध्यक्ष: श्री मति कविता जैन जी, अब आप पांच मिनट के लिए बोलिये।

श्रीमति कविता जैन (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, बस पांच मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्पीकर सर, महाहिम राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण मात्र सरकार का झूठा गुणवान है और यह बात विधानसभा में रखी गई कैंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर होती है। रिपोर्ट से तरफ पता चलता है कि किस तरह सरकारी खजाने को दुरुपयोग किया गया है चाहे वह कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, फूड एण्ड सप्लाइ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट में जमकर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया।

वास्तव में यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो रही सरकार करोड़ों
गये बेकार, यह बिल्कुल सच साबित होता है। स्पीकर सर, एक
तरफ तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में टैक्स हटाने की
बात कही गई है लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के जी गैर-घरैलू
बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार द्वारा 100 से 130 रुपये प्रति
किलोवाट प्रति माह बिल से अलग चार्ज डालकर छोटे-छोटे
उद्योगों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है और इसी तरह से
भाहरों के अंदर जो व्यवसायिक नक्शा पास करवाने की फीस थी
उसे भी 1431 रुपये की बजाय भाहर अनुसार 6000 रुपये से लेकर
13500 रुपये प्रति वर्ग गज तक बढ़ाकर भारी आर्थिक बोझ डाल
दिया है। स्पीकर सर, एक तरफ तो सरकार हमें किसान के
हित की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाये तो
किसान आज बर्बादी के कगार पर है। ध्यान कपास की जो फसल
है उसके दाम इस वर्ष पिछले वर्ष से आधे दिये गये हैं जबकि
खाद, बीज और डीजल के दाम बढ़ते जा रहा है। अगर सरकार
वाकई में किसानों का भला चाहती है तो रंगनाथ मिश्र आयोग की
रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, सरकार हमें
अधिग्रहण की नीति के बारे में हमें बड़ी-बड़ी बातें कहती रहती
है तो फिर क्या कारण है कि सोनीपत के अंदर जैसे बड़खालसा,
राई, भौदपुर कुंडली के किसान काफी लंबे अर्से से अधिग्रहण के
खिलाफ बैठे हुए हैं। वास्तव में यह तो अपने मुंह मियां मिट्टू
वाली बात है। स्पीकर सर, बिजली उत्पादन के केस के अंदर मैं
कहना चाहूंगी कि सरकार बार-बार बिजली उत्पादन बढ़ोतरी का

गुणवान करती रहती है, लेकिन बिजली की हालत क्या है? प्रदेश के अंदर जो बिजली की बुरी स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। सर्दियों का आलम भी यह है कि यहां हर रोज भाहरों के अन्दर 6 से 8 घंटे के कट लगाये जाते हैं। एक तरफ से यह कहा जा सकता है कि इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तो दिवाला ही निकल चुका है क्योंकि बिजली बोर्ड आज 6617 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। स्पीकर सर, 5 साल पहले 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए गए थे और उसका भार उन उपभोक्ताओं पर डाला गया था जो रैगुलर बिल भरते हैं। हालत यह हो गई है कि 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिल माफ करने के बावजूद भी 39000 करोड़ रुपये के आज भी बकाया है और इस वजह से बिजली विभाग फिर से बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह बात बहुत ही गलत है और उन लोगों के लिए गलत है जो समय पर बिजली के बिल भरते हैं। सरकार को उन उपभोक्ताओं के बारे में भी सोचना चाहिए जो वाकई में बिजली के बिल पे करते हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के ऐड्रेस में ग्रामीण विकास की बात कही गई है जबकि सचवाई यह है कि गांव जाने वाली सारी सड़के टूटी पड़ी है। ईंटों का सरकारी रेट 3800 रुपये प्रति हजार है जबकि बाजार में यह 4000 रुपये की दर से मिलती है। इस बारे में जैसा कि क्वै चन ऑवर में क्वै च भी लगा था उसके जवाब में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर मना किया था कि गांव में सीवरेज नहीं डाल सकते। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत सारे

गांव ऐसे है जिनका कि हुडा डिपार्टमेंट की तरफ से जमीन का अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। गांव के गन्दे पानी निकासी के लिए कोई जमीन नहीं बची है। ऐसे में सरकार किस आधार पर दावे पे आ करती है कि विकास हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार सचेत है। इसी तरह से मैं ऐजूके इन डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहूंगी कि शिक्षा का एक तरह से बेड़ा ही गर्क हो चुका है। हालांकि हमारी शिक्षा मंत्री महोदय हमें आ ही क्वालिटी और क्वांटिटी ऐजूके इन की बात करती हैं लेकिन यदि यदि मायनों में देखा जाये तो आज जो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, वह प्राइवेट स्कूलों के सहारे से चल रही है। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार यदि वाकई में शिक्षा के प्रति इतनी सोच रखती है तो क्या कारण है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता? यहां तक कि कैंग की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर लिखा है कि ऐजूसेट प्रणाली लागू करने के लिए किस तरह से सरकार के करोड़ों रूपयों का नुकसान किया गया है। हमारे सोनीपत भाहर में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कोई लैंड है, न बिल्डिंग है तो फिर वे कैसे ऐजूसेट प्रणाली का लाभ उठा पाएंगे।

इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि राजीव गांधी ऐजूके इन सिटी का प्रचार केवल अखबारों तक सीमित होकर रह गया है जबकि उसके लिए भूमि अधिग्रहण करते वक्त साफ भाब्दों में यहा कहा गया था कि वहां ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर

सिटी बनाई जायेगी और उसमें यूनिवर्सिटी भी बनेगी। मुझे लगता है कि यह ड्रीम प्रोजैक्ट ड्रीम ही बनकर रह जायेगा, कभी पूरा नहीं होगा।

आज लोगों के स्वास्थ्य की बात कही जा रही है जबकि सच तो यह है कि अस्पताल खूद की बीमार हो चुके हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर भेज दिया जाता है। हमारे सोनीपत का सिविल अस्पताल है वहां नयी भर्ती तो होती नहीं है वहां जो वर्तमान में स्टाफ है उसको भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। एक रेडियोलॉजिस्ट था उसे भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। आई स्पेशलिस्ट को भी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री मति गीता भुक्कल मातनहेल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि राजीव गांधी ऐजूके इन सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजैक्ट है और वह इसका विधान सभा क्षेत्र है इनको तो इसके लिए मुख्यमंत्री की यूनिवर्सिटी बना दी है। वहां इतना विकास हो रहा है, इनको तो इनके लिए मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए बजाय इसके ये गर्वनर साहब के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा और न जाने क्या-क्या कह रही है। अध्यक्ष महोदय, ने केवल वहा प्रचार-प्रसार किया है बल्कि जिस दिन राजीव गांधी ऐजूके इन सिटी में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जायेगा उससे वहां ने इनल इंटरने इनल लेवल की ऐजूके इन आएगी

और ओवजआल इफ्रंस्ट्रक्चर डवैल्प होगा। मैं तो इसके लिए माननीय सदस्य को कहूंगी कि इनको तो मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

श्रीमति कविता जैन: वहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आयेंगे तो हम उस दिन मामनीय मुख्यमंत्री जी को पूरे जोर- जोर से धन्यवाद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कविता जी, आप बैठिये, आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गये हैं।

श्री मति कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, सामाजिक और न्याय के अधिकार की बात करते हैं। कई माहिने हो गये हैं लेकिन वृद्ध अवस्था, विकलांग और विधवाओं को समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है। इसी तरह से लाखों की संख्या में लोगों के नाम बी.पी.एल. कार्ड की लिस्ट से काट दिए गये हैं। बिना लोगों की इन्फार्म किये लोगों को राशन देना बन्द कर दिया है जोकि सरासर गलत है। सबसे पड़ी बात यह है कि जो बी.पी.एल. कार्ड बनाने का आधार बनाया गया है वह 443.21 रूपये प्रति माह है जोकि सरासर ही गरीब लोगों की भावनाओं के साथ एक खेल रचा गया है। एक तरफ से गर्वनर एड्रेस में प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम वर्तमान मूल्यों पर 1.09.227 रूपये बताई गई है और दूसरी तरफ बी.पी.एल. कार्ड बनाने का आधार 443.21 रूपये प्रति माह किया गया है जोकि सरासर गलत है। इसी तरह से भाहरी विकास

के मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि सोनीपत के अन्दर रोहतक रोड़ गोहाना रोड़ बाबा तराना रोड़ और ककरोई रोड़ पर चलना मुश्किल हो गया है। पिछले बार जब विधान सभा का गठन हुआ था उस समय पहले गवर्नर एड्रेस में सोनीपत भाहर को मैंगा सिटी बनाने का प्रचार किया गया था और उस समय हमने इस बात का स्वागत भी किया था। मैंने जब भाहरी निकाय विभाग से मैंगा सिटी के बारे में प्रश्न लगाया था तो उसका जवाब इन्कार में आया था तो यह साफ तौर से जाहिर होता है कि गवर्नर पड्रेस में प्रदेश की जो बात लिखी गई है यह सही नहीं होती।

Mr. Speaker: Thank you very much.

श्रीमति कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की बुरी हालत है मैं प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आज प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो गया है आज कॉमन पीपल तो एक एम.एल.ए. भी प्रशासन से त्रस्त हो चुके हैं। सरकार ने प्रशासन के सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था जिस पर आज तक 1.75 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। अगर प्रशासन की मनमानियों से जनता को राहत देना चाहते हैं तो सिटीजन चार्टर को लागू करना चाहिए और इसके बारे में कानून बनाना चाहिए। अन्त में मेरा कहना है कि सरकार को कहने में नहीं करने में विरोध वास करना चाहिए तभी प्रदेश की वास्तव में तस्वीर बदलेगी।

18.00 बजे

श्री कृष्ण हुड्डा (बड़ौदा): अध्यक्ष महोदय, महाममहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पे । इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और सदन में उपस्थित सत्तापक्ष व विपक्ष के मेरे समस्त साथियों व हरियाणा के जन मानस को बधाई देता हूँ कि हमारा प्रदेश । राज्यपाल महोदय के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को प्रभावशाली नेतृत्व में दिन-दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। हरियाणा में बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, जो एक लाख के आकड़ों को पार कर चुकी है कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, हरियाणा सरकार का मिल रहे पुरस्कार, खेल व शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, इस बात के साक्ष्य हैं कि हमारी विकास की गाड़ी सरपट दौड़ रही है बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की है। सन् 2004 में औसतन बिजली उत्पादन 578 लाख यूनिट था जो अब बढ़कर 1009 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गया है। वर्तमान में जो परियोजनाएं चल रही हैं। उनसे हरियाणा बिजली उत्पादन अधिशेष वाला राज्य बन जाएगा। जिससे हर गांव भाहर, किसान उद्योग को 24 घंटे बिजली मिलेगी और सस्ती भी होगी क्योंकि बाहर से मंहगी दरों को खरीदनी नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की अर्थिक विकास दर 2011 में 9.6 प्रतिशत होना यह दर्शाता है कि विप्लववादी अर्थिक मंदी होते हुए भी हरियाणा ने प्रगति की है जोकि सरकार की सूझबूझ और कुशलता का परिचय देती है। हरियाणा एक छोटा राज्य होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डार में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है अध्यक्ष

महोदय, खेल के क्षेत्र में हरियाणा की पहचान व प्रतिष्ठा देश में सर्वोपरि है। ऐतिहासिक खेलों में लगभग दो दर्जन स्वर्ण पदक परोक्ष व अपरोक्ष रूप से हरियाणा से सम्बन्धित है। देश के दूसरे सभी राज्य हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए यहां हर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। चाहे वो धन से सम्बन्धित हो चाहे ढाचा गत राशि के साथ-साथ उन्हें पुलिस विभाग में ऊंचे सरकारी पद भी दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हरियाणा को शिक्षा हब के रूप में जाना जाने लगा है। सरकार ने सैकड़ों कॉलेजों के साथ-साथ दर्जन भर विविद्यालयों की स्थापना की है। शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने पाठ्यक्रम, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ-साथ ऐजूसैट व कम्प्यूटर शिक्षा सभी स्कूल व कॉलेजों में लागू की है। जिससे हरियाणा के युवा अब बड़े बाहरों में उच्च स्तर की नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने थोड़े से अरसे में काफी उन्नति की है पर यात्रा कभी करती नहीं है। विकास के कई पड़ाव अभी हमें पार करने हैं। इसके लिए हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सकारात्मक सहयोग की जरूरत है। अतः मैं प्रदेशवासियों, सत्ता पक्ष व विपक्ष के साथियों से आह्वान करता हूँ कि आओ हम मिलकर हरियाणा को एक उन्नत और स्वर्ण समान सुन्दर राज्य बनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार समस्याएं अपने हल्के की भी कहना चाहूंगा। मेरे हल्के के अंदर जो हमारी मार्किटिंग बोर्ड की सड़के हैं उनकी

बड़ी खस्ता हालत है, उनकी तरफ भी मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। मैं एक डिमांड यह करूंगा कि बड़ौदा हल्के के अंदर कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और मेरे हल्के का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: श्री रामपाल माजरा जी, अब आप बोलें।
(विघ्न)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यदि आपको परे ानी है तो—

श्री अध्यक्ष: रामपाल माजरा जी, मुझे परे ानी नहीं लेकिन आपके बैठे-बैठे ऐसे कमेंट्स किया, यह अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और आपसे अस्पैक्ट करता हूँ।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तरसा कर जो समय दिया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप पार्टी के चीफ स्पीकर हैं और हम चाह रहे थे कि पहले और लोग बोल लें और आप बाद में आराम से बोल लेते। आपने मेरी चिट भी पढ़ी होगी और अगर

वह चीट आपका सम्मान न कर रही होती तो आप खुद अपने आप अंदाजा लगाइए। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यह चिट पिछली बार भी आई थी, आपने यह कहा था बजट पर आप बोलेंगे लेकिन आपने यह कह दिया कि मेरी मजबूरी थी।

श्री अध्यक्ष: मेरी आज कोई मजबूरी नहीं है। आप बोलिए।

श्री रामपाल माजरा (कलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें भूलकर यही कहूंगा कि आपने मुझे महामहिमा राज्यपाल महोदय के अभिभाषक पर चर्चा करने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण दे रहे थे और जब वे इस अभिभाषण को पढ़ रहे थे तो ट्रेजरी बेंचिर्ज की तरफ से कहीं भी किसी भी योजना के ऊपर मेजें नहीं थपथपाई गई। केवल पार्लियामैंट एफेयर्ज मिनिस्टर अकेले पड़े हुए थे और दूसरे मैम्बर्ज की तरफ देख रहे थे कि कोई और भी मेर्ज थपथपाए। उनका दिल भी मान रहा था कि मेजें थपथपाने वाला अभिभाषण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस अभिभाषण को सुनकर और पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि—

दिखने में जो प्यार संभाले बैठे है, अंदर से अंगार संभाले बैठे है।

सच तो यह कि सच से है परहेज इन्हें, ये झूठा व्यापार संभाले
बैठे है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जब किसान आयोग बना उस समय मैंने समझा था कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की समस्याओं का कोई समाधान होगा। कमीशन बनने के बाद डॉक्टर परोदा इस आयोग के चेयरमैन बने। उन्होंने वेबसाइट भी जारी की कि सुझाव दिए जायें लेकिन तब से लेकर आज तक किसानों को सबसे ज्यादा समस्या आई है। सर, अब 10 पैसे प्रति किलो गन्ने के भाव बढ़ते हैं और 20 पैसे प्रति किलो गेहूं के भाव बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एम.एस.पी. तक करती है और इसके साथ-साथ कई चीजें इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यदि चावल के दाम बढ़ जाते हैं तो ये कहते हैं नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट की बात है और दीवारों पर लिखा जाता है हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। आज वही राज है जिसमें जीरी गई ब्याज में और पराली गई लाज में क्योंकि बासमती जीरी का भाव 20 साल पहले 1600-1700 रुपये प्रति क्विंटल था वह आज 20 वर्ष बाद भी कम होकर 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल है। सत्तापक्ष के सदस्य भी बाई इलैक्ट्रॉन में गये थे और इन्होंने देखा होगा कि किसान भाव नहीं बढ़े। किसानों ने तरसने के बाद यह समझा कि आज वह नारा जो दीवारों पर लिखा होता था वहां कहां गया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी

ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में मैं याद दिलाना चाहता हूँ
किसान (विधन)

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh):

Speaker Sir, on a point of order. माननीय सदस्य जीरी का जिक्र कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह पी.आर. जीरी की बात नहीं है यह 1121 या दूसरी जीरी होगी जिसका भाव कभी एम.एस.पी. पर निर्भर नहीं होता। एस.एस.पी. पर केवल पी.आर. जीरी निर्भर होती है। पी.आर. जीरी का रेट बता दें कि इनकी सरकार में क्या था और अब क्या है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं किसान की और बातें भी बता सकता हूँ। इनके समय में किसानों से 11 प्रतिशत ब्याज मिनी बैंको में लिया जाता था जो हमने कम करके 4 प्रतिशत तक कर दिया है। (विधन)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथी जो किसान की बात करते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999 से 2005 तक 4392 एकड़ 6 कनाल 11 मरला भूमि किसानों की कही सेज के नाम पर कही आई. एस. टी. के नाम पर और कहीं उद्योग खड़े करने के नाम पर अधिग्रहण की गई है। इस तरह से 750 एकड़ भूमि प्रति वर्ष अधिग्रहण की गई है।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मेरे काबिल दोस्त रामपाल माजरा जी सदन को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। माननीय साथी जिस सेज की बात कर रहे हैं उस सेज की जमीन

का मैं आज नोटिफिके न लेकर आया हूँ। वह नोटिफिके न इसके समय की है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, ये उस बात को विद्डा कर रहे है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, हम विद्डा नही कर रहे है। मैं यह भी बता दूंगा कि किस-किस प्रोजैक्ट के लिए कितनी-कितनी भूमि किसानों की अधिग्रहण की गई है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, मंत्री जी यह बता रहे है कि सेज की जमीन आपकी सरकार में वक्त में अधिग्रहण की गई। आप यह बात विद्डा कर लो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नोटिफिके न है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, ये विद्डा कर रहे है। You need not reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी जिस जमीन की बात कर रहे हैं उसका मुआवजा ये लोग 1-1 लाख 2-2 लाख और 5-5 लाख रूपये प्रति एकड़ प्रति एकड़ दिया करते थे। हरियाणा प्रदे 1 बेहतरीन फ्लोर रेट पॉलिसी बनाई और एक-एक करोड़ रूपये तक प्रति एकड़ मुआवजा उस जमीन का दिया जिसका इन्होने 5-6 लाख मुआवजा

प्रति एकड़ दिया था। मेरे पास सारे आंकड़े और तथ्य मौजूद हैं।
(तोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस गुण जमीन कहीं होजरी कम्पलैक्स के नाम पर, कहीं औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर, कहीं न्यूक्लीयर पावर प्लांट के नाम पर और कहीं आई. एम.टी. के नाम पर अधिग्रहण करके किसानों से छीन ली। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी डिटेल्ड प्रॉजेक्टवाइज है यदि ये कहेंगे तो मैं वह जानकारी भी सदन में रख दूंगा। इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कह भी कहा है कि.... (तोर एवं व्यवधान) सर, इसके अलावा न्यूक्लीयर पावर प्लांट के बारे में भी इन्होंने पूछा है। इन लोगों ने भायद पढ़ा नहीं होगा मैं इनको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सौम्य दत्ता ने कहा है कि न्यूक्लीयर पावर प्लांट के 15 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में खतरनाक विकिरण होगा और 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैंसर बढ़ेगा और दूसरी बीमारीयों भी बढ़ेंगी। जिस न्यूक्लीयर पावर प्लांट की ये बात कर रहे हैं उसमें हेल्थ की कोई रिक्वोरिटी नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा नीतिगत मुद्दा है। ये सभी पार्टियों के एक्रॉस भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, क्या मैं यह समझूँ कि श्री रामपाल माजरा जी उनकी पार्टी की तरफ से यह कह रहे हैं कि वे हरियाणा प्रदेश में न्यूक्लीयर पावर प्लांट लगाने के विरोध हैं। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, राज्यपाल माजरा जी कह रहे हैं कि वे हरियाणा प्रदेश में न्यूक्लीयर पावर प्लांट लगाने के विरोधी हैं (गोर एवं व्यवधान) बड़ी सिम्पल सी बात है ये विरोधी हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस न्यूक्लीयर पावर प्लांट के लगने से फतेबाद और सिरसा जिले के अन्दर 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आयेगा (गोर एवं व्यवधान) ये बात कर देते हैं जापान की (गोर एवं व्यवधान) सरकार, अगर ये न्यूक्लीयर पावर प्लांट के विरोध है तो ये हरियाणा के किसान के हितों के विरोधी है, हरियाणा के गरीब मजदूर और हरियाणा के आम व्यापारी के हितों के भी विरोध है क्योंकि ये चाहते हैं नहीं कि वहां पर पावर आये। सिरसा और फतेबाद जिले के अन्दर हम इससे ज्यादा पावर किसी और सोर्स से नहीं दे सकते। ये न्यूक्लीयर पावर प्लांट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आतिथ्य से और उनकी ही मदद से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल से फतेहाबाद के लिए लेकर आये हैं।

श्री रामपाल माजरा: मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि देश के दूसरे प्रदेशों में जहां पर न्यूक्लीयर पावर प्लांट लगे हुए हैं क्या वहां मुख्यमंत्री भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ही हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हम न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट नहीं लगायेंगे तो हमारे पास alternative sources of energy क्या है?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर सर, जो हमारे पास थर्मल पॉवर प्लांट्स हैं उनके लिए हमें कोयला कोल प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड से बहुत मुफ्त काल से मिलता है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये जमीन अधिगृहित की गई थी क्या उन थर्मल पॉवर प्लांट्स के लिए ही अधिगृहित हुई है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मैं यह कहा रहा हूँ कि यह जमीन न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट के लिए ही अधिगृहित हुई है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसके द्वारा हरियाणा को बहुत भारी फायदा होने वाला है। विपक्ष के साथियों के सोच बहुत गलत है। ये वहाँ पर जाकर किसानों को भड़काते हैं (गोर एवं व्यवधान) सर, मैं आपकी, तमाम सदन और इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 80 परसेंट किसानों ने लिखकर दिया है कि उनको इस न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट के लिए सरकार द्वारा जमीन एक्वायर करने से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद भी ये विपक्ष के लोग हाउस को गुमरहा करते हैं। पता नहीं ये हाउस को क्यों मिसलीड करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट है जिससे 1500 मैगावाट बिजली

पैदा होगी। ये इसका विरोध कर रहे हैं यह बड़े ताज्जुब की बात है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट के लगने से न केवल सिरसा और फतेहाबाद में बिजली ही आयेगी बल्कि 50 हजार करोड़ रुपये के लगभग का निवेश भी आयेगा। उस न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट जो विरोध करते हैं वे फतेहाबाद सिरसा के साथ-साथ पूरे हरियाणा के हितों के विरोधी हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मैं वह भी विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि उस न्यूक्लीयर पॉवर में सारे-सारे लेटैस्ट सेफ्टी मेजर्स को लिया जा रहा है। वहां पर दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया जायेगा। ये यह कहकर कि वहां पर लोगों को कैंसर की बीमारी होगी, वहां पर लोगों का नुकसान होगा, हाउस को मिसलीड कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री परमिन्दर सिंह दुल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट के विरोध में वातावरण बना हुआ है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट था वह फोकोसीमा (जापान) में था उसे भी विधिवत रूप से

इसी वजह से बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके विकिरण की स्थिति किसी से सम्भाली नहीं जा सकी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी केवल संकीर्ण और नकारात्मक सोच रखते हैं। Some people have negative thoughts. Government has passed Bill on nuclear energy. It has been decided umpteenth number of times right from the times of Pandit Jawaharlal Nehru uptill today that Nuclear energy will sustain energy needs of this country. It marks us independent. Sir, we are going to get Coal from 3000 kilometres. सर, 3000 किलोमीटर से हरियाणा सरकार को कोयला लाना पड़ता है उसके बाद उसकी सफाई होती है। उसके बाद ही हम बिजली पैदा करते हैं क्योंकि हमारे पास बिजली पैदा करने का नैचुरल सोर्स नहीं है। स्पीकर सर, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 64 वर्ष से हम न्युक्लीयर पॉवर प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हैं। आज तक हिन्दुस्तान का रिकॉर्ड है कि यहां पर न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के मामले में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। कभी विपक्ष के साथी रिया पहुंचा जाते हैं और कभी जापान पहुंच जाते हैं। सर, यहां पर हम जापान या रिया की नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बात कर रहा है। सर, दुर्भाग्य से लोकदल के साथी जिनको न इस बात की पूरी जानकारी है और न ही तकनीक की समझ है, हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता के ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। (गौर एवं व्यवधान) It is important for the sustenance of this country. And anybody

who opposes nuclear energy, opposes the energy sustenance of the country. I am saying that anybody who is opposing the production of nuclear energy is going against the national interests. (Noise & Interruption)

Mr. Speaker: It is very important. Please resume your seats.

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, ये इस बात का पहले भी कह चुके हैं। जब चौटाला साहब बोल रहे थे तब भी इन्होंने इस बात को कहा था। इस बात को बार-बार कहने का कोई औचित्य नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रणदीप जी, ये तो खिलाफ है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आप हमें कोट कर लो, हम तो खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष: हॉ, ठीक है।

श्री रामपाल माजरा: ठीक है सर, बात खत्म हुई। ये कहते हैं कि हमने पंचायतों का स अधिकारण कर दिया। स्पीकर सर, पहले पंचायतों के पास रिवैन्यू के राईट्स होते थे, सिविल राईट्स थे और ज्यूडिियल कम्पलैट्स भी पंचायतों के सुनाती थी लेकिन इन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से ये ग्रामीण विकास की बात करते हैं। स्पीकर सर, 2 अक्टूबर, 2008 को इन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना भुरु की और 607447 लोग इसके लिए चिन्हित किये गये। (गोर एवं व्यवधान)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि 3,80,000 लोगों को 100—100 गज के प्लॉट मिले हैं। स्पीकर सर, 2,27,447 लोगों को अभी प्लॉट मिलने बाकी है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल रजिस्ट्री करने से काम नहीं होगा, जब से जाकर नींव भरेंगे तब जाकर पता चलेगा कि प्लॉट मिला है या नहीं यह योजना फेल हुई, स्पीकर सर। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिान फौजी): अध्यक्ष महोदय, मैं माजरा जी से पूछना चाहता हूँ ये हरिजनों के हितेशी बने फिरते हैं। ये बता दें कि इन्होंने अपने 6 साल के राज में एक इंच जमीन भी हरिजनों को कभी दी हो। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, इनकी बात का जवाब दीजिए और अगर जरूरी नहीं समझते तो मत दीजिए (गोर एवं व्यवधान) इन्होंने पूछा है कि क्या आपकी सरकार ने एक इंच जमीन भी हरिजनों को दी थी। (गोर एवं व्यवधान) किसी हरिजन, बाल्मीकि, ब्राह्मण या बैकवर्ड को एक इंच भी जमीन दी है या नहीं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी सरकार ने भी नहीं दी। यह तो पंचायतों की जमीन थी ये तो सूखी वाह—वाही लेकर गये हैं। ग्राम पंचायतों की जमीन दी गई है। हमारे राज में भी 75—75 गज के प्लॉट दिये जाते थे। 75 गज के प्लॉट हमारी पंचायतों से दिये जाते थे। मैंने खुद रजिस्ट्री

करवाई हुई है, उस समय मैं सरपंच था। स्पीकर सर, मेरी बात सुनो। यह ग्राम पंचायतों की जमीन थी। मैं खुद सरपंच था, मुझे सब पता है। यह पुरानी परम्परा है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी, आप माजरा जी कि इस बात का जवाब दीजिए (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, यहांपर जितने भी विधायक विपक्ष में बैठे हुये हैं, उनसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं वे आत्मा पर हाथ रख कर कह दें कि मेरे हलके में एक भी प्लॉट आबंटित नहीं हुआ। कोई एक भी कह दो। आप कहलवा कर दिखा दो (गोर एवं व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा: सरकार ने नहीं दिये। आप एक प्लॉट ता बताईये जो सरकार ने दिया हो। कोई सिंगल प्लॉट भी सरकार ने दिया हो। यह तो ग्राम पंचायतों जमीन थी उसमें से ही दिये गये हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्दिरा आवास योजना की तहत साढ़े आठ लाख लोगों में से 17293 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसी प्रकार से हलियाली की बात करते हैं इन्होंने 11 हर्बल पार्क नियमों का उल्लंघन करके बना दिये और संजिव चतुर्वेदी की उस रिपोर्ट की जिसकी सी.बी.आई. ने कहा था कि इंडीपेंडेंट इन्कवायरी होनी

चाहिए, इन्होंने उसको ठण्डे बस्ते में रखा दिया। (तोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिान फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं माजरा साहब से एक पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने हांसी-बुटाना नहर बनाई थी और फिर दिया कि इसका लेवल गलत है। आज हमारी सरकार हर्बल पार्क बना रही है तो ये कहते हैं कि ठीक नहीं है। आज हमारी सरकार 100-100 गज के प्लांट बांट रही है तो ये कहते हैं कि यह गलत है। बिजलीघर बनाये जा रहे हैं, वह भी गलत है। इससे नुकसान हो जायेगा। किसान को बिजली की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please resume your seat.
(Interruptions)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। इन्होंने कहा कि हर्बल पार्क बनवाए तो उसमें क्या बुरी बात है? हमने जो हर्बल पार्क बनाये हैं उनाये हैं उनमें कोई अनियमितता नहीं है और वे बिल्कुल एज नॉर्म बने हैं और उसके लिए लोग हमारा धन्यवाद करते हैं। (तोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी: स्पीकर सर, जो गरीब लोगों को प्लांट देने की बात है, यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। मह मेरी आदत है कि जब आप सढौरा में जाते थे तो मैं आपका भाषण सुनने जाया करता था और जब कही इस इलाके में चौधरी

ओमप्रकाश चौटाला जी आते थे तो मैं उनका भी भाषण सुनने आया करता था चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ये बताएं कि ये उसका समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप किस बारे में कह रहे हैं? (गोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी: स्पीकर सर, गरीबों को जो प्लॉट दिये जा रहे हैं मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप समर्थन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो? (गोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी: सर, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने नंगला गांव में। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: सरकार ने खरीद कर दिए हो तो बताएं ये तो पंचायत पहले भी देती थी और अब भी दे रही है। फौजी साहब, आपने मुख्यमंत्री के आतिर्वाद से तीन सौ कीले जमीन बना ली है आम भी गरीब की बात कर है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी: चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने नंगला गांव में ये ब्यान दिया था.....। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Mr. Bhukri, please listen to me आप अपना प्र न दोहराईये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी: सर, ओमप्रका ा चौटाला जी का ये ब्यान था कि ये जो गरीबों को प्लाट दिए जा रहे हैं, ये कटने नहीं देने और जनता इसका विरोध करे। ये चौधरी ओमप्रका ा चौटाला का भाषण था मैं यही कहना चाहता था सर। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, राजपाल भूखड़ी जी ने यह बहुत वाजिब बात उठाई है, लोकदल के साथियों ने दलितों को प्लांट देने को विरोध किया था और हमें इस बात पर ऐतराज है। अगर किसी दलित के बेटे के पास जमीन है तो इसमें क्या पाप है, क्या दलित के बेटे को ये अधिकार नहीं कि वो जमीन का मालिक हो? (गोर एवं व्यवधान)

श्री नरे ा कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो दुलिया में पांच-पांच हरिजन दालितों के बच्चे को जिंदा जलवा दिया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए प्लीज। Please be seated.

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमति अनिता यादव): स्पीकर सर, वैसे तो यह हरिजनो का मूद्दा है। हरिजनों के लिए इन लोगों ने हमें ा ही मनमर्जा से काम लिया। जब हम लोग अपोजि ान की साईड बैठते हैं तो माजरा साहिब इधर से जहां

आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बोलते हैं, बोला करते थे। आपने नरे । जी को बोलने से रोका लेकिन मैं नरे । जी का समर्थन करती हूँ। मेरे बारे तो प्रेस में भी आता है कि मैं नरे । जी की बात को जरूर उठाती हूँ। जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर होते थे तो हमारे नठेड़ा गांव से इसकी सिर्फ पांच वोटें आई थी। एक बार जब नठेड़ा गांव का सरपंच इसके पास गया तो यह उनसे बोले कि नठेड़ा से कितनी वोट आई थी, वह बोला की पांच आई थी। इसके जवाब में यह बोले कि पर्ची तुम्हारे गांव से आवे पांच और तुम सोचो के मैं तुमने दे दूँ प्लॉट, यहां से भाग जाओं। स्पीकर सर, विपक्ष की बात तो वही बतायेगा जो उस टाइम यहां पर हाजिर हुआ करता था (विघ्न) अरोड़ा जी उस वक्त आप मंत्री थे और हम भी इस सदन के सदस्य थे लेकिन आप विपक्ष को बोलने नहीं दिया करते थे। आज जब नरे । जी या श्री रामकि ।न फौजी जी आपके बारे कोई बात कह रहे हैं। तो यह बिल्कुल सच कह रहे हैं। उस वक्त रामपाल माजरा जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो एक-एक घंटा सदन को गुमराह किया करते थे और आज भी इनकी यही मं ।। है कि सदन को गुमराह किया जाये। (विघ्न) बहादूर सिंह जी, आपसे मेरी कोई बात नहीं हो रही है, मेरा सदन में प्लॉयंट आफ आर्डर है। मैं चेयर की इजाजत पर खड़ी हुई हूँ। मैं आपकी परमि ।न से नहीं खड़ी हुई हूँ।

श्री अध्यक्ष: अनिता जी, आप बोलिये। मैंने आपको अलाऊ किया है।

श्रीमति अनिता यादव: स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मं ता सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की है और यह बात बिल्कुल सच है कि आज हर एक हरिजन भाई को प्लॉट अलॉट हो रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों में जमीन नहीं है, वहा जमीन को खरीदकर के उसे पर प्लॉट काटकर हरिजनों को दिये जा रहे हैं। क्या रामपाल माजरा जी बतायेगे कि वह हरिजनों के हित में है या विरोध में है? क्या उनको प्लॉट मिलने चाहिए या नहीं?

श्री अध्यक्ष: खटक जी, आप बोलिये।

श्री मति भाकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी ने अभी कहा कि प्लॉट के लिए पंचायती जमीन का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माजरा जी से पूछना चाहती हूँ कि जब इनका भासन था क्या उस उसम पंचायती जमीन नहीं थी? इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आज हमारे मुख्यमंत्री जी हरिजनों के हितैशी है तो यह उसका विरोध कर रहे है (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्रीमति गीता भुक्कल, मातनहैल): अध्यक्ष महोदय, 100 गज के लिए प्लॉट पर बहुत लंबी चर्चा इस सदन में

हो रही है। प्लॉट न केवल जाति के लोगों को बल्कि जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी हमारे अपोजि उन के लोग इस बात के खिलाफ है कि ये प्लॉट जो दिये जा रहे हैं ये पंचायत की जमीन से क्यों दिये जा रहे हैं।

श्री गीता भूककल मातनहैल: अध्यक्ष महोदय, यह प्लॉट बी.पी.एल. को भी दिये जा रहे हैं, बी.सी.ए. को भी दिये जा रहे हैं। वास्तव में यह लोग इस बात के खिलाफ है कि गरीबों की हितैशी यह सरकार गरीबों के लिए इस तरह के कार्य क्यों कर रही है। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, कोई भी कंट्रोवर्षियल बात न कहे, मैं सभी को बोलने के लिए समय दूंगा आप प्लॉट देने की स्कीम के खिलाफ है तो आप अपना स्टैंड दीजिए। इतनी पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए कि आप लोग यह कह कि हम इसके खिलाफ है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भी कंट्रोवर्षियल बात नहीं कहता। मैं प्लॉट देने की स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ। परन्तु ये असलियत में दे नहीं रहे हैं।

अभी से क्यों झलक आये आंसू, तेरे आंखों में नादान,

अभी तो छोड़ी है दासतां फिर भी तूने मेरे दोस्त।

हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सोसायटी बनाई गई। नौजवानों को कहा गया कि हम उन्हें रोजगार के लिए विदे 1 में भेजेगे। स्पीकर सर, अनपढ़, गरीब व मजदूर टाईप के लोग विदे 1 में जाते है तथा दलाल उनसे 10-10, 12-12 लाख रूपये ठग लेते है। हरियाणा सरकार ने इमिग्रे 1न एक्ट 1983 भी बनाया परन्तु उस पर इंप्लीमेंटे 1न कुछ नही हुआ फलतः नौजवानों को ठगा जा रहा है। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सोसायटी पर लाखों रूपये किये जाने के बाद भी वह कारगर सिद्ध नही हो सकी।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for five minutes?

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: OK the time oif the sitting of the House is extended for five minuts.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, सदन का समय कम से कम एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

Mr. Speaker: You please conclude in five munutes, आप पांच मिनट में पूरी बात कहे।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं तो केवल जनता की बात कहूंगा। हरियाणा प्रदेश की 25 प्रतिशत जनता डेरों और ढाणियों में रहती लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 10 से 11 फेमिलीज को डेरे और ढाणियों में बिजली देने की योजना बनाई है कैंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसका 6833 लोगों के फायदा उठाया है। सर, यह भी कमाल की बात है कि जहां लाखों डेरे और ढाणियों हैं फिर भी इसे वहां कि जनता से पूछकर भी नहीं बनाया गया। इन्होंने अपनी मर्जी से और यह सोचकर कि इसके लिए 50-50 परसेंट के हिसाब से खर्चा देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने सारे डेरी और ढाणियों को बिजली नहीं दी। इस वजह से लोगों आज अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री मान् जी आज वे आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नियम में रिलैक्सेशन दे दीजिए। इन्होंने कहा था कि हमने तो बिल माफ कर दिये, 2008,2009 में 2899 करोड़ रुपया बिलों बकाया था और 2009-10 में 3142 करोड़ रुपया बिलों का बकाया था, वर्ष 2010-11 में 3842 करोड़ बकाया था और ये बकाया दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 750 करोड़ रुपये की टूयून पर प्रतिवर्ष के हिसाब से इसमें बढ़ौतरी हो रही है। इस बढ़ौतरी से ऐसा लगता है कि इनमें या तो वसूल करने की इच्छा भावित नहीं है। या बिलों में कोई हेराफेरी है जो जनता देना नहीं चाहती या ये चाहते होंगे, कहते भी होंगे, या ये माफ करना चाहते होंगे, इनकी दोबारा से कोई ऐसी नीति होगी?

कैप्टन अयज सिंह यादव: माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: बिजली के दोनों निगम उत्तरी और दक्षिणी में 6671 करोड़ रुपये के घाटे में है। आज इनके हालात ये हैं कि इनको कोई लोन देने वाला नहीं रहा।

श्री नरे । कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने अपने चुनाव घोषण पत्र में कहा था कि इनके राज में मीटर होगा न रीडर होगा (गोर एवं व्यवधान) फ्री बिजली देंगे। जब ये सत्ता में आए तो इनको जब इनके वादे की किसानों ने याद दिलाई तो कंडेला में इन्होंने निहत्थे किसानों की हत्या करा दी जाब वे किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं। छाज तो बोले छलनी भी बोले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, बिजली के दोनों निगमों पर आज 15568 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं और कोई भी इनको लोन देने को तैयार नहीं है। सवा 13 परसेंट के रेट आफ इंटरस्ट पर लोन ले रहे हैं। जहां तक कृषि क्षेत्र के नलकूपों की बात है वहां 3.96 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी गई और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम 4.7 घंटे की सब्सिडी मांग रहा है औय यू.एच.बी.वी.एन. ने 3.49 घंटे प्रतिदिन के हिसाब

से बिजली दी है और 7.08 घंटे के हिसाब से सब्सिडी मांग रहा है। इस प्रकार से..... (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये फ़ैक्चुअली इनकरैक्ट बात है कि नलकूपों को 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी जाती है। पॉवर मिनिस्टर साहब मौजूद है। इस बारे में पॉवर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लीयर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। जिसके फलस्वरूप चाहे बाहर से बिजली खरीद कर दी लेकिन हरियाणा के किसानों के ट्यूबवैल को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे हरियाणा सरकार द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है..... (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, ये मैंने नहीं कहा है एच.आर.ई.सी. ने कहा है। इसके अलावा 2009-10 में इन्होंने बड़े ढोल पीटे थे कि एच.वी.डी. एस. बनेगा उससे सैग्रेगेटिड ऑफ पॉवर हो जायेगी। इस पर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने तो 1497 करोड़ रुपये भी खर्च दिये कि लाइन लैसिज कम हो जाएंगे लेकिन लाइन लौसिज आपके सामने है। सर, 2011-12 में 23 प्रतिशत है, टी एण्ड डी. लौसिज.....(गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इनके समय में तो लाइन लौसिज 41 परसेंट थे अब घटकर 24 परसेंट पर आ गए हैं। इनका यह कहना कि नलकूपों के लिए तीन घंटे बिजली दे रहे हैं, ये हाउस को गुमराह

कर रहे है। तीन घंटे नही बल्कि 8 से 10 घंटे प्रतिदिन बिजली ट्यूबवैल को दे रहे है और 20-22 घंटे बिजली भाहरी क्षेत्र में दे रहे है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, झज्जर में 35 प्रति गत लाइन लौसिज है, जींद में 28 प्रति गत लाइन लौसिज है। ये कैग की रिपोर्ट है। ये मैं नही कह रहा हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। आपको सिर्फ एक मिनट का समय वाइंड अप करने के लिए और दिया जाता है

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मार्च 2011 से 33 फीडर टी. एण्ड डी.लौसिस और लाइन लोसिस 25 और 30 परसेंट थी। (गोर एवं व्यवधान) मार्च 2011 में विभिन्न परिचालन मण्डलों में 11 के.वी.ए. के 2737 फीडर थे और उनमें 25 प्रति गत से अधिक लाइन लौसिज थे। (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: इनके समय मैं कितने सब स्टे गन बने थे और कितने फीडर्स कितने लाइन लौस में थे?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, 483 फीडर्स में 25 परसेंट लाइन लौसिज थे, 267 फीडरों में 50 प्रति गत से अधिक लाइन लौसिज थे। (गोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्रीमति गीता भुक्कल, मातनहैल): स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इनके हल्के में 132 के.वी. के पावर हाउस का अभि सी. एम. साहब उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो कि कलायात में बना है, इसी तरह से एक संगण में बना है। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow, the 2nd March 2012.

18.35 hrs.

(The Sabha then*adjourned till 2.00P.M. on Friday, the 2nd March, 2012.)